झारखंड बजट

* ओड़िशा संस्करण

कलम कलम बढ़ाये जा

आजाद सिपाही

₹1,28,900 करोड़ का बजट

रांची 28 फरवरी, 2024, बुधवार, वर्ष 09, अंक 129, फाल्गुन, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी, संवत 2080, पृष्ठ : 16, मूल्य : ₹3.00

सत्यमेव जयते

झारखण्ड सरकार GOVERNMENT OF JHARKHAND

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा
की पावन धरती, झारखण्ड पर

श्रीमती द्रौपदी मुर्मु
भारत की माननीय राष्ट्रपति

का हार्दिक अभिनंदन और

जोहार

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

P.R. 320586 (IPRD) 23-24

झारखंड बजट

कलम कलम बढ़ाये जा

आजाद सिपाही

₹1,28,900 करोड़ का बजट

रांची 28 फरवरी, 2024, बुधवार, वर्ष 09, अंक 129, फाल्गुन, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी, संवत 2080, पृष्ठ : 16, मूल्य : ₹3.00

झारखंड बजट

कलम कलम बढ़ाये जा

आजाद सिपाही

₹1,28,900 करोड़ का बजट

रांची 28 फरवरी, 2024, बुधवार, वर्ष 09, अंक 129, फाल्गुन, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी, संवत 2080, पृष्ठ : 16, मूल्य : ₹3.00

चंपाई सरकार के बजट में किसानों की बल्ले-बल्ले

आजाद सिपाही संवाददाता

- 1.28 लाख करोड़ का बजट पेश
- किसानों का दो लाख का कर्ज होगा माफ
- गरीबों के आंसू पोछने की योजनाएं
- राज्य के नौनिहालों पर विशेष फोकस
- विकास को मिलेगी गति
- 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

रांची। चंपाई सरकार ने पहली बार मंगलवार को बजट पेश किया। बजट में किसानों को बड़ी राहत दी गयी है। गरीबों का आंसू पोछने के लिए कई योजनाओं का प्रवाधान किया गया है, तो अलग से बाल बजट बना कर राज्य के नौनिहालों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट से विकास को गति मिलेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। बजट में किसानों की ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख कर दिया है। इस योजना में एनपीए खाता धारक किसानों को भी शामिल करने का ऐलान किया है। रामेश्वर उरांव लगातार पांचवीं बार विधानसभा में बजट पेश किया। इस बार के बजट में पिछले साल से 3.7 फीसदी का इजाफा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष का बजट एक लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपये था। चुनावी साल होने के कारण इस बार योजनाओं पर सरकार का फोकस है। आर्थिक विकास दर 7.7 फीसदी रहने का अनुमान है।

सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राजस्व आय के 53 हजार 500 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2023-24 से 2030 के बीच हर साल 14.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके हासिल किया जा सकता है। चंपाई सरकार ने झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन (10 लाख करोड़ रुपये) की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

राजस्व खर्च में 8.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी

पिछले वित्तीय वर्ष से 3.7 प्रतिशत अधिक का बजट है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय के लिए 91 हजार 832 करोड़ रखे गये जो पिछले साल से 8.5 प्रतिशत अधिक है। राजस्व आय 53 हजार 500 करोड़ रहने का अनुमान है, जिसमें कर राजस्व से 34 हजार 200 करोड़ गैर राजस्व से 19 हजार 301 करोड़ केंद्रीय सहायता से 16 हजार 961 करोड़ केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 40 हजार 338 करोड़ रुपये लोक ऋण में 18 हजार करोड़ रुपये विभाग और अग्रिम वसूली में 100 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। राजकोषीय घाटा 24-25 में 9 हजार 500 करोड़ रुपये का अनुमान है।

हर गरीब को मिलेगा आवास

सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.50 लाख, वर्ष 2025-26 में 2.50 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने का निर्णय किया था। बड़ी संख्या में आये आवेदनों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक इसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष 4.5 लाख परिवार कर दिया गया है। इससे लगभग 20 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। योजना के लिए सरकार ने 4,831 करोड़ 93 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया है। सर्वजन पेंशन योजना में उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गयी है। आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने बजट में कुल 3,107 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया

स्कूली शिक्षा में 325 प्रखंडस्तरीय लीडर स्कूल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 4036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। डिप्लोमा स्तर पर पढ़ाई करने वाली छात्राओं को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा स्तर पर 15 हजार प्रति वर्ष और डिग्री स्तर के लिए 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जायेगी। राज्य सरकार मेसर्स कॉमन सर्विस सेंटर पीवी के साथ साझेदारी कर एक राज्यव्यापी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करेगी। बीआइटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य सरकार राज्य में 19 नये महाविद्यालय, जिसमें 15 डिग्री महाविद्यालय और 4 महिला महाविद्यालय की स्थापना करेगी। राज्य सरकार आगामी वर्षों में राजधानी रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी। छात्रों के लिए नि:शुल्क आवासन की सुविधा के लिए बहुमंजिला मॉडल छात्रावास का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जायेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया है ध्यान

वर्ष 2024-25 में पथ घनत्व बढ़ाने एवं कोर रूट नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नये पथों को शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर पथ और 200 पुल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना एवं पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना के कार्यान्वयन करवाया जायेगा। इसके अलावा पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना के लिए 456 करोड़ 63 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। महिला एवं बाल विकास के तहत 2500 आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जायेगा।

बाल बजट पेश, 8,866.69 करोड़ खर्च करेगी सरकार

80 योजनाओं के दायरे में झारखंड के नौनिहाल

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। चंपाई सरकार ने बाल बजट पेश किया है। 80 योजनाओं के दायरे में झारखंड के नौनिहालों को रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है। बाल बजट तैयार करने का उद्देश्य राज्य में बच्चों के समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है। राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने बाली योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 216 योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 80 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 8,866.69 करोड़ की राशि उपबंधित की गयी है। यह राशि आउटकम बजट के अंतर्गत लिए गये योजनाओं के कुल उपबंधित राशि का लगभग 18 प्रतिशत है। राज्य के कुल योजना आकार का लगभग 11 प्रतिशत है। इसमें बच्चों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है।

बाल बजट बच्चों की जरूरतों और कल्याण के लिए सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों को आवंटित करने और व्यय की योजना बनाने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सरकारी व्यय के प्रभाव का मूल्यांकन करना भी है। इस बजट के माध्यम से बच्चों के विकास से संबंधित सभी योजनाओं की सही मॉनिटरिंग हो सकेगी। बच्चों के विकास पर कितना काम हुआए इसकी सही-सही जानकारी मिल सकेगी। इस बजट के माध्यम से ही बच्चों के विकास को सुनिश्चित करने कते लिए स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण और शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के लिए संसाधनों को आवंटित किया जाता है।

झारखंड बजट

कलम कलम बढ़ाये जा

आजाद सिपाही

₹1,28,900 करोड़ का बजट

रांची 28 फरवरी, 2024, बुधवार, वर्ष 09, अंक 129, फाल्गुन, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी, संवत 2080, पृष्ठ : 16, मूल्य : ₹3.00

झारखंड बजट

कलम कलम बढ़ाये जा

आजाद सिपाही

₹1,28,900 करोड़ का बजट

रांची 28 फरवरी, 2024, बुधवार, वर्ष 09, अंक 129, फाल्गुन, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी, संवत 2080, पृष्ठ : 16, मूल्य : ₹3.00

बजट की प्रमुख घोषणाएं

1. दो लाख रुपये तक का कृषि कर्ज माफ
2. अबुआ आवास योजना के तहत 3.50 लाख घर बनाने की योजना
3. 15,00 रुपये का मातृ किट देगी सरकार
4. खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ा कर 25 लाख करने का प्रस्ताव
5. मुखिया का मानदेय बढ़ाया
6. 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी
7. कृषि क्षेत्र के लिए 4606 करोड़ का बजट
8. पेंशन मद में 8021 करोड़ रुपये का बजट
9. एससी-एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 3523.55 करोड़
10. महिलाओं और बच्चियों के कल्याण के लिए बजट
11. 21 जिलों में चलंत ग्राम क्लीनिक का संचालन किया जायेगा।
12. रिम्स का सुदृढ़ीकरण एवं रिनपास के कैंपस में एक मेडिको सिटी की स्थापना
13. राजधानी रांची में एक और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी।
14. अब झारखंड के गरीब परिवारों को चावल-दाल के साथ सोयाबीन बड़ी भी मिलेगा.
15. पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना और पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गयी है.
16. पलामू पाइप लाइन सिंचाई योजना के लिए 4 सौ 56 करोड़ 63 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं.
17. राज्य में 2 हजार 5 सौ आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण होना है।

यह बजट आत्मनिर्भर झारखंड की परिकल्पना को पूरा करेगा: सीएम

गरीब कल्याण, सर्वसमावेशी तथा जन आकांक्षा के अनुरूप है बजट 2024-25

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि यह जन आकांक्षाओं का बजट है। राज्य सरकार ने जनता के विश्वास एवं उम्मीद के अनुरूप बजट बनाने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने आज 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। हमारी सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देने का कार्य किया है। बजट में किसानों की ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इस ऋण माफी योजना के अंतर्गत एनपीए हुए खाता धारक किसानों को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। अबुआ आवास के तहत 20 लाख पात्र गरीब परिवारों को तीन कमरे का पक्का मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कई मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जैसे पटमदा, पीरटाड़ और पलामू इत्यादि कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में पेश बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना में उम्र सीमा बदलाव किये गये हैं। एसटी-एससी और महिला के लिए उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गयी है। 2500 नये आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण भी किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आत्मनिर्भर झारखंड की परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में निवेशकों को पूरी सुविधाएं एवं बेहतर माहौल प्रदान की जा रही है, ताकि औद्योगिक प्रतिष्ठानों का अधिष्ठापन सुगमता पूर्वक की जा सके।

शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2024-25 में 19 नये महाविद्यालय स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 महिला महाविद्यालय का निर्माण किये जायेंगे। रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी। रिनपास की जमीन पर एक मेडिको सिटी की स्थापना भी की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में 90 हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन कार्ड में 5 लाख की वृद्धि की गयी है। अब कुल 25 लाख ग्रीन कार्ड होंगे। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को आप 100 यूनिट की जगह 125 मिनट नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करायी जायेगी। चंपाई ने कहा कि शिक्षा, खेल, कौशल विकास सहित कई सेक्टर में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे राज्य के युवा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।

चंपाई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के इस बजट में कोई नयी चीज नहीं मिली। बेरोजगारी भत्ता देने की बात इस सरकार ने बड़ी जोर-शोर से किया था, उसका क्या हुआ? यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। जनता से तमाम लोकलुभावन वादे करती है और बाद में जब सदन में बजट आता है, तो उन वादों से दूरी बना लेती है।

-बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

दिशाहीन व निराशाजनक झारखंड बजट है। ना नीति, ना नियत और ना नेतृत्व क्षमता। यह निराशाजनक बजट झारखंड को पीछे ले जाने वाला है। खुद सत्ता पक्ष उदासीन है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यह झामुमो-कांग्रेस-राज्य सरकार का आखिरी बजट साबित होगा और विदाई तय है।

- अमर कुमार बाउरी, नेता प्रतिपक्ष

प्रेस कांफ्रेंस

20 लाख परिवारों को अबुआ आवास: डॉ रामेश्वर

रांची (आजाद सिपाही)। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के सभागार में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बजट में कई नयी घोषणाएं शामिल हैं। इनकी संख्या दो दर्जन से अधिक है। वित्तीय वर्ष 24-25 में ऋण माफी की सीमा 50 हजार रुपये से बढाकर 2 लाख रुपये किया जायेगा। एनपीए खाताधारक किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 27-28 की अवधि तक 20 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जायेगा। रामेश्वर उरांव ने बताया कि सरकार 2025 तक भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में से 2500 भवनों का निर्माण करायेगी। सत्र 2024-25 से सरकार द्वारा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन किये जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा 4036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले दो सालों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहली बार राज्य के 259 स्कूलों में मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रक्रिया प्रायोगिक तौर पर आरंभ की गयी थी। अब 24-25 में इसे राज्य के 7 जिलों के 1000 प्राइमरी स्कूल में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में पथ घनत्व बढ़ाने एवं रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नये रोड को शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका विकास कम से कम इंटरमीडिएट लेन के रूप में किया जायेगाए इसके अंतर्गत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एवं इंपॉर्टेंट कॉरिडोर का भी निर्माण होगा। रांची शहर के लिए इनर रिंग रोड एवं फीडर रोड के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। डॉ रामेश्वर उरांव ने जानकारी दी कि राज्य में कुल 19 नये कॉलेज खोले जायेंगे। इनमें 15 डिग्री कॉलेज और 4 महिला महाविद्यालय होंगे। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को वित्तीय मदद दी जायेगी। डिप्लोमा स्तर पर 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष और डिग्री स्तर के लिए 30 हजार रुपये प्रति वर्ष दिये जायेंगे। वर्ष 24-25 में इसे लागू किया जायेगा।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास : बजट-1053.27 करोड़

प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता

रांची (आजाद सिपाही)। वर्ष 2023-24 में क्रियान्वित मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिये जाने के लक्ष्य 1,40,000 के विरुद्ध लगभग 75,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे युवक-युवतियों, जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका है, को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में डीबीटी के माध्यम से 2.45 करोड़ का प्रोत्साहन भत्ता निर्गत किया गया है।

अनुसूचित जनजाति-जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण : बजट-1371.39 करोड़

बनेगा बहुमंजिला मॉडल छात्रावास अखड़ा गांव को पारंपरिक वाद्य यंत्र

छात्रावासों का निर्माण योजनांतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण को लेकर अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नि:शुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावासों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जायेगा। जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से युनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दन आयरलैंड में स्थित चयनित विश्वविद्यालयों / संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स/एमफिल डिग्री ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के वर्ग 8

में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में शैक्षणिक निरंतरता को प्रोत्साहित करने और ड्रॉप आउट रेट रोकने के उद्देश्य से छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरण किया जायेगा। अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए धार्मिक स्थल, श्मशान और मसना की घेराबंदी का कार्य किया जायेगा। जनजातीय संस्कृति एवं उनकी समृद्ध विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से जनजातीय गांवों में अखड़ा का निर्माण और उनके पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति का प्रस्ताव है।

योजना एवं विकास : बजट-415.43 करोड़

सरकार ने चौथी बार पेश किया आउटकम बजट

रांची। झारखंड देश का पहला राज्य है, जिसने न केवल आउटकम बजट के सूत्रण की प्रक्रिया में सतत विकास लक्ष्यों को केंद्र में रखा है। ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से वित्तीय वर्षवार आउटकम बजट के विरुद्ध प्रगति प्रतिवेदन को भी सदन के पटल पर प्रस्तुत करता रहा है। योजना एवं विकास विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से आउटकम बजट का सूत्रण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 13 विभागों का आउटकम बजट इस सदन के पटल पर लगातार चौथी बार प्रस्तुत किया जा रहा है।

बजट भाषण का बहिष्कार कर विपक्ष का वॉक आउट

रांची (आजाद सिपाही)। सदन में वित्त मंत्री के बजट पढ़ने के दौरान विपक्ष ने बजट भाषण का बहिष्कार किया और सदन से निकल गये। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि इनमें बजट भाषण सुनने की ताकत ही नहीं है। ये गरीबों को माड़ भात खिलाते थे। हेमंत सरकार ने चावल के साथ दाल भी खिलायी। अब चंपई सरकार दाल भात के साथ सब्जी भी खिलायेगी।

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य : बजट-336.16 करोड़

नेतरहाट बनेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट

पर्यटन उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी काफी उपयोगी है

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। बजट में कहा गया है कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी काफी उपयोगी है। इसलिए राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए अलग से एक पर्यटन नीति का गठन किया है। नेतरहाट को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी का गठन किया गया है। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद आवार्ड प्राप्त खिलाडी, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाडी कॉमन वेल्थ खेल, एशियन गेम के पदक विजेता खिलाड़ी जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं है, ऐसे झारखंड राज्य के खिलाड़ियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए पेंशन योजना प्रारंभ की गयी है। खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिता के लिए उचित मंच प्रदान करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन का प्रस्ताव है, जिसमें मुख्यतः दो प्रतियोगिताएं शामिल हैं। खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए सिदो-कान्हू युवा क्लब स्थापित किया गया है। सिदो कान्हू युवा खेल क्लब गठन और संचालन मार्गदर्शिका की अधिसूचना के बाद नवंबर, 2023 तक ग्राम स्तर पर कुल 27,433 और प्रखंड स्तर पर 130 सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब का गठन किया जा चुका है।

बजट 2024-25: चुनावी नहीं, जनहित बजट

बीते वर्ष के मुकाबले थोड़ा बढ़ा, लेकिन दिख रहा बड़ा विकास

प्रशांत झा

रांची। गठबंधन सरकार (झामुमो, कांग्रेस और राजद) की तरफ से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को विधानसभा में पांचवीं बार बजट पेश किया। अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होना है और इसके बाद इस वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे। इसके बावजूद बजट को लोक लुभावन या चुनावी बजट नहीं कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में यह पहला बजट है। बीते वर्ष के मुकाबले बजट को थोड़ा ही बढ़ाया गया है, लेकिन विकास का बड़ा प्रावधान दिख रहा। योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, तो किसान,

महिला, बच्चे, युवा, आदिवासी हर वर्ग को लाभ मिलता दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो प्रवाधान किये गये हैं, उससे रांची राजधानी से लेकर दूर देहात तक की तस्वीर बदलनी तय है।

पेट भरने के लिए भोजन की बात हो, या गरीबों के सिर पर छत की व्यवस्था। किसानों के ऋण से मुक्ति की बात हो, या गरीबों को पेंशन दे कर राहत देने का प्रयास। बजट में इस तरह के सभी प्रावधान दिख रहे हैं। लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मुहैया कराने के लिए बजट में राशि है, तो राशनकार्ड धारियों को सोयाबीन मुहैया कराने का ध्यान रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल से लेकर कॉलेज तक की चर्चा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में रांची के रिम्स में सुधार की बात है, तो अन्य क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, खेल, स्वास्थ्य समेत शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें विकास के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार ने अच्छा वित्तीय प्रबंधन दिखाया है। सरकार लोगों तक सुविधा मुहैया कराने के लिए राजस्व बढ़ोत्तरी पर ध्यान दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 53 हजार पांच सौ करोड़ 43 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा का अनुमान 2.02 है, जो एफआरबीएम की निर्धारित सीमा तीन फीसदी से कम है। बजट में बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। ये सारी बातें इस बात की पुष्टि करती हैं कि बजट आकार भले ही कम बढ़ा हो, लेकिन जनहित के लिए बहुत ही अच्छा है।

अष्टम् पुण्यतिथि

स्व० कौशल किशोर सिंह
(15.01.1940 - 28.02.2016)

आपकी स्मृतियां सदैव हम सभी के मानस पटल पर अंकित रहेगी.
अष्टम् पुण्यतिथि पर हम सभी की ओर से आपको हार्दिक श्रद्धांजलि।

आपकी यादों में :

अमरेन्द्र कुमार (पुत्र) – रूबी देवी
इन्दु देवी – विजय कुमार
रमेन्द्र कुमार – अनिता देवी
शशांकराज, सृष्टिराज, सुर्याशराज, सारांशराज (दर्श)
संस्था : लिटिल विंग्स स्कूल, बुटी मोड़, राँची।
संस्था : आर एस ग्रुप ऑफ कंपनी,
माँ शांति देवी फाउंडेशन।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की नयी घोषणाएं

- आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण माफी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये करने तथा एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।
- सरकार की महत्त्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अनाच्छादित राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए की गई है, जिसमें लाभार्थियों को पाँच किस्त में 2,00,000 (दो लाख) रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 लाख 50 हजार एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख 50 हजार परिवारों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया गया था, परन्तु आवेदनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार अब इस योजना के आकार को बड़ा करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख 50 हजार परिवारों, यानि लगभग 20 लाख परिवारों को इसका लाभ दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,831.83 करोड़) रुपये का बजट प्रस्तावित है।
- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना एवं पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा। पीरटांड प्रखंड में बराकर नदी पर वीयर का निर्माण कर भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से जल उद्वह कर पीरटांड प्रखंड में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार पूर्वी सिंहभूम के पटमदा आदि क्षेत्रों में भूमिगत पाईप लाईन से जल उद्वह सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
- पलामू जिलांतर्गत भूमिगत पाईपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों / जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाईपलाइन सिंचाई योजना हेतु लगभग 456.63 करोड़ (4 सौ 56 करोड़ 63 लाख) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना से पलामू जिलांतर्गत चैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, विश्रामपुर, छत्तरपुर, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज आदि क्षेत्र के कृषक मुख्य रुप से लाभांवित होंगे। प्रस्तावित पाईपलाइन के दोनों तरफ 2 किमी के दायरे में अवस्थित जलाशयों में आवश्यकतानुसार जल भरा जा सकेगा।
- निर्वाचित जन प्रतिनिधियों यथा जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, मुखिया, उपमुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय में बारह वर्षों के बाद पहली बार वृद्धि की गयी है।
- मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किये गये हैं, किन्तु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजाति के व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, एचआइवी/एड्स से ग्रसित व्यक्तियों एवं ट्रान्सजेंडरो / तृतीय लिंग व्यक्तियों के साथ-साथ 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आर्थिक रुप से कमजोर सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति/जाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 3,107.40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत लगभग 23,50,000 (23 लाख 50 हजार) लाभार्थी आच्छादित होंगे।
- सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन हो, इसे राज्य सरकार सुनिश्चित करा रही है। इसी क्रम में सरकार वर्ष 2025 तक भवनहीन केन्द्रों में से 2,500 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण करायेगी। वर्तमान में 38,432 केंद्र संचालित है। कुल 7,687 आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए टेबुल, कुर्सी के मद में कुल 280.17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा सभी 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रारंभ करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही 4,036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले 02 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रुप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहली बार राज्य के 259 विद्यालयों में मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रक्रिया प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ की गयी थी। इसके सकारात्मक फलाफल को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसे राज्य के 07 जिलों के एक हजार प्रारंभिक विद्यालयों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृति योजना की पहल की है, जिसमें डिप्लोमा स्तर पर 15,000 रुपये प्रतिवर्ष एवं डिग्री स्तर के लिए 30,000 (तीस हजार) रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू किया जायेगा।
- राज्य सरकार के द्वारा मेसर्स कॉमन सर्विस सेंटर एसपीवी के साथ साझेदारी में विद्यार्थियों की ऑनलाइन शिक्षण को सक्षम बनाने के लिए एक राज्य-व्यापी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) विकसित किया जा रहा है। एलएमएस में छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं, मूल्यांकन, प्रॉक्टरिंग और ग्रेडिंग की सुविधा होगी। यह छात्रों के ज्ञान में वृद्धि के लिए यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन भी संचालित करेगा।
- विद्यार्थियों को बाजार प्रासंगिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों यथा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआर-वीआर आदि और बाजार मांग वाले सेवा यथा खुदरा, सत्कार, वित्तीय सेवाओं आदि पर एसपीवी (स्पेशल परपस व्हीकल) के माध्यम से बीआइटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है।
- राज्य सरकार ने राज्य में उन्नीस नये महाविद्यालयों (15 डिग्री महाविद्यालय तथा 04 महिला महाविद्यालय) स्थापित करने का निर्णय लिया है। 04 नये महिला महाविद्यालय बनाने से राज्य में प्रत्येक जिला सरकारी महिला महाविद्यालय से अच्छादित हो जायेगा।

बजट भाषण की कविता के जरिये गिनायी उपलब्धियां

सरकार आपके द्वार खुशियां लायी...

वित्त मंत्री ने पढ़ा 41 पेज का बजट भाषण

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। 2024-25 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने सरकार की चार साल की उपलब्धियों का बखान किया। कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार विकास के रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की चुनौती को स्वीकार किया। अथक प्रयास से झारखंड के वित्तीय प्रबंधन को उत्कृष्ट बनाने में सफलता हासिल की है। हम जनआकांक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसके बाद उन्होंने एक कविता पढ़ी, जो इस प्रकार है -

हर विघ्न को हमने पार किया,
कांटों का झुरमुट साफ किया,
जब घटा कोरोना की छाई,
सुखाड़ उदासी भर लाई।
जब लगा सिमटने केंद्रीय अनुदान,
वित्तीय प्रबंधन बना समाधान।
हुआ अग्रसर तब अबुआ राज,
कुशल, बेहतर कर काम-काज।
विकास की गाड़ी घर-घर आयी,
सरकार आपके द्वार खुशियां लायी।

वित्त मंत्री ने 41 पन्ने के अपने बजट भाषण के 8वें और 9वें पन्ने में जाकर इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। तीसरे पन्ने की कविता का विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 के बीच झारखंड की मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी 9.1 फीसदी की औसत वार्षिक दर से बढ़ी। इस दौरान वर्ष 2015-16 में कमजोर मानसून, वर्ष 2019-20 में आर्थिक मंदी और वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी की वजह से विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन 11 वर्षों में से 5 वर्ष आर्थिक विकास दर 14.2 प्रतिशत से अधिक रही।

भाषण का अंत कविता से : उन्होंने बजट भाषण का अंत भी एक कविता से ही किया। कहा कि काल की शाश्वतता में आज का यह कालखंड हमारे आने वाले भविष्य की नींव है। इसलिए आज हमने सदन के पटल पर केवल आय-व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा है, बल्कि यह समस्त झारखंडवासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मूक अभिव्यक्ति को वाणी भी दी है। डॉ उरांव ने कहा कि कठिनाइयां और विषम परिस्थितियां मंजिल के लिए बाधा नहीं, बल्कि वे और ज्यादा दृढ़ प्रयास करने को प्रेरित और संकल्पित हैं। चंद्रोदय से पूरनमासी के सफर से आगे हमारी गठबंधन सरकार झारखंड के लोगों को विश्वास दिलाना चाहती है कि हम प्रगति और खुशहाली के उस रास्ते पर अग्रसर हैं, जहां विकास का सूरज कभी अस्त नहीं होता। इसके बाद उन्होंने एक कविता पढ़ी।

मैं दृष्टि श्रेष्ठ प्रबंधन का
जल, जमीन और जंगल का
हर हाथ को मिले जब रोजगार
अबुआ आवास की छत-दीवार।
कर संपदा का सही इस्तेमाल
बने झारखंड समृद्ध-खुशहाल
गूंजे स्वर मीठे हर कौम से
खुशियां बरसेंगी तब व्योम से।
लें प्रण, सब मिलकर करें प्रयास
हर सोमरा-मंगरा का हो विकास।

टैक्स से सरकार ने कमाये 34,200 करोड़

वित्त मंत्री ने झारखंड सरकार की कमाई के स्रोतों के बारे में भी विधानसभा को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार को टैक्स से 34,200 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जबकि 19,301 करोड़ रुपये नॉन टैक्स से मिले। केंद्रीय सहायता के रूप में उन्हें 16,961 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। सेंट्रल टैक्सेज में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में झारखंड सरकार को 40,338 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने कहा है कि लोक ऋण से 18 हजार करोड़ रुपये और उधार एवं अग्रिम वसूली से 100 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा 9500 करोड़ रहने का अनुमान

डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 9500 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो अनुमानित जीएसडीपी का 2.02 फीसदी है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक विकास दर 9.8 फीसदी रहने का अनुमान है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक झारखंड को 10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। वर्ष 2022-23 में झारखंड का जीएसडीपी 4 ट्रिलियन रहा।

हमारी सरकार ने किया बेहतर वित्त प्रबंधन: डॉ रामेश्वर उरांव

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया है। यही वजह है कि कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन की वजह से जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं, उससे हम उबर चुके हैं। आज हमारी सरकार जनहित में योजनाएं बना रही हैं। उन्हें लागू भी कर रही है। डॉ उरांव ने कहा कि हमारा यह बजट गरीबों पर केंद्रित बजट है। आम लोगों पर केंद्रित बजट है। इसमें आम लोगों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा गया है।

झारखंड में विकास ने पकड़ी रफ्तार : डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण से स्पष्ट हो गया कि झारखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आयी है। विकास की रफ्तार तेज हुई है। आम लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय 91 हजार रुपये से अधिक हो चुकी है। अगले वर्ष इसके एक लाख रुपये से अधिक हो जाने का अनुमान है।

आर्थिक विकास दर 7.7 फीसदी रहने का अनुमान : आर्थिक विकास दर 7.7 फीसदी रहने का अनुमान है। भविष्य में किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए सिंकिंग फंड में 1600 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसका इस्तेमाल ऋण भुगतान के लिए ही किया जायेगा। 2024-25 में 500 करोड़ से अधिक निवेश करने का लक्ष्य है।

सुनने, सीखने की क्षमता नहीं: डॉ रामेश्वर

डॉ रामेश्वर उरांव ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनमें सुनने और सीखने की क्षमता नहीं है। ये लोग 20 साल तक बच्चों को मांड़ भात खिला रहे थे। हमारी सरकार ने दाल-भात खिलाना शुरू किया। अब चंपाई सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार बच्चों को दाल-भात के साथ सब्जी भी खिलायेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इनमें सुनने की क्षमता नहीं है। सीखने की क्षमता नहीं है। जब सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो बेहतर कैसे करेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे।

कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र: बजट- 4,606.57 करोड़

ऋण माफी से लेकर खेती-किसानी में बड़ी राहत

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र में चंपाई सरकार ने 4606.57 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। इससे ऋण माफी से लेकर खेती-किसानी में बड़ी राहत मिलेगी। सूखा से राहत दिलाना और किसानों के आय में वृद्धि सरकर का लक्ष्य है। कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4.62 लाख से अधिक किसानों के बीच 1,858 करोड़ की ऋण माफी की गयी। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण माफी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख करने का लक्ष्य है। बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण, फसल विस्तार योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागू कर लगभग 2 लाख 10 हजार किसानों को आच्छादित करते हुए अनुदान पर बीज वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजनांतर्गत 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर पंप सेंट रीपर ट्रॉसप्लांटर आदि का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। खेती में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एकीकृत जल प्रबंधन के माध्यम से आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए कृषकों के निजी भूमि पर शत-प्रतिशत सरकारी अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 10 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। किसानों को कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में क्षति होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। वनोपज के व्यापार से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर अनुसूचित जनजाति, ग्रामीणों को उनके द्वारा उत्पादित-संग्रहित उत्पादों का उचित पारिश्रमिक दिलाने, उचित मूल्य दिलाने आदि के उद्देश्य से सिदो कान्हू कृषि-वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड का गठन किया गया है। 2024-25 में ग्रामीण, शहरी इच्छुक युवा को मछली पालन की विभिन्न विधाओं में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने के लिए 3,50 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन कराने की योजना है।

वनोपज में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की पहल

वित्तीय वर्ष 2024-25 की नयी घोषणाएं

- राज्य सरकार टेर्टियरी हेल्थ केयर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आगामी वर्षों में राजधानी रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रिम्स का सुदृढ़ीकरण तथा रितपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी की स्थापना करेगी।
- झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का सुगम संचालन एवं किसानों को ससमय उनके धान का मूल्य प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत क्रय किये गए धान से प्राप्त चावल से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को संचालित किये जाने के संबंध में कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) का उपयोग प्रथम बार किया जा रहा है।
- झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत लाभुकों को आच्छादित किये जाने का वर्तमान में निर्धारित लक्ष्य 20 लाख है, जिसे बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव है, ताकि किसी परिस्थिति में पात्र लाभुकों को खाद्यान्न के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
- जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के कमीशन में वृद्धि हेतु विगत वर्षों से महंगाई दरों में हुए वृद्धि तथा जनवितरण प्रणाली संघो द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत देय डीलर कमीशन की राशि 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने का प्रस्ताव है।
- 4जी नेटवर्क आधारित इपॉस मशीनों के अधिष्ठापन हेतु राज्य अंतर्गत आधार आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में वर्तमान में कार्यरत 2जी नेटवर्क आधारित इपॉस मशीनों के स्थान पर 4जी नेटवर्क आधारित इपॉस मशीनों के अधिष्ठिापन की कार्रवाई की जा रही है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को सोयबीन-बड़ी का वितरण किये जाने का प्रस्ताव है।
- छात्रावासों का निर्माण योजनांतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावासों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जायेगा।
- मराड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से युनाईटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एण्ड नॉर्दन आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों / संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स / एम0फिल0 डिग्री ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- जनजातीय संस्कृति एवं उनकी समृद्ध विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से जनजातीय गाँवों में अखड़ा का निर्माण एवं उनके पारम्परिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति का प्रस्ताव है।
- वर्ष 2024-25 में पथ, घनत्व बढ़ाने एवं कोर रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नये पथों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिनका उन्नयन न्यूनतम इमीडिएट लेन कनफिगरेशन के रुप में किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एवं महत्वपूर्ण गलियारे का निर्माण तथा राँची शहर के लिए इनर रिंग रोड एवं अन्य आर्टेरियल-फीडर पथों के निर्माण का लक्ष्य है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,500 कि0मी0 पथ एवं 200 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है।
- राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करने पर स्वीकृति दी गयी है।
- पतरातु में चार हजार मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
- कोडरमा, चांडिल, बलियापुर, गोमिया एवं देवीपुर में ग्रिड सबस्टेशन के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जबकि सिमरीया, बड़कागांव, गोला, दुग्धा, महुदा, निरसा, गांवा, पुटकी, रामगढ़, विष्णुगढ़, पेटरवार एवं हंटरगंज में ग्रिड सबस्टेशन तथा संबंधित संचरण लाईन का निर्माण कराया जायेगा।
- अमृत 20 मिशन अंतर्गत 8 जलापूर्ति योजनाओं यथा कपाली, जामताड़ा, गुमला, बरहरवा, हहिरगंज, छत्तरपुर, श्रीवंशीधरनगर एवं लोहरदगा का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा।
- राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिता हेतु उचित मंच प्रदान करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन का प्रस्ताव है, जिसमें मुख्यतः स्पोर्ट्स एक्शन टुवाइर्स हारनेसिंग एस्पाइरेशन ऑफ यूथ तथा मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।
- जेसैक (झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर) द्वारा एक ड्रोन सर्वेक्षण इकाई स्थापित करने की योजना बनायी गयी है। यह इकाई राज्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नोडल एजेंसी के रुप में कार्य करेगी। यह इकाई ड्रोन निगरानी एवं प्रशिक्षण केन्द्र के रुप में काम करेगी, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के साथ-साथ निजी संस्थाओं को सेवाएं देने के अलावा ड्रोन प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रगति पर शिक्षण एवं अनुसंधान भी किया जायेगा।
- आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। बाल बजट तैयार करने का उद्देश्य राज्य में बच्चों के समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है तथा राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 216 योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 80 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है जिसमें कुल 8,866.69 करोड़ (8 हजार 8 सौ 66 करोड़ 69 लाख) रुपये की राशि उपबंधित की गई है। यह राशि आउटकम बजट के अंतर्गत लिए गये योजनाओं के कुल उपबंधित राशि का लगभग 18 प्रतिशत है तथा राज्य के कुल योजना आकार का लगभग 11 प्रतिशत है।
- झारखण्ड राज्य में परिवर्तन के लिए राजकीय संस्था की स्थापना की जायेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य समग्र विकास हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर समेकित एवं समावेशी विकास को कार्य रुप दिया जायेगा।

बेहतर ऋण प्रबंधन की झलक दिखी

प्रावधान

सामान्य प्रक्षेत्र ▷ 37.124 करोड़

सामाजिक प्रक्षेत्र ▷ 45,377 करोड़

आर्थिक प्रक्षेत्र ▷ 46,399 करोड़

प्राप्ति

राज्य को अपने कर राजस्व: 34,200 करोड़	केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी: 40,338 करोड़
गैर कर राजस्व: 19,301 करोड़	लोक ऋण: 18,000 करोड़
केंद्रीय सहायता: 16,961 करोड़	अग्रिम की वसूली: 100 करोड़ प्राप्त

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। चंपाई सरकार के बजट में बेहतर ऋण प्रबंधन की झलक भी दिखायी पड़ी। इसमें कहा कि राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिये गये ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अबतक इसमें लगभग 1600 करोड़ का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जायेगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ-साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 592 करोड़ रुपये का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव किया गया है। कर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने के लिए पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 700 करोड़ रुपये पेंशन कोष में निवेश किया गया। वर्ष 2024-25 में भी 780 करोड़ रुपये का निवेश के लिए बजट प्रस्तावित है।

वित्तीय संकल्पना: 2024-25 में राजकोषीय घाटा 9,500 करोड़ का अनुमान

बजट पेश करते हुए डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसी विश्वास के साथ में 1.28,900 करोड़ का सकल बजट लाया गया है। यह बीते वर्ष से 10.7 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय को लिए 91,832 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 85 प्रतिशत अधिक है। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाये तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37.124 करोड़, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 45,377 करोड़, आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 46,399 करोड़ उपबंधित किये गये हैं। राज्य को अपने कर राजस्व से 34,200 करोड़ रुपये और गैर कर राजस्व से 19,301 करोड़, केंद्रीय सहायता से 16,961 करोड़ और केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 40,338 करोड़, लोक ऋण से 18,000 करोड़ (18 हजार करोड) रुपये, अग्रिम की वसूली से 100 करोड प्राप्त होंगे। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 9,500 करोड़ होने का अनुमान है।

ग्रामीण विकास: बजट-11316.07 करोड़

गांवों की पगडंडियोंसे निकलेगी विकास की राह

रांची (आजाद सिपाही)। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोतों को बढ़ाने पर बल दिया गया है। रोजगार सृजन और जीवन स्तर को ऊंचा करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2023-24 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 9 करोड़ अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक कुल 9.39 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया। वर्ष 2024-25 में 9 करोड मानवदिवस सृजित करने का लक्ष्य है। अबुआ आवास के तहत लाभुकों को पांच किस्त में दो लाख रुपये देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 लाख 50 हजार और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख 50 हजार को हजार परिवारों को इसका लाम दिया जायेगा। 90 हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का लक्ष्य है। फुलो-झानो आशीर्वाद अभियान को तहत 32676 महिलाएं हडिया दारू बिक्री छोड़कर सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका से जुड़ रही हैं। सखी मंडली के उत्पादों को उचित मूल्य और आर्थिक सहायता देने के लिए यश-ब्रांस के तहत विपणन लक्ष्य 10 करोड़ रखा गया है। राज्य में 6 बड़े शहरों में पलाश मार्ट निर्माण का प्रस्ताव है।

जल संसाधन: बजट 2238.06 करोड़

पीरटांड और पटमदा को लिफ्ट सिंचाई योजना का तोहफा

रांची (आजाद सिपाही)। रांची। राज्य सरकार के अनुसार कृषि योग्य भू-भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर होने के कारण सिंचाई की सुविधा भू-भाग में उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीरटांड मेगा लिफ्ट सिचाई योजना और पटमवा लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा। पीरटाड प्रखंड में बराकर नदी पर बीयर का निर्माण कर भूमिगत पाइप लाईन के माध्यम से जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार पूर्वी सिंहभूम के पटमदा आदि क्षेत्रों में भूमिगत पाइप लाइन से सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। पलामू जिलांतर्गत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशायों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपलाइन सिंचाई योजना के लिए लगभग 456.63 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पंचायती राज: बजट-2066.08 करोड़

12 साल में पहली बार जनप्रतिनिधियों को तोहफा

रांची (आजाद सिपाही)। बजट में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, मुखिया, उपमुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों के मानदेय में बारह वर्षों के बाद पहली बार वृद्धि की गयी है। इसमें मुखिया का मानदेय दो हजार से बढ़ाकर 2500 किया गया है। अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान मद में 1,385 करोड़ (1) हजार ३ सौ 85 करोड) रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है। उक्त राशि से संबंधित सरथा 30 (तीस) प्रतिशत जलापूर्ति पर, ३० (तीस) प्रतिशत स्वच्छता पर एवं शेष 40 (चालीस) प्रतिशत का व्यय स्थानीय आवश्यकता की योजनाओं पर कर सकेगी। पंचायती व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए 2,066.08 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा : बजट-8021.93 करोड़

महिला और बाल विकास पर सरकार की विशेष नजर

आजाद सिपाही संवाददाता

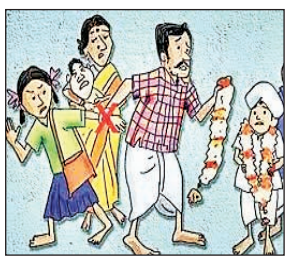

रांची। बजट में वृद्ध, महिलाओं, बच्चों, किशोरियों, दिव्यांगजनों और समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों का कल्याण, समाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किया गया है, लेकिन निःशक्त, आदिम जनजाति, निराश्रित महिलाओं, ट्रांसजेंडरों के साथ-साथ 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आर्थिक रुप से कमजोर सभी महिलाओं, अनुसूचित जनजाति/जाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 3,107.40 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 23 लाख 50 हजार लाभार्थी आच्छादित होंगे। सभी आंगनबाडी केंद्रों का अपना भवन हो, इसे राज्य सरकार सुनिश्चित करा रही है। इसी क्रम में सरकार वर्ष 2025 तक भवनहीन केंद्रों में से 2,500 केंद्र भवन का निर्माण करायेगी। वर्तमान में 38.432 केंद्र संचालित है। यहां बच्चों के लिए टेबुल, कुर्सी भी मिलेगी। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात के लिए आवश्यक सामग्री के लिए 1,500 रुपये के मातृ किट् को 6 लाख लाभार्थियों के बीच वितरण कराया जायेगा। कामकाजी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में समुचित आराम, देखभाल के लिए आर्थिक मदद प्रति लाभुक 5,000 की योजना मद में 92 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग 1 लाख 90 हजार कामकाजी महिलाएं लाभान्वित होंगी।

पेयजल एवं स्वच्छता बजट-2860.27 करोड़

62 लाख ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल

रांची (आजाद सिपाही)। 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 62 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल संयोजन के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध अबतक 31 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण : बजट-7223 करोड़

रांची को मेडिकल कॉलेज, रिनपास में मेडिको सिटी की मिली सौगात

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राज्यवासियों को सुलम, सस्ते और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना, नये नर्सिंग फार्मेसी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इस क्रम में पलामू, चाइबासा, दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना कर ली गयी है।

21 जिलों में चलंत ग्राम क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है।

आगामी वर्षों में राजधानी रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रिम्स का सुदृढीकरण और रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी की स्थापना करेगी।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले : बजट-2,860.27 करोड़

राशन कार्डधारी परिवार को सोयबीन-बरी भी मिलेगा

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत मुफ्त में खाद्यान्न वितरित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए दाल वितरण योजनांतर्गत प्रतिमाह एक किलोग्राम चना दाल, नमक वितरण योजनांतर्गत एक किलोग्राम नमक और प्रति लाभुक 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में वितरित किये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में निर्धारित लक्ष्य 20 लाख है, जिसे बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव है, ताकि किसी परिस्थिति में पात्र लाभुकों को खाद्यान्न के लान से वंचित न रहना पड़े। जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के कमीशन में वृद्धि की गयी है। कमीशन की राशि 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को सोयबीन-बरी का वितरण किये जाने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण कार्य : बजट-5114.03 करोड़

2500 किमी पथ और 200 पुलों का होगा निर्माण

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक हजार किमी पथ पूर्ण करने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 887.04 किमी पथ 602.48 करोड़ खर्च कर पूर्ण की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,000 किमी पथों के निर्माण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढीकरण योजना के तहत पांच वर्ष एवं उससे पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त लगभग 15,000 किमी ग्रामीण सड़कों का सुदृढीकरण कराते हुए ग्रामीण आबादी का सरकारी कार्यालय, स्कूल कॉलेज, स्वास्थ्य केन्द्र / अस्पताल, बाजार तक आवागमन सुगम बनाने का लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके तहहत 5,000 किमी पथों के सुदृढीकरण करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 70 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है। 2500 किमी एथ और 200 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है।

नागर विमानन : बजट-112.93 करोड़

गिरिडीह एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि जल्द

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार की ओर से 301.12 एक-ड़ भूमि का हस्तांतरण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण के पक्ष में एक रुपये की टोकन राशि पर तीस साल के लिए किया गया है। दुमका-बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का कार्य अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार को लाइसेंस निर्गत करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आम जनता के लिए सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा 24 घंटे संचालित की जा रही है। राज्य में नागर विमानन क्षेत्र के उत्तरोत्तर विकास के लिए झारखंड उड्डयन संस्थान नामक सोसाइटी का गठन किया गया है। गिरिडीह स्थित बोडी हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के निमित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है।

शिक्षा प्रक्षेत्र : बजट-2411.77 करोड़

325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का होगा संचालन

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण की सुनिश्चितता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव पहल की गयी है। 80 उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारंभ किया गया है। 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा सभी 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रारंभ करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही 4,036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक हजार विद्यालयों के किचिन-सह-स्टोर की मरम्मति का कार्य किया जायेगा। 2024-25 में सात जिलों के एक हजार प्रारंभिक विद्यालयों में मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की पहल की गयी है, जिसमें डिप्लोमा स्तर पर 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष-डिग्री स्तर के लिए 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू किया जायेगा।

ऊर्जा विभाग : बजट-9378.49 करोड़

गिरिडीह में मॉडल सोलर सिटी विकसित होगी

रांची (आजाद सिपाही)। राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्वाध बिजली आपूर्ति करना सरकार का लक्ष्य है। 100 यूनिट बिजली मुफ्त योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त का लाभ अगस्त, 2022 से दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लगभग19 लाख 20 हजार उपभोक्ता उठा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह मुक्त बिजली प्रदान करने पर स्वीकृति दी गयी है। झारखंड सपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के क्रियानाथन से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हुई है। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं के लिए नये विद्युत संरचना का निर्माण भी किया गया है। पतरातु में चार हजार मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। कोडरमा, चांडिल, बलियापुर, गोमिया, देवीपुर में ग्रिड सबस्टेशन से निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जबकि सिमरिया, बड़कागांव, गोला, दुवा, महुदा, निरसा, गांवा, पुटकी, रामगढ़, विष्णुगढ़, पेटरवार, हंटरगंज में ग्रिड सबस्टेशन से संबंधित संचरण लाइन का निर्माण कराया जाना है। गिरिडीह को मॉडल सोलर सिटी विकसित किया जा रहा है, जिसका दायरा वित्तीय वर्ष 2024-25 में शहर से बढ़ाकर संपूर्ण जिला में करने का प्रस्ताव है।

पथ निर्माण : बजट-6398.28 करोड़

सड़क के जरिये अर्थव्यवस्था को गति देने पर बल

रांची (आजाद सिपाही)। राज्य सरकार का मानना है कि आधारभूत संरचना का विकास न केवल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, वरन यह सामाजिक विकास और सांस्कृतिक उन्नयन का भी वाहक है। राज्य गठन के समय राज्य में पथों की कुल लंबाई 5.400 किमी थी, जो अब बढ़कर 14.131 किमी हो गयी है। पथों का घनत्व वर्ष 2023-24 के प्रारंभ में 173 किमी प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 177 किमी प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। राजधानी में ट्रैफिक को सुगम बनाने के उद्देश्य से पिछले तीन वर्षों में कई नयी योजनाएं प्रारंभ की गयी हैं। इनमें से रांची के सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक फ्लाइओवर, कांटाटोली फ्लाइओवर, सहजानंद चौक से जज कॉलोनी तक फ्लाइओवर, मोरहाबादी पथ पर करमटोली साइंस सिटी फ्लाइओवर, विकास विद्यालय से नामकोम तक फोरलेन पथ निर्माण योजना प्रमुख है।

संकल्प सभा: हेमंत सोरेन को जेल से बाहर निकलवाने का लिया संकल्प

हेमंत सोरेन के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे: चंपाई सोरेन

नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव में झामुमो की जीत सुनिश्चित करने का लिया संकल्प

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। रांची के विधानसभा मैदान में मंगलवार को झारखंड की सत्ताधारी दल झामुमो की ओर से संकल्प सभा आयोजित की गयी। इसमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री बेबी कुमारी सहित कई विधायक शामिल हुए। इस दौरान झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में झामुमो की जीत सुनिश्चित करने और हेमंत सोरेन को जेल से बाहर निकलवाने का संकल्प लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आज हम संकल्प लेते हैं कि हेमंत बाबू के अधूरे कामों को पूरा करने का काम करेंगे, साथ ही आगामी चुनाव में बहरूपिया पार्टी भाजपा को हराकर देश को बचाने का काम करेंगे।

संविधान को रौंदने और तार तार करने में लगी है केंद्र सरकार : मिथिलेश ठाकुर

मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को रौंदने और तार-तार करने में लगी है। समय रहते हम लोग नहीं जागे तो आज जिस तरह संकल्प सभा में बोल रहे हैं। वह बोलने की आजादी भी छिन जायेगी। फिलहाल राष्ट्र और देश में जो स्थितियां बनी है। देश में जो कानून लाये जा रहे हैं। जब कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे इडी और सीबीआइ जेल में डालने का काम करती है। क्या गलती थी हमारे हेमंत सोरेन की। आप सभी किसान है सभी एक दो कट्ठा जमीन खरीदते हैं, लेकिन भाजपा जानती है।

झारखंड के आदिवासी-मूलवासी भोले होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह इडी-सीबीआइ ने बगैर सबूत हेमंत सोरेन को जेल में डाला। इससे भाजपा ने झारखंड के साढ़े तीन करोड़ गरीब आदिवासी की हाय ली है। मौके पर मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि 2019 में हेमंत सोरेन की सरकारी बनी और उसी दिन से भाजपा हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने एका काम किया। एक बार फिर हम सभी मिलकर हेमंत सोरेन के सपनों को साकार करेंगे। विधायक दीपक विरुआ ने कहा कि झारखंड निर्माण में गुरुजी शिबू सोरेन ने जो संकल्प लिया था। उसे पूरा करने के लिए संकल्प रैली की है। हेमंत सरकार को केंद्र सरकार की साजिश करने के फंसाया गया है। 24 वर्ष में किसी भी सरकार ने नहीं किया उसे चंपाई सोरेन ने संकल्प लिया है आठ महीने में उसे पूरा किया जायेगा।

विशाल मोटर साइकिल रैली निकाली

रांची (आजाद सिपाही)। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सीमिती द्वारा आयोजित धुर्वा स्थित शहीद मैदान में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस स्कल्प सभा में झामुमो रांची महानगर की ओर से एक विशाल मोटर साइकिल रैली मधुकम खादगढ़ा सब्जी मंडी से अरुण वर्मा के नेतृत्व में निकाली गयी जो पहाड़ी मंदिर, किशोर गंज चौक, हरमू , अरगोड़ा चौक, बाईपास होते हुए और शिबू सोरेन जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जेल का फाटक टूटेगा हेमंत सोरेन छूटेगा का नारा बुलंद करते हुए धुवा स्थित स्कल्प सभा में शामिल हुए जिसमें तीन सौ मोटर साइकिल 50 ऑटो रिक्शा और अन्य वाहन से महिला पुरुष युवा शामिल रहे। जिसमें मुख्य रूप से अरूण वर्मा, लालाजी रमण, विक्रम सिंह, कृष्णा महतो, सुजीत कुजूर, तौफीक अहमद, मुन्ना यादव, आयुष राज वर्मा, अजय वर्मा, सलाउद्दीन खान,आफताब आलम,अराफात हुसैन, अफजल हुसैन जावेद खान, समीर मंसूरी, अरमान मंसूरी परदीप सिंह, राहुल तिवारी शिवकुमार, अरुण वर्णवाल, रविंद्र चौधरी, पूर्णिमा मिंज, दिनेश वर्मा, अमन चौधरी, रंजीत चौधरी, संदीप वर्मा, संतोष वर्मा, पिंकी तिर्की, मुनी तिर्की, पूजा मिंज, विशाखा कुजूर, चंदू उराइनी, अमित एक्का, अजय मिंज, अरविंद बाखला, विजय कच्छप, राजेश कुजूर, कौशल साहू, विश्वजीत डे, राज डे, संजय अरीप टोप्पो, विकास कुमार, अमन कुमार वर्मा, शुभम कुमार, उत्कर्ष तिवारी, विशाल वर्मा, रंजीत गुप्ता, जयशंकर प्रसाद गुप्ता, राज चक्रवर्ती, मोनू रजक,अनिल रजकसहित सैकड़ों लोग शामिल रहे।

संकल्प सभा में ये भी थे मौजूद

कार्यक्रम में केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने मंच संचालन किया। इस मौके पर मथुरा महतो, विधायक सविता महतो, विधायक समीर मोहंती, विधायक भूषण तिर्की, विधायक जोबा मांझी, विधायक जीग्गा मुंडा, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक बैद्यनाथ राम, विधायक सुदिव्य सोनू, मंत्री दर्जा प्राप्त फागू बेसरा, सांसद महुआ मांझी, पूर्व विधायक और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र महतो सहित झामुमो के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।

भाजपा ने पूछा, सच क्या है बतायें हेमंत सोरेन

थाने में लिखकर दिया पैसे साजिश के तहत इडी ने रखे थे

कोर्ट में एफिडेविट दिया पैसे झामुमो ने दान में दिये : प्रतुल शाहदेव

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वह गलत बयानी कर कानून का दुरुपयोग और अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतुल ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दस्तावेजों को भी दिखाया। कहा कि जब इडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर में छापे के दौरान 36 लाख रुपये नगद उनके रूम के वार्डरोब से बरामद किया था। तब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी, 2024 को एससी एसटी थाने में दर्ज प्राथमिकी की संख्या 06/24 में यह स्पष्ट कहा था कि उन्हें मीडिया चैनलों से ये खबर मिल रही है कि उनके घर से बड़ी मात्रा में अवैध पैसा बरामद हुआ है। उन्होंने उस समय स्पष्ट कहा था कि बरामद किया गया गैरकानूनी पैसा उनका नहीं है। ये सिर्फ ईडी के अधिकारियों के द्वारा उनको सामाजिक रूप से बेइज्जत करने की साजिश है। इसी मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवेदन पर एससी-एसटी एक्ट का एक फर्जी मुकदमा दर्ज भी हो गया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमा डब्ल्यूपी(सीआर) नंबर 68/2024 में हेमंत सोरेन ने अपने आवेदन के प्वॉइंट नंबर 108 में यू टर्न मारते हुए कहा है कि उनके माता और पिता वृद्ध है। उनका लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली में आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उन्होंने कैश को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए रखा था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही नहीं रुके। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो कैश उनके बंगला से बरामद हुआ है वह उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दान में प्राप्त हुआ है।

प्रतुल ने कहा कि एससी एसटी केस में दिये गये आवेदन में वर्णित किये गये तथ्य और उच्च न्यायालय में दिये गये आवेदन में आसमान जमीन का अंतर है। पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कैश से किनारा करते हैं। बाद में उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्राप्त किया डोनेशन बताते है। प्रतुल ने कहा ऐसा करके वह एक्सपोज हो गए हैं। प्रतुल ने कहा कि अब तो इस विषय पर इडी को और इनकम टैक्स को भी जांच करना चाहिए कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इतनी बड़ी राशि किस दिन हेमंत सोरेन को दी थी? प्रतुल ने कहा जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन अपने बचाव में लगातार अपने स्टैंड से पलट रहे हैं और अपने दिये गये बयानों से ही मुकर रहे हैं। अब यह तो साफ हो गया है कि एससी एसटी मामले में दिये गये उनका बयान बेबुनियाद था क्योंकि उच्च न्यायालय में उन्होंने ठीक इसके उलट बयान दिया है। प्रतुल ने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से एक्सपोज्ड हो गयी है। प्रेसवार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक भी उपस्थित थे।

चेशायर होम रोड में 'सिद्धार्थ लोटस' का भूमि पूजन कल

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। अमविशा रियल इस्टेट के बहु प्रतिक्षित लग्जरियस प्रोजेक्ट की भव्य लॉन्चिंग 29 फरवरी दिन गुरुवार को होगी। यह जानकारी मंगलवार को अमविशा रियल इस्टेट के मैनेजिंग डॉयरेक्टर अमरेश झा ने प्रेस को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ लोटस अत्याधुनिक जीवन शैली की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण चेशायर होम रोड, बरियातू, रांची में अवस्थित है। यह प्रोजेक्ट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर, रांची रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से पांच किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छे स्कूल, रिम्स अस्पताल, जिमखाना क्लब, खेलगांव, मेन मार्केट सभी निकटतम दूरी पर हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी इसके निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक का प्रयोग है। जो सामान्यतः मेट्रो सिटीज के भवन निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जिससे भवन की मजबूती भी बहुत उम्दा एवं पर्यावरण अनुकूल होती है। इसके भवन निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक और वास्तु के नियमों का खास ध्यान रखा जायेगा। झारखंड के अतिप्रसिद्ध चड्ढा आर्किटेक्ट ने सिद्धार्थ लोटस का डिजाइनिंग किया है। इन अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग और आधुनिक जीवन शैली की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण इसके कीमत को प्रबंधकों ने बहुत ही रीजनेबल रखा है। यह प्रोजेक्ट रांची नगर निगम एवं रेरा से एप्रूव्ड है और इसे एनजीटी का भी क्लीयरेंस प्राप्त है। प्रबंध निदेशक अमरेश झा ने आगे बताया कि प्रोजेक्ट के इच्छुक ग्राहकों को प्रमुख बैंकों एसबीआइ, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ लोन फाइनेंस कराने की भी सुविधा उपलब्ध है।

ज्ञातव्य है कि सिद्धार्थ लोटस में 3 एवं 4 बीएचके फ्लैट के साथ-साथ प्रीमियम क्वालिटी के पेंटहाउस भी उपलब्ध होंगे। झारखंड वासी अपने बजट और अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी साइज का फ्लैट बुक कर सकते हैं। प्रबंधकों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में 70 प्रतिशत ओपेन स्पेस एरिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिम्नेजियम,जोगिंग ट्रैक, क्लब एवम स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्स बार और कैफेटेरिया, इनडोर गेम्स, गार्डेन, किड्स प्ले एरिया, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर, रिटेल शॉप, एमपी थिएटर,टेंपल, कार वाश, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग प्वाइंट,इत्यादि सभी अत्याधुनिक सुविधायें मौजूद रहेंगी।

अमविशा रियल इस्टेट के मैनेजिंग डॉयरेक्टर अमरेश झा ने उपरोक्त जानकारी के साथ साथ बताया कि सिद्धार्थ लोटस अपने उम्दा क्वालिटी और समय पर डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर कंपनी के कई पदाधिकारी, अजय कुमार सिंह, मिनाक्षी झा, अनुज वत्स, बी पी सिंह, यूपी सिंह, विनोद कुमार पटेल, सुनील कुमार, कुमार गौतम, पंकज कुमार, सत्यम कुमार, पूजा मौजूद थे। इच्छुक ग्राहक 8271985000 और 9939167506 पर संपर्क कर सकते हैं।

बजट की सत्ता पक्ष ने की सराहना

राज्य के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समृद्धि का बजट है : बन्ना गुप्ता

रांची (आजाद सिपाही)। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पेश बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट दूरगामी बजट है। राज्य की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के समृद्धि का बजट है। सभी वर्गों को इस बजट में जोड़ने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से राज्य का भला होगा समृद्धि आयेगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मिले अनुदान पर कहा कि विभाग को 7223 करोड़ का बजट मिला है इससे स्वास्थ्य विभाग की दिशा दशा दोनों बेहतर होगी।

जो बजट पेश किया है वह आने वाले समय में झारखंड की तस्वीर बदल देगा: सत्यानंद

रांची (आजाद सिपाही)। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि आज का बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा जो पेश किया गया वह खासकर श्रमिकों और किसानों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय में समग्र विकास दिखाई देगा। पिछली सरकार ने जो बजट पेश किया था वह कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दिया। हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है वह आने वाले समय में झारखंड की तस्वीर बदल देगी।

पहली बार गांव में अखाड़ा का निर्माण करने एवं वाद्य यंत्र की घोषणा की गयी : भूषण बाड़ा

रांची (आजाद सिपाही)। कांग्रेस के विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि पहली बार गांव में अखाड़ा का निर्माण करने एवं वाद्य यंत्र की घोषणा की गयी है। जो हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए आने वाले समय में मिल का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि चंपाई सरकार ने उभरते खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिये प्रतियोगिता का आयोजन करने की भी घोषणा की है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए एक मंच मिलेगा।बजट में किसानों और गर्भवती महिलाओं के लिए कई योजना लायी गयी है। कुल मिलाकर बजट दूरगामी परिणाम देगा।

चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारियां हैं, इसे हम भली-भांति निभा रहे हैं : मिथिलेश ठाकुर

रांची (आजाद सिपाही)। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस बजट में लक्ष्य है कि सभी घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचना है। इसमें कई बार केंद्र सरकार द्वारा अर्चन लगायी जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों की बात करें तो कृषि विभाग में निर्णय हुआ है कि 2 लाख तक का ऋण किसानों का माफ करना बहुत एक उपलब्धि है। सभी क्षेत्रों में इस बजट में ध्यान रखा गया है।

किसानों को कर्ज से राहत दिलाने वाला बजट: राजेश ठाकुर

रांची (आजाद सिपाही)। प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पेश किया गया बजट अन्नदाता किसानों को कर्ज से राहत दिलाने वाला बजट है। साथ ही गरीबों को सिर ढकने के लिए अबुआ आवास योजना झारखंड का सराहनीय बजट है। इसमें वित्तीय सूझबूझ की झलक साफ दिखायी देती है। क्योंकि बजट न सिर्फ सरकार के वित्तीय घाटा को कम करने में सफल है, अपूर्ति अपने राजस्व सरप्लस से पूंजीगत खर्चों का भी वित्त पोषण कर पा रहा है। यह बजट किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं सभी क्षेत्रों वर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है।

बजट आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा : राकेश सिन्हा

प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि गठबंधन सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। झारखंड की साक्षारता दर में 07 फिसदी की बढ़ोतरी हुई। यह बजट आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा।

किसानों को राहत :सतीश पॉल

प्रदेश मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि 01 लाख, 28 हजार, 09 सौ करोड का बजट पेश किया गया। किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए कर्ज माफी को अब 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। गठबंधन की सरकार किसानों की राहत देने का काम कर रही है वहीं केंद्र की तानाशाह सरकार किसानों पर गोलियां चला रही है।

बजट को भाजपा और आजसू ने नकारा

झारखंड के बजट में गांव-गरीब, किसान युवा के लिए कुछ नहीं : संजय सेठ

रांची (आजाद सिपाही)। सांसद संजय सेठ ने झारखंड सरकार के द्वारा पेश बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा के लिए कुछ नहीं है यह बजट सिर्फ मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाने वाला बजट है। झारखंड ने 1.28 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। पिछली बार से 10 प्रतिशत अधिक है परंतु सरकार पिछले वर्ष की राशि का मात्र 54 प्रतिशत ही खर्च कर पायी है। गठबंधन की सरकार ने जो वादे किये थे हर साल 5 लाख नौकरी देंगे क्या हुआ। नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे उसका क्या हुआ। जब भाजपा की सरकार थी तो किसानों को 5000 प्रति एकड़ दिया जाता था 2000 केंद्र सरकार दे रही है कुल 7000 प्रति एकड़ किसानों को मिलता था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार बनते ही इस योजना को बंद कर दिया। उम्मीद थी कि सरकार का अंतिम बजट है इसमें कुछ प्रावधान करेंगे परंतु फिर इस बार किसानों के साथ गठबंधन की सरकार ने छल करने का काम किया है। कुल मिलाकर सिर्फ यह बजट मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाने वाला है।

बजट में गांव के विकास को लेकर कोई परिकल्पना नहीं: सुदेश महतो

रांची (आजाद सिपाही)। आजसू विधायक सुदेश कुमार महतो ने कहा कि शिक्षा विभाग का बजट घटाना निराशाजनक है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को लेकर बजट में इच्छाशक्ति का अभाव है। झारखंड जैसे राज्य में शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। कोई भी प्रगतिशील राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को विशेष महत्व देते हैं। रोजगार को लेकर उम्मीद जगाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट के अन्य पहलू पर भी नजर डालने से लगता है कि सरकार और उसका तंत्र दिशाहीन है। गांवों के विकास को लेकर उनके पास कोई परिकल्पना नहीं है। इस बजट में आम लोगों को मानक बनाकर काम करने की कहीं जगह नहीं है। रहा। दुखद यह है कि पिछले चार साल से यही पोथी लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और उसमें कोई जवाबदेही नहीं होती।

राज्य की दिशा बदलने में बजट सक्षम नहीं: महेश पोद्दार

रांची। पूर्व सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि राज्य के बजट का साइज तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन कुछ वर्गों को छोड़कर बाकी के लिए छोटा दिख रहा है। रोजगार झारखंड की बडी समस्या है। इसका भी सरकारीकरण करने की कोशिश की जा रही है। तथ्य यह है कि इस बजट की योजनाओं से बहुत छोटे वर्ग को सरकार संतुष्ट कर पायेगी। जो स्वतः रोजगार निर्माण होते हैं इसके लिए बजट में आधारभूत संरचना और प्रोत्साहन इन सब मुद्दों का अभाव दिखता है। केंद्र की सहायता पर निर्भर कई योजनाएं हैं, उनमें राज्य के हिस्से के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है। बजट की खानापूर्ति तो जरूर हुई, पर यह झारखंड की दिशा और दशा बदलने में सक्षम नहीं होगा।

राज्य के बिचौलियों के अनुरूप बजट बनाया है:कुणाल षाड़ंगी

रांची। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इसपर सूबे की मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने झारखंड सरकार के बजट को लूटने और लुटाने वाला बजट करार दिया है। भाजपा झारखंड प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे राज्य की जनता के साथ छलावा बताते हुए राज्य के बिचौलियों के अनुरूप बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट का 40 प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं कर पाई हो वैसी स्थिति में सिर्फ चुनाव को देखते हुए लोकलुभावन और घोषणाओं पर आधारित बजट लाना राज्य की जनता के साथ धोखा और उन्हें भ्रमित करने वाला है।

नया वित्तीय वर्ष झारखंड व झारखंड के लोगों को निराश करने वाला होगा: रमेश सिंह

भाजपा के नेता रमेश सिंह ने कहा कि झारखंड का बजट जन व विकास विरोधी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव में किया गया वायदा पूरा नहीं किया है। बजट में विकास की कोई गति नहीं दिख रही है। यह जनता व राज्य हित में नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं को बजट में दिखाकर सरकार अपना नाम कमाने में लगी हुई है। एक वर्ष में सरकार ने जिस प्रकार काम किया। नया वित्तीय वर्ष झारखंड व झारखंड के लोगों को निराश करने वाला होगा। गठबंधन सरकार पिछले वर्ष की बजट योजनाओं और वायदों को ही पूर्ण नहीं कर पायी। बजट पूर्ण रूप से झूठ का पुलिंदा है। सरकार पिछले बजट का एक फीसद भी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पायी है।

बजट से गरीब, किसान, युवाओं, आदिवासियों को निराशा हुई: सन्नी टोप्पो

भाजपा नेता सन्नी टोप्पो ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले चार साल से अधिक समय से झारखंड के लोगों को झूठे वादों और घोषणाओं की घुट्टी पिलाने वाली झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार का यह बजट भी खोखला है। वर्तमान सरकार के इस अंतिम बजट से जनता को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इस दिशाहीन व निराशाजनक बजट से गरीब, किसान, युवाओं, आदिवासियों और महिलाओं के साथ सभी वर्गों को को निराशा हुई है।लुभावन घोषणाओं के मायाजाल व उदासीन क्रियान्वयन से झारखंड सरकार की योजनाएं पोस्टर और बैनर तक सिमटकर विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल के कुशासन से त्रस्त हो चुकी जनता में सरकार की कार्यप्रणाली से भारी आक्रोश है।

भ्रमित, निराश और हताश करने वाला बजट : जैलेंद्र कुमार

जैलेंद्र कुमार ने झारखंड सरकार के बजट को भ्रमित, निराश और हताश करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में भविष्य की कोई ठोस योजना नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखद है कि युवाओं को फिर से धोखा मिला है। यह बजट सिर्फ घोषणाओं पर टिकी हुई बजट है। झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार पिछली बार के बजट की राशि और घोषणाओं को अबतक पूरा नहीं कर पाई। बजट में बेरोजगारी और युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं की गयी है। युवा वर्ग को झामुमो- कांग्रेस गठबंधन सरकार ने फिर से धोखा दिया है।

अदूरदर्शी सोच वाला, विकास विरोधी बजट: दीपक बंका

दीपक बंका ने बजट को अदूरदर्शी सोच वाला, विकास विरोधी बजट बताया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दूरगामी सोच वाला लोक कल्याणकारी योजनाओं का समावेश नहीं है। केवल लूट खसोट की योजनाओं का कॉपी पेस्ट करते हुए ऑफिसर्स के लिए लूट के रास्ते को खुला रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को ठगबंधन सरकार ने 4 वर्ष पूर्व ही 2 लाख तक के ऋण माफी की बात कही थी लेकिन सब खाली गया। युवाओं के बेरोजगारी भत्ता का भी वादा पूरी तरह विफल साबित हुआ। उल्टे इस सरकार ने भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद कर किसानों के साथ अन्याय किया।

बजट में छात्र और युवा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है: ओम वर्मा

रांची (आजाद सिपाही)। आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश वर्ष 2024 के बजट में छात्र और युवा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार छात्र और युवा के नाम पर युवा पीढ़ी को बरगला कर इस सत्ता में आयी है। सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर छात्र और युवा विरोधी कार्य कर रही है। शिक्षा का भी बजट कम कर दिया गया है। इससे आगे कहा कि न रोजगार, न शिक्षा और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था ही अच्छा है। छात्र और युवा पढ़ाई छोड़ रोजगार के लिए आंदोलन करने कर रहे हैं, फिर भी सरकार अपनी गहरी निद्रा में सोई हुई है।

बजट से झारखंड का भला नहीं: विजय शंकर

रांची। संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विजय शंकर नायक ने कहा कि इस बजट से झारखंड का भला नहीं हो सकता है। सरकार बजट तो लंबा चौड़ा बनाती है, मगर खर्च करने में फिसड्डी साबित होती रही है। श्री नायक ने कहा कि राजद, कांग्रेस, झामुमो महागठबंधन की सरकार का यह अंतिम बजट होगा, क्योंकि यह सरकार ने झारखंडी समाज के विकास के साथ विश्वासघात करने का कार्य किया है।

शहर की खबरें पेज 10 पर भी

विकास के जरिये नक्सल के खात्मे पर जोर

गृह, कारा और आपदा प्रबंधन, बजट-9527.20 करोड़

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राज्य के 13 उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आकस्मिक प्रकृति की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष केंद्रीय सहायता नामक योजना वर्ष 2017-18 में प्रारंभ की गयी है। इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो राशि प्राप्त होगी, उसका व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही संभव हो सकेगा, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है। राज्य के युवक जो वामपंथ उग्रवादियों के प्रभाव में आकर भटक गये हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, ताकि ये एक सामान्य जीवन जी सकें एवं राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें। जिन इलाकों को उग्रवाद के चगुल से मुक्त कराया जा चुका है, वहीं विकास की गति में तेजी लायी जायेगी, ताकि उग्रवाद यहीं दोबारा पैर नहीं पसार सके। जो इलाके आज भी वामपंथ उग्रवाद से ग्रसित है उन इलाकों को अभियान और विकास के माध्यम से वामपथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त कराया जायेगा। काराओं में क्षमता से अधिक बंदियों की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न काराओं की मरम्मति/चहारदीवारों का निर्माण / अतिरिक्त बंदी वार्ड का निर्माण / शौचालय / रसोईघर इत्यादि का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

वन क्षेत्र बढ़कर 34 प्रतिशत तक पहुंचा

वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

बजट-1371.39 करोड़

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। वन संवर्द्धन एवं संरक्षण के सतत प्रयासों के कारण राज्य का वनावरण, पौधरोपण बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 34 प्रतिशत से अधिक हो गया है। राज्य के वनों-संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यप्राणी आश्रयणियों में अवस्थित प्राकृतिक सौंदर्य स्थलों में इको टूरिज्म का विकास कार्य मुख्यमंत्री जन-वन योजना, कैंपा योजना, लघुवन पदार्थ का उन्नयन योजना आदि के माध्यम से वन क्षेत्र का कार्य किया जा रहा है।

ड्रोन सर्वेक्षण इकाई स्थापित करने का लक्ष्य

सूचना, प्रौद्योगिकी और इ-गवर्नेस, बजट-303.49 करोड़

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राज्य सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत राज्य की दो महत्वाकांक्षी पॉलिसी को अधिसूचित किया गया है। इससे राज्य के युवक/युवितियों को उद्यमिता में काफी बढ़ावा मिलेगा। देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं, संसद में वर्तमान मैनुअल कार्यप्रणाली को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जारी है। इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी और इ-गवर्नेस विभाग, झारखंड विधान सभा के मध्य त्रिपक्षीय एकरारनामा किया गया है। परियोजना का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

एक ड्रोन सर्वेक्षण इकाई स्थापित करने की योजना बनायी गयी है। यह इकाई राज्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। यह इकाई ड्रोन निगरानी, प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगी, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के साथ-साथ निजी संस्थाओं को सेवाएं देने के अलावा ड्रोन प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रगति पर शिक्षण-अनुसंधान भी किया जायेगा।

पुवाल चक्की में लगी आग, हजारों का नुकसान

ईचागढ़(आजाद सिपाही)। प्रखंड क्षेत्र के कुरमाडीह टोला बिस्टाटांड़ गांव निवासी सुफल महतो के खलियांन में रखे पुवाल में मंगलवार शाम 4 बजे अचानक आग लग गयी। आग लगने से खलियान में रखे जल कर राख हो गयी। जिससे किसान सुफल महतो का हजारों रुपये का नुकसान हो गया। पुवाल चक्की में आग की सूचना मिलते ही घर वाले आनन फानन में कुंवा से पानी ला कर आग को बुझाया, तब तक सभी पुवाल जल कर राख हो गया था। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि मुकेश कुमार महतो ने बताया कि आग किस कारण लगा था, इसका पता नहीं चल रहा है। वहीं उन्होंने आपदा प्रबंधन बिभाग से किसान सुफल महतो को मुआवाजा देने की मांग किया। चांडिल डैम से विस्थापित 116 गांव के विस्थापितों का पुनर्वास और घोड़ानेगी के रैयत के मुआवजा को लेकर विभागीय मंत्री बसंत सोरेन से मिले विधायक सविता महतो उपस्थित थे।

खोरठा के वरिष्ठ साहित्यकार शिवनाथ प्रमाणिक का निधन

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। खोरठा के वरिष्ठ साहित्यकार शिवनाथ प्रमाणिक का मंगलवार को सुबह 10 बजे 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। स्व शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म बोकारो जिले के बैधमारा गांव में सन 13 जनवरी 1949 को एक साधारण परिवार में हुआ था। वे पूरे खोरठा क्षेत्र में 'माणिक' के नाम से विख्यात थे। माणिक जी बचपन से ही नटखट, चंचल और लिखाई-पढ़ाई में काफी रूचिकर थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के बावजूद उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरी की। तमाम पारिवारिक व अन्य दिक्कतों के बावजूद साहित्यिक लेखन को लगातार प्रवाहित करते रहे और खोरठा साहित्य जगत में साहित्य की हर विधा में एक से बढ़कर एक रचनाएं उन्होंने दिये। इतना ही नहीं वे गांव गांव जाकर लोगों को खोरठा भाषा साहित्य के विकास से अवगत कराते रहे। कई जगहों में खोरठा भाषा से जुड़ी संस्थाओं का गठन किये तथा कुछ ऐसी संस्था जो कई वर्षो से शिथिल पड़ी हुई थी उसका पुनर्गठन भी करवाये। माणिक जी एक उच्चस्तरीय साहित्यकारों मे से एक हैं। इन्होंने खोरठा भाषा साहित्य की संरक्षण व संवर्धन करने हेतु लोगों को खोरठा लेखन के प्रति जागरूक भी करवाते रहे जो आज भी निरंतर देखने को मिल रही है।

अबुआ आवास सूची में गड़बड़ी को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

खलारी(आजाद सिपाही)। लपरा पंचायत के नवाडीह के ग्रामीणों ने अबुआ आवास योजना सूची में गड़बड़ी को लेकर खलारी प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। रैयत विस्थापित मोर्चा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बीडीओ से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत जारी सूची में नवाडीह की भारी आबादी जिसमे एससी एसटी की लिस्ट में नाम नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि अबुआ आवास में लाभुको के चयन में गड़बड़ी की गयी है, यही कारण है कि नवाडीह जैसे भारी आबादी वाले गांव में मात्र चार पांच लोगों की सूची में नाम है जबकि गांव में अधिकांश एससी एसटी वर्ग के लोग हैं जिनका रहने के लिए ठीक से घर नहीं है। वैसे लाभुकों को आवास मिलना चाहिए। मुखिया पुतुल देवी ने भी कहा कि जो सूची ग्राम सभा में प्रस्ताव किया गया था। उस आधार पर सूची में गड़बड़ी हुई है जिससे प्रथम सूची में जिनको सूची में रखा गया था, वैसे लाभुकों का नाम नही आया है। इस मौके पर रैयत विस्थापित मोर्चा के प्रवक्ता राम लखन गंझु, कार्यकारी अध्यक्ष जालिम सिंह, अमृत भोगता, नरेश गंझु, शिवनारायण लोहरा, दिनेश प्रसाद, नरेश यादव, रामधारी गंझू, बिनोद मुंडा सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।

अधिकार मार्च रैली में शामिल हुए खूंटी से मूलवासी सदान मोर्चा के लोग

खूंटी (आजाद सिपाही)। मूलवासी सदान मोर्चा के बैनर तले रांची के मोरहाबादी मैदान से मंगलवार को निकाली गयी अधिकार मार्च रैली में खूंटी क्षेत्र से बड़ी संख्या में मूलवासी सदान मोर्चा के लोग शामिल हुए। अधिकार मोर्चा रैली में शामिल होने के लिए खूंटी से बड़ी संख्या में मूलवासी सदान मोर्चा के लोग मोरहाबादी रांची के लिए रवाना हुए। इनमें मुख्य रूप से सदान मोर्चा के जिलाध्यक्ष शिव नारायण गौंझू, प्रदेश युवा अध्यक्ष सयूम अंसारी, जिला संरक्षक किशोर कुमार गौंझू, नरेंद्र कुमार साहू, महावीर महतो, विनोद राम, बजरंग महतो, कृष्णा महतो, राशिद खान, शफीक अंसारी, गोंदरा महतो आदि शामिल हैं।

वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रानीखटंगा में श्री महाबीर मंदिर का वार्षिकोत्सव संपन्न

इटकी (आजाद सिपाही)। इटकी प्रखंड के रानीखटंगा गांव में श्री महाबीर मंदिर का वार्षिकों उत्सव के अवसर पर मंगलवार को सैकड़ों महिलाओं ने कलश सोमायात्रा निकाली। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर गांव की सीमा के बाहर पंडरा गांव स्थित कोयल नदी पहुंचा। जहां मां गंगा का अह्वान कर महिलाओं ने कलश में जल लेकर कतारवद्ध होकर जयकारा लगाते श्री महाबीर मंदिर प्रांगण पहुंचे। आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। आयोजकों द्वारा भंडरा का भी आयोजन किया। कलश यात्रा में वरण ठाकूर, सतीष गोप, राम नरायण ठाकुर, अमित उरांव, रमेश ठाकुर के अलावा सैकड़ों महिलाएं और ग्रामीणों ने भाग लिया।

विवेक जायसवाल को दूरसंचार सलाहकार बनाये जाने पर भाजपायों में खुशी का माहौल

बुंडू (आजाद सिपाही)। विवेक जायसवाल को भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा दूरसंचार सलाहकार समिति रांची के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य बनाये जाने से तमाड़ सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह मुंडा अड़की सांसद प्रतिनिधि अनूप साहू भाजपा प्रदेश पंचायत प्रकोष्ठ के सहसंयोजक रंजीत लाहेरी जिला मंत्री गणेश कुम्हार नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेश उरांव बुंडू नगर मंडल अध्यक्ष आलोक दास ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धीरेंन महतो तमाड़ मंडल अध्यक्ष रड़गाव मंडल अध्यक्ष भास्कर मुखर्जी सुबोध मुखर्जी सहित तमाड़ विधानसभा के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी।

भाजपा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया

खलारी (आजाद सिपाही)। गांव चलो अभियान के निमित भाजपा कार्यकर्ता रतन लाल ने भूत नगर डकरा के बूथ संख्या 41 में प्रवास किया। जहां बूथ अध्यक्ष से संपर्क कर सभी कार्यों को पूर्ण किया। जिसमें बुथसमिति का सत्यापन, नये सदस्यों को सदस्यता कराया, दीवार लेखन किया। साथ ही, केंद्र सरकार के योजनाओं से अवगत कराया और जानकारी लिया। इस तरह से सभी कार्य पूर्ण किया गया। इस अभियान में विशेष रूप से विधायक प्रतिनिधि श्याम सुंदर सिंह, बुथ अध्यक्ष संजीत तुरी, अनिल तुरी, प्रमोद प्रजापति, धनु तुरी, ननका तुरी,रमेश भुइया, दशरथ तुरी, विजय तुरी, कृष्ण तुरी, उर्मिला देवी, मोहनी देवी, कमली देवी, फोगनी, जशो, पूजा आदि लोग शामिल रहे।

भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब मथुरा की बारी : संजय सेठ

सांसद ने 56 लाख की लागत से बनने वाले चार कमरे का किया शिलान्यास

आजाद सिपाही संवाददाता

सिल्ली। सोमवार देर शाम सांसद संजय सेठ ने कुटाम, मुरी स्थित भक्ति वेदांत गुरूकुल में चार कमरे का शिलान्यास विधिवत पूजा पाठ और नारियल फोड़कर किया। मौके पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि गुरूकुल में सीसीएल के सीएसआर फंड के तहत 56 लाख की लागत से चार कमरे का निर्माण कराया जायेगा। कमरे के निर्माण होने से कमरे की जो कमी थी वो पूरी हो सकेगी। गुरूकूल से मेरा अन्याश्रय संबंध है जब भी आता हूं शांति की अनुभूति होती है। यहां के विकास के लिए आगे भी मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा। कुटाम स्थित गुरुकुल आने वाले समय में यह राज्य का सबसे बेहतरीन अध्यात्मिक केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि गुरूकुल हमारी वैदिक परम्परा है। आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आध्यात्मिक ज्ञान से मन को शांति मिलती है और मन स्थिर रहता है। सांसारिक सुख अशांति का कारण है। इससे मुक्ति का एक मात्र साधन परमात्मा का ध्यान है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है अब मथुरा की बारी है। इससे पूर्व सांसद ने गौशाला में गौ माता की पूजा की उसके बाद आश्रम के लोगों के साथ हरिनाम संकीर्तन में खूब झूमे। कार्यक्रम के अंत में सांसद ने श्रद्धालुओं के साथ सामूहिक प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर संस्थापक दास गदाधर दास, भाजपा ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष विनय महतो धीरज, मंडल अध्यक्ष विनोद साहू, चित्तरंजन महतो, मनोज महतो, सृष्टिधर प्रजापति, प्रधान गोवर्धन मुंडा, सुबल दास, विजय दास , करूणा अवतार गौर दस, भद्रांग, कुरूश्रेष्ठ दास, असीम कृष्ण दास, सचिसुत दास, विश्वानाथ दास, घनश्याम, स्तोक कृष्ण, व्रजनंद आदि मौजूद थे।

आदिवासी न्याय उलगुलान हुंकार सभा में 11 प्रस्ताव पारित

इवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराये आयोग

आजाद सिपाही संवाददाता

खूंटी। झारखंड उलगुलान संघ के तत्वावधान में मंगलवार कों कचहरी मैदान खूंटी में आदिवासी न्याय उलगुलान हूंकार सभा का आयोजन 22 पड़हा कोम्पाट मुण्डा के अध्यक्ष विलियम तोपनो की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। सभा का संचालन आशीष गुड़िया, मुंशी मुंडा और बेनेदिक्त नवरंगी ने संयुक्त रूप से किया। खूंटी जिला के सैकड़ों गांवों के हजारों आदिवासियों की उपस्थिति में 11 प्रस्ताव पारित किये गये। प्रस्ताव के संबंध में अलेस्टेयर बोदरा ने बतोया कि इसमें कहा गया है कि आदिवासी समाज में डिलीस्टिंग का जहर फैलाने का मूल लक्ष्य है पांचवी अनुसूची को समाप्त कर जमीन और जंगल पर कब्जा करना तथा आरक्षण को खत्म करना। ऐस तत्वों और संगठनों पर आदिवासी समाज में वैमनस्यता फैलाने को लेकर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आदिवासियों के सामुदायिक उपयोग की भूमि, जंगल-झाड़, गैर मजरूआ और गोचर जमीन, जो खतियान पार्ट टू में उल्लेखित है उसे भूमि बैंक में शामिल करना आदिवासी विरोधी सोच है। इस नीति को यथाशीघ्र रद्द किया जाये। सरना कोड नहीं देने के पीछे का षडयंत्र है आदिवासियों के अस्तित्व को नकार देना। शहरीकरण के नाम पर गांव को लैंड-पूल के दायरे में लाने से आदिवासियों के संवैधानिक विशेषाधिकार के प्रभावित होने का खतरा है। ऑनलाइन भू.दस्तावेजों खेवट, खतियान, लगान रसीद में त्रुटि जानबूझ कर किया गया है। इसलिए सुधार को लेकर अधिकारियों में भी गंभीरता नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इवीएम से चुनाव किये जाने में निष्पक्षता का अभाव है, मतगणना के दौरान वीवीपेट पर्ची की गणना नहीं किया जाना संदेह पैदा करता है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव किया जाना चाहिए। सभा को संयोजक अलेस्टेयर बोदरा, मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्लेडसन डुंगडुंग, सुबोध पूर्ति, अनिल वीरेन कंडुलना, रेजन गुड़िया, दुर्गावती ओड़ेया, बैजनाथ पाहन, कुलन पतरस आईंद, शिबू होरो, पौलुस हेमरोम, दामू, सेरेंग पतरस गुड़िया, सिरील, उमल, अबिसालोम आदि ने संबोधित किया।

अच्छी पुस्तकें जीवन के अंधकार को दूर कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं: डीडीसी

आजाद सिपाही संवाददाता

खूंटी। जिला सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में परिणत शहर के एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय में मंगलवार को एक दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। इस पुस्तक मेले में देशभर के 26 प्रकाशकों द्वारा अपने पुस्तकों की प्रदर्शनी लगायी गयी। पुस्तक मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह ने किया। पुस्तक मेला में राज्य स्तर से जिले के चयनित 16 विद्यालयों जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय, मॉडल विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्थापित पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का क्रय करने के लिए सभी संबंधित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों द्वारा उपयोगी पुस्तकों का चयन किया गया। मौके पर डीडीसी नीतीश कुमार सिंह ने पुस्तकों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अच्छी पुस्तकें लोगों के जीवन में व्याप्त अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाने और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस पुस्तक मेले में काफी अच्छी पुस्तकें प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैं। इन्हें देखने और पढ़ने की आवश्यकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपरूपा पाल चौधरी ने कहा कि आज के दौर में भी पुस्तकों का महत्व उतना ही है, जितना पहले हुआ करता था। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को विद्यालय में उपलब्ध पुस्तकों की गहनता से अध्ययन करना चाहियें, ताकि वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अच्छे चरित्र का भी निर्माण कर सकें। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी, क्षेत्र प्रबंधक के साथ ही राज्य स्तर से चयनित सभी 16 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाएं, विद्यार्थी सहित अन्य पुस्तक प्रेमी उपस्थित थे।

श्रमदान कर ग्रामसभा ने बनाया बोरी बांध

खूंटी (आजाद सिपाही)। जनशक्ति से जलशक्ति अभियान के तहत मंगलवार को मुरहू ग्रामसभा और पंचायत प्रतिनिधियों ने श्रमदान कर मुरहू नाला पर बोरीबांध का निर्माण किया। मदईत परंपरा के तहत श्रमदान से जब बोरीबांध बनकर तैयार हुआ, तो ग्रामसभा के सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से सोमार बाजार टांड़ में भोजन किया। बोरीबांध निर्माण में ग्रामीणों का उत्साहवर्द्धन करने के लिए ग्रामसभा सचिव राफेल मुंडू, जिला परिषद सदस्य नेलानी देमता, उपप्रमुख अरूण कुमार साबू, मुखिया ज्योति ढ़ोढ़राय ने श्रमदान किया। गांववालों को गर्मी के दिनों में मवेशियों को पानी पिलाने, नहाने-धोने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती थी। बोरीबांध बनने से ग्रामीणों के एक साथ कई फायदे होंगे। जिला परिषद सदस्य नेलानी देमता ने कहा कि गर्मी के दिनों में सोमार बाजार मुहल्ला के लोगों को काफी परेशानियां होती है। मौके पर जुनिका मालवा, सुसाना मुंडू, अगाथा होरो, सहित कई लोगों ने श्रमदान किया।

लोवाडीह ग्राम प्रधान का आकस्मिक निधन

सोनाहातू (आजाद सिपाही)। प्रखंड के राजस्व ग्राम लोवाडीह के ग्राम प्रधान देवेंद्र नाथ सिंह मुण्डा का मंगलवार को आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन पर क्षेत्र में दु:ख की लहर फैल गयी। अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को दिन 12 बजे कांची नदी लाया गया और दाह संस्कार किया गया। मुंडा के निधन पर ग्राम प्रधान संघ के मुंडा कृष्ण कुमार सिंह, जगतपाल बड़ाइक, गोपाल सिंह मानकी, धीरज सिंह मुंडा, आदिवासी विकास संघर्ष समिति के भोलेश्वर सिंह मुंडा, मनोज सिंह मुंडा, विकास सिंह मुंडा, मनोहर सिंह मुंडा, राजकिशोर सिंह आदि ने शोक व्यक्त किया।

विधायक सविता महतो ने जल संसाधन मंत्री बसंत सोरेन से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा

ईचागढ़(आजाद सिपाही)। झारखंड विधानसभा परिसर में मंगलवार को ईचागढ़ के विधायक सविता महतो ने जल संसाधन मंत्री बसंत सोरेन से मुलाकात कर तीन मांग पत्र सौंपा। इस दौरान विधायक सविता महतो ने चांडिल डैम से विस्थापित 116 गांव के विस्थापितों का पुनर्वास और अन्य सभी सुविधा मुहैया कराने, डैम का जलस्तर आर एल 180 मीटर तक ही भंडारण का मांग किया। साथ ही विधायक ने घोड़ानेगी के रैयतदारों की जमीन जो विगत 40 वर्षो पूर्व लिया गया था। जिसका मुआवजा करीब 24. 50 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हुआ है रैयतदारों को मुआवजा भुगतान हेतु राशि उपलब्धता करने व ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के लिए मैसाड़ा गांव चांडिल डैम से नहर होते हुए 15 किमी लिफ्ट द्वारा सिंचाई, नीमडीह प्रखंड के ओड़ीया गांव से 10 किमी की सिचाई लिफ्ट द्वारा और चांडिल प्रखंड के आमटांड नदी से कांसीडीह होते हुए घाटशिला कांदरबेड़ा तक 6 किमी तक सिचाई लिफ्ट इरिगेशन से करने का मांग किया है। विभागीय मंत्री ने विधायक सविता महतो को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी मांगों पर अमल किया जायेगा। इस अवसर पर झामुमो केंद्रीय सदस्य काबलु महतो, समीर महतो, घोड़ानेगी के रैयतदार आमीन महतो, परितोष सतपति, राम प्रसाद आदित्यदेव, कमल, रामपोदो आदि उपस्थित थे।

बुंडू के नगर प्रशासक को ज्ञापन सौंपा गया

बुंडू (आजाद सिपाही)। आजसू पार्टी रांची जिला समिति के वरीय उपाध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा के नेतृत्व में मंगलवार को नगर पंचायत बुंडू के नगर प्रशासक शुभम पोद्दार को एक ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में पेयजल कनेक्शन में बुंडू नगर पंचायत द्वारा 2008 में बीपीएल सर्वे कराये गये थे। इस आधार पर नि:शुल्क पेयजल कनेक्शन दिया जाये, वर्तमान में नगर पंचायत द्वारा जारी किया गया। बीपीएल सूची में तृतीय में अभिलंब संज्ञान में लेकर सुधार करने, अभिलंब सर्वे कराकर बीपीएल नंबर जारी करना जब तक सर्वे नहीं होती है तब तक आने वाले गर्मी को नजर में रखते हुए लाल पीला कार्ड को मान्यता देकर पेयजल कनेक्शन नि:शुल्क या न्यूनतम राशि में देने की मांग किया गया है। इस ज्ञापन की प्रति को बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी संदीप अनुराग टोपनो उपयुक्त रांची और सचिव नगर विकास विभाग को भी दिया गया है। इस अवसर पर हरिहर महतो, योगेश्वर महतो, काली पद महतो, नंदे महतो, मोहम्मद सेराज सुख सारण महतो, सचिन महतो आदि मौजूद थे।

डीएवी स्कूल खूंटी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्ट ब्लांच प्रोजेक्ट का बनाया गया हब

खूंटी (आजाद सिपाही)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्ट ब्लांच प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वामी श्रध्दानंद डीएवी सेंटीनरी पब्लिक स्कूल को खूंटी का हब स्कूल बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का संचालन सीबीएसई तथा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी संयुक्त रूप से करेंगे। यह जानकारी स्कूल के प्राचार्य मनोजेश्वर कुमार ने मंगलवार को विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष आठवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों के पठन पाठन का कार्य हाइब्रिड लर्निंग माध्यम से होगा, जहां शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाएं एक साथ लेने की व्यवस्था की जायेगी। उपर्युक्त कार्य के लिए आवश्यक उपकरण, लैपटॉप तथा सॉफ्टवेयर टेक अवांट ग्रांट कंपनी द्वारा प्रदान किये जायेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करना है।

विद्यालयों में चलाया गया जागरुकता अभियान

खूंटी (आजाद सिपाही)। तोरपा थाना पुलिस के सौजन्य से मंगलवार को राजकीयकृत मध्य विद्यालय उकड़ीमाड़ी, राजकीय मध्य विद्यालय गिड़ुम सहित कई विद्यालयों में डायन बिसाही, सड़क सुरक्षा, बाल विवाह, पोक्सो एक्ट, सोशल मीडिया सहित अन्य सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वास के संबंध में जाकरुकता अभियान चलाया गया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन पांडेय ने कहा कि डायन बिसाही जैसे अंधविश्वास और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कोई सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करें।

बहुजन समाज पार्टी का भविष्य

बहुजन समाज पार्टी सांसद रितेश पांडेय ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। बड़ी बात यह है कि वह अकेले नहीं हैं। पार्टी के कई सांसदों के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी निष्ठा बदल चुकी है। हालांकि जब तक औपचारिक घोषणा न हो जाये, तब तक ऐसी अटकलों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मगर बसपा चीफ मायावती ने खुद यह कह कर इन खबरों को कुछ हद तक प्रामाणिकता दे दी है कि अपना हित साधने में लगे ऐसे सांसदों को पार्टी टिकट दे भी तो क्यों।

गिरता ग्राफ : हाल के चुनावों में बसपा का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। इसने पार्टी के भविष्य से जुड़ी चिंताओं को मजबूती दी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में उसने 10 सीटें जीतीं, लेकिन नतीजे आने के ठीक बाद पार्टी ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले लड़ी और सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पायी। उसका वोट शेयर भी गिरकर 12 फीसदी पर आ गया, जबकि 2014 में एक भी सीट हासिल नहीं करने के बावजूद उसे 19.77 फीसदी वोट मिले थे। चुनावी राजनीति में इस तरह का प्रदर्शन आम तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसकी समाप्ति का संकेत ही माना जाता है।

बहुजन समाज पार्टी सांसद रितेश पांडेय ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। उन्होंने पार्टी टिकट देने की अपेक्षा भी जतायी है। बसपा का चुनावों में प्रदर्शन कमजोर रहा है और गठबंधन तोड़ने के बाद वोट शेयर भी गिरकर 12 प्रतिशत हो गया है।

गठबंधन से दूरी : बसपा समर्थकों में सबसे ज्यादा चिंता पार्टी नेतृत्व की गठबंधनों से दूरी रखने की घोषणा से है। गौर करने की बात है कि बसपा हमेशा किसी न किसी गठबंधन के जरिये ही सत्ता तक पहुंची है। एकमात्र अपवाद 2007 के विधानसभा चुनाव रहे, जिसमें पार्टी ने 'बहुजन हिताय' की जगह 'सर्वजन हिताय' को चुनावी मंत्र बनाया था। अपने मुख्य समर्थक वर्ग के साथ ही किसी और तबके को साथ लेकर ही वह चुनावी जीत को साध पाती है। ऐसे में मौजूदा पॉलिसी पार्टी के बाहर ही नहीं, अंदर भी कई तरह के सवाल और संदेह पैदा कर रही है। पार्टी समर्थकों को इस बात की भी चिंता है कि यदि पार्टी जल्दी किसी फैसले पर नहीं पहुंची, तो 2024 के चुनाव में भी उसके लिए बहुत कुछ शेष नहीं रह जायेगा। किसी भी दल के लिए 15 साल का वनवास बहुत मायने रखता है।

उत्तराधिकार का सवाल : बसपा चीफ ने औपचारिक तौर पर ऐसी घोषणा भले न की हो, पार्टी में यह साफ कर दिया है कि उनके भतीजे आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। बहुजन समाज के हितों को समर्पित मानी जाने वाली इस पार्टी के समर्थकों के लिए यह कथित परिवारवादी रुझान एक नयी चीज है और कहा जा रहा है कि उनके लिए इसे पचाना आसान नहीं होगा। बसपा के लोग अभी से इस पर भौहें सिकोड़ने लगे हैं।

चुनाव नतीजों का इंतजार : वैसे किसी नेता या राजनीतिक दल की भूमिका या उसके सफर का भविष्य एकाध फैसलों या कुछेक चुनाव परिणामों से नहीं तय किया जा सकता। आज भी बसपा कुछ राज्यों में दलित समूहों के बीच सबसे प्रभावी उपस्थिति रखती है। यही नहीं, अपने लंबे राजनीतिक करियर में मायावती अपने समर्थकों को ही नहीं, विरोधियों को भी चौंकाती रही हैं। लेकिन इस बार वह ऐसा कुछ कर पाती हैं या नहीं, इसका जवाब पाने के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा।

अभिमत
आजाद सिपाही

सीजीटीएमएसइ ने एमओएमएसएमइ के साथ मिलकर उद्योग जगत और ऋण देने वाले संस्थानों के बीच जागरूकता पैदा की है। सीजीटीएमएसइ फंडिंग की मंजूरी के बाद के वर्षों में लाभार्थियों ने अपने कारोबार के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी वृद्धि का अनुभव किया है। इसका एमएसइ क्षेत्र के छह प्रमुख क्षेत्रों यानी प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन, बाजार विकास, योजना की स्थिरता, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

समृद्धि की राह: एमएसएमइ के लिए ऋण की सरल प्रक्रिया

डॉ इ विजया

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, क्योंकि वे देश के सतत विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस क्षेत्र की जीवंतता घरेलू और वैश्विक, दोनों बाजारों के लिए तैयार किये गये उत्पादों/सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला में निहित है, जो सरकारों/हितधारकों के नीतिगत समर्थन से लैस है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के बावजूद एमएसएमइ क्षेत्र को ऋण की सहज उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियां धन उधार लेने में अपनायी जाने वाली पारंपरिक कार्य प्रणालियों, तीव्र प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों की कठिन प्राथमिकताओं और डिजिटल सुविधाओं की कमी के कारण पैदा होती हैं और इस क्षेत्र के विकास की राह में अतिरिक्त समस्याएं पेश करती हैं।

भारत सरकार का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमइ) पिछले एक दशक से ऋण सहायता, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल विकास और बाजार संबंधी सहायता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जरिये एमएसएमइ क्षेत्र को समर्थन प्रदान करने और उन्हें विकसित करने हेतु सक्रिय रूप से विभिन्न नीतिगत उपायों को लागू कर रहा है। ये पहल भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एमएसएमइ क्षेत्र की वृद्धि और स्थिरता की दृष्टि से अहम हैं।

पिछले साल की 1.04 लाख करोड़ रुपये की गारंटी की मंजूरी की तुलना में यह सीजीटीएमएसइ के संचालन में निरंतर व महत्वपूर्ण तेजी का संकेत देता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) योजना का उद्देश्य नये स्व-रोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिये देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। शुरुआत के बाद से पीएमइजीपी के तहत महिला उद्यमियों की कुल दो लाख 59 हजार 339 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गयी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के एनएसएस 73वें दौर के अनुसार देश में अनुमानित रूप से कुल एक करोड़ 23 लाख 90 हजार 523 महिला स्वामित्व वाले एमएसएमइ हैं।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीटीएमएसइ) एमएसएमइ को दिये गये पांच सौ लाख रुपये तक के गारंटी मुक्त ऋण के लिए गारंटी कवर प्रदान करती है, जिससे वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम कम हो जाता है। अब तक सीजीटीएमएसइ ने 82.28 लाख इकाइयों को 5.75 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी दी है, जिससे 2.14 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने में मदद मिली है।

टिकाऊ उद्यमों के लिए वित्तीय अनुसंधान एवं नवाचार को 24 जनवरी 2024 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमइ (एनआइ-एमएसएमइ) में सिडबी और सीजीटीएमएसइ के संयुक्त वित्तीय समर्थन के साथ लांच किया गया था, ताकि एमएसइ की ऋण संबंधी साख को बढ़ाने और वित्तीय ज्ञान एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को लोकतांत्रिक बनाकर, एमएसइ इकोसिस्टम में वित्तीय अनुशासन एवं विवेक को विकसित कर एमएसइ के बीच प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देने से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य किया जा सके।

सीजीटीएमएसइ ने एमओएमएसएमइ के साथ मिलकर उद्योग जगत और ऋण देने वाले संस्थानों के बीच जागरूकता पैदा की है। सीजीटीएमएसइ फंडिंग की मंजूरी के बाद के वर्षों में लाभार्थियों ने अपने कारोबार के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी वृद्धि का अनुभव किया है। इसका एमएसइ क्षेत्र के छह प्रमुख क्षेत्रों यानी प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन, बाजार विकास, योजना की स्थिरता, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह इस बात से स्पष्ट है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीजीटीएमएसइ ने 30 जनवरी 2024 को 10 महीने की अवधि में 1.5 लाख करोड़ रुपये की गारंटी की एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पिछले साल की 1.04 लाख करोड़ रुपये की गारंटी की मंजूरी की तुलना में यह सीजीटीएमएसइ के संचालन में निरंतर व महत्वपूर्ण तेजी का संकेत देता है।

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) को लीन मैन्यूफैक्चरिंग के जरिये अपशिष्ट में कमी लाकर, बेहतर डिजाइन के लिए समर्थन प्रदान कर, बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाकर, शून्य दोष शून्य प्रभाव (जेडइडी) योजना को अपनाकर, डिजिटल एमएसएमइ के जरिये एमएसएमइ का डिजिटल सशक्तिकरण कर और देश भर में इनक्यूबेशन के जरिये विनिर्माण के साथ-साथ ज्ञान आधारित नवाचार एमएसएमइ में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाकर और व्यक्ति विशेष की अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा और समर्थन देकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमइ) के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है।

फिनराइज: टिकाऊ उद्यमों के लिए वित्तीय अनुसंधान एवं नवाचार को 24 जनवरी 2024 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमइ (एनआइ-एमएसएमइ) में सिडबी और सीजीटीएमएसइ के संयुक्त वित्तीय समर्थन के साथ लांच किया गया था, ताकि एमएसइ की ऋण संबंधी साख को बढ़ाने और वित्तीय ज्ञान एवं सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को लोकतांत्रिक बनाकर, एमएसइ इकोसिस्टम में वित्तीय अनुशासन एवं विवेक को विकसित कर एमएसइ के बीच प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देने से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य किया जा सके।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा संचालित अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक विशेष योजना भारत सरकार के एमएसएमइ मंत्री नारायण राणे द्वारा 14 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश में चार प्रौद्योगिकी केंद्रों के उद्घाटन के दौरान शुरू की गयी। यह योजना सूक्ष्म/नैनो उद्यमों को 20.0 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करेगी और इसका उद्देश्य क्रेडिट जोखिम धारणा को कम करना है और ऋण देने वाले संस्थानों को आइएमइ को ऋण देने के लिए प्रेरित करना है। जैसे-जैसे यह पहल आगे बढ़ेगी, इससे न सिर्फ व्यक्तिगत उद्यमियों को सशक्त बनाने की उम्मीद है, बल्कि एक समावेशी, गतिशील और सुदृढ़ आर्थिक इकोसिस्टम भी तैयार होगा।

इसके अलावा सरकार ने देश में एमएसएमइ के लिए ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने हेतु वर्तमान में जारी योजनाओं सहित कई उपाय किये हैं। उनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आइएमइ) को एमएसएमइ के औपचारिक दायरे में लाने हेतु 11 जनवरी 2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से खुदरा और थोक व्यापारियों को 02 जुलाई 2021 से एमएसएमइ के रूप में शामिल करना।
- एमएसएमइ की हैसियत में ऊपर की ओर बदलाव होने की स्थिति में गैर-कर लाभों को तीन साल के लिए बढ़ाया गया।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से विविध फाइनेंसरों के जरिये सरकारी विभागों एवं पीएसयू सहित कॉरपोरेट तथा अन्य खरीदारों से एमएसएमइ के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने हेतु ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरइडीएस)।
- आत्मनिर्भर भारत कोष के जरिये 50 हजार करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश। इस योजना में भारत सरकार की ओर से 10 हजार करोड़ रुपये के कोष का प्रावधान है।
- पांच वर्षों में छह हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमइ के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने (आरएएमपी) की योजना का शुभारंभ।

भारत सरकार का एमएसएमइ मंत्रालय गारंटी मुक्त ऋण की सहायता प्रदान करने जैसी रचनात्मक योजनाएं शुरू करके एमएसइ की विकास यात्रा में उनका साथ देने के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ है और साथ ही अनगिनत उद्यमियों के सपनों को सशक्त बनाने एवं उनके प्रयासों का समर्थन करने की आकांक्षा रखने वाली विभिन्न रणनीतियों व क्षमताओं को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है।

(लेखिका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमइ (एनआइ-एमएसएमइ), हैदराबाद की संकाय सदस्य हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

राजधानी की खबरें

राज्यपाल ने एम्स भुवनेश्वर में चियास्मा 2024 का उद्घाटन किया

इसे देश का शीर्ष संस्थान बनाने की कामना करते हैं: रघुवर दास

देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के सैकड़ों छात्र उत्सव के भव्य आयोजन के गवाह बने

आजाद सिपाही संवाददाता

भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर ने कोविड़ महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। विकासशील भारत की सच्ची भावना को साकार करने में देश के युवा सबसे आगे हैं। इसके अलावा देश का युवा नागरिक स्टार्ट-अप, खेलो इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री की कई अन्य युवा केंद्रित पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह बात ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने मंगलवार को एम्स भुवनेश्वर में छात्र उत्सव चियास्मा 2024 के उद्घाटन के अवसर पर कही। इस राष्ट्रीय संस्थान की अपनी पहली यात्रा में राज्यपाल ने एम्स भुवनेश्वर को देश का शीर्ष चिकित्सा संस्थान बनाने की कामना की। उन्होंने चियास्मा में खेल, संस्कृति और साहित्य जैसे आयोजनों को शामिल किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यकारी निदेशक डॉ आशुतोष विश्वास ने राज्यपाल का स्वागत किया और विभिन्न सफल उपलब्धियों के बारे में बताया। डॉ विश्वास ने अन्य संस्थानों से आये छात्रों का भी स्वागत किया और चार दिवसीय उत्सव की बड़ी सफलता की कामना की। अन्य लोगों में डीन डॉ पीआर महापात्रा, एमएस डॉ दिलीप परिदा, रजिस्ट्रार डॉ देबप्रिया बंद्योपाध्याय, डीडीए रस्मी रंजन सेठी, छात्र संघ अध्यक्ष दिव्यज्योति पांडा ने राज्यपाल के साथ मंच साझा किया। एम्स भुवनेश्वर के छात्र-संघ द्वारा आयोजित पूर्वी भारत के सबसे बड़े कॉलेज उत्सवों में से तीन मार्च तक जारी रहेगा। चियास्मा उन मेगा सितारों के समृद्ध इतिहास का भी दावा करता है, जिन्होंने मंच पर आग लगा दी है और इस साल दो मार्च की शाम को बॉलीवुड सनसनी मोहित चौहान और 29 फरवरी (गुरुवार) को सबसे बुद्धिमान अभिषेक उपमन्यु पूरी तरह तैयार हैं।

श्याम मित्र मंडल का पांच दिवसीय स्थापना दिवस 17 मार्च से

18 मार्च को मारवाड़ी भवन से भव्य शोभायात्रा निकलेगी

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। श्री श्याम मित्र मंडल का स्थापना दिवस हरमू रोड के श्री श्याम मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। इस पंच दिवसीय विराट महोत्सव की सभी तैयारियां को लेकर प्रतिदिन मंडल के अध्यक्ष सुरेश सरावगी के नेतृत्व में सभी तैयारियां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। महोत्सव के लिए मंडल के मंत्री गौरव अग्रवाल मोनू को महोत्सव का संयोजक और पंकज गाड़ोदिया आदित्य लोहिया को उप संयोजक मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर प्रथम दिवस 17 मार्च रविवार को श्री गणेश पूजन हवन यज्ञ ध्वज स्थापना करके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। महोत्सव संयोजक गौरव अग्रवाल मोनू ने बताया कि 18 मार्च को मारवाड़ी भवन से भव्य शोभायात्रा निकाली जायेगी, जिसमें खाटू नरेश के पवित्र ध्वज निशान लेकर बड़ी संख्या में भक्तजन शोभायात्रा में चलेंगे।

सीयूजे के दीक्षांत समारोह में आज शामिल होंगी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति 11 बजे विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 फरवरी को रांची आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर चार आइपीएस, 25 डीएसपी सहित 2000 फोर्स की तैनाती कार्यक्रम स्थल सहित पूरे रूट पर की गयी है। मंगलवार को पुलिस के वरीय अधिकारियों के की ओर से राष्ट्रपति के कारकेड का रिहर्सल किया गया। रांची एयरपोर्ट से लेकर कारकेड मनातू स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। इसका जायजा वरीय अधिकारियों ने लिया और जरूरी निर्देश दिये। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात अफसरों और जवानों को ब्रीफ किया गया। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात जवानों को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहें। इस रूट लाइन से राष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा, वहां पूरी तरह से पुलिसकर्मी को सतर्क रहने को कहा गया है। काफिले के रास्ते में पड़ने वाले सभी ऊंची इमारतों पर पुलिस के स्नाइपर जवानों को तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति बुधवार को 11 बजे विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी और फिर चार बजे वापस ओड़िशा रवाना हो जायेगी। राष्ट्रपति रांची के सीयूजे के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आ रही हैं।

राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक के साथ बैठक

आजाद सिपाही संवाददाता

हाजीपुर। राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में रेलवे से संबद्ध स्थायी संसदीय समिति और पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक तरूण प्रकाश के बीच पटना में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सांसद कौशलेंद्र कुमार, सांसद नरहरि अमीन, सांसद अजित कुमार भुइंया, सांसद खीरू महतो और सांसद डॉ प्रशांत नंदा भी उपस्थित थे। बैठक में पूर्व मध्य रेल में यात्री सुविधा के विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण

विषयों पर चर्चा की की गयी। बैठक के दौरान पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं जैसे फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफार्मों का उच्चीकरण, प्लेटफार्म शेड का निर्माण, स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने सहित अन्य कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में रेलवे के डिजिटलीकरण पर विशेष रूप से बल दिया गया।

तसर उत्पादन में झारखंड नंबर-1, एक लाख लोगों के लिए प्रशस्त होगा रोजगार का मार्ग

उद्योग विभाग
बजट : 484.87 करोड़ रुपये

भवन निर्माण विभाग
बजट : 883.23 करोड़ रुपये

नगर विकास व आवास
बजट : 3429.86 करोड़ रुपये

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ऐसा राज्य है, जहां औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं हैं। राज्य सरकार अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में विभिन्न नयी औद्योगिक नीतियों का सूत्रण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभाग से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत 6,400 लोगों को योजनांतर्गत स्वरोजगार से लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिसमें लगभग 51 हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत निवेशकों को सभी प्रकार की आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है। विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत इस वर्ष 20,710 करोड़ का निवेश लाया जायेगा, जिससे यहां केएक लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। झारखंड तसर उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 872 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। राज्य वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,000 मीट्रिक टन तसर रेशम उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। 2024-25 में 144 बुनकरों को बुनाई में एकवर्षीय उन्नत प्रशिक्षण, हस्तशिल्प के विभिन्न ट्रेडों में 270 शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है।

अमृत मिशन के तहत आठ जलापूर्ति योजना का निर्माण जल्द

रांची (आजाद सिपाही)। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत अब तक झारखंड राज्य के लिए 2 लाख 11 हजार आवासीय इकाई स्वीकृत है, जिसमें से 1 लाख 14 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके है। 78,032 इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अमृत 20 मिशन अतर्गत 8 जलापूर्ति योजनाओं यबा कपाली, जामताड़ा, गुमला, बरहरवा, हहिरगंज, छत्तरपुर श्रीवशीधरनगर, लोहरदगा का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) को सहायता के तहत 49 नगर निकायों में सर्वेक्षण के माध्यम से कुल 66,090 पथ विक्रेताओं को चिह्नित कर 19 को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब तक कुल 46,605 पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र दिया जा चुका है। नमामि गंगे योजना अंतर्गत राज्य में 300 किमी तक बहनेवाली गंगा की सहायक नदी दामोदर को नमामि गंगे परियोजना में शामिल करते हुए केंद्र सरकार द्वारा फुसरो, रामगढ़ एवं धनबाद शहर के लिए परियोजना की स्वीकृति दी गयी है।

नये विधायक आवास का निर्माण नवंबर तक

राजधानी में विधायकों को समुचित आवासन की सुविधा प्रदान करने के लिए 70 आवासों के निर्माण के लिए 203.21 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे नवंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भवन निर्माण के लिए 883.23 करोड़ रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

ओरमांझी प्रखंड प्रमुख ने हासिल किया विश्वासमत

ओरमांझी (आजाद सिपाही)। प्रखंड प्रमुख अनुपमा देवी के खिलाफ मंगलवार को रांची अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि सदस्यों की संख्या कम होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। जिस कारण अनुपमा देवी विश्वास मत हासिल करने में सफल रहीं और एक बार फिर से ओरमांझी प्रखंड प्रमुख पद पर अपना कब्जा जमाया। इसकी जानकारी होते ही ओरमांझी प्रखंड के भाजपा समर्थकों व ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ शास्त्री चौक से विजय जुलूस निकाल कर खुशी मनायी। मौके पर जिप सदस्य सरीता देवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष, पंसस ललिता देवी, उपमुखिया संतोष गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि राजेश गुप्ता, विनोद गुप्ता, शशी मेहता, विक्रांत तिवारी, अलखनाथ महतो, आनंद महतो, राजकिशोर साहू आदि मौजूद थे।

कार्यालय , वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल

सूचना

एतद द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद WP(C) No. 5150/2023 अमित कुमार वनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची द्वारा दिनांक 15.01.2024 को पारित आदेश के आलोक में अमित कुमार पिता डॉ0 कल्प नाथ पाण्डेय, निवास स्थान आनन्दपुरी पो0 हजारीबाग थाना हजारीबाग सदर जिला हजारीबाग को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11.05.2015 को जोरदाग वन से जी0एफ0 वाद संख्या– 223/2015 में जप्त ट्रक निबंधन संख्या JH-02R-9666 को आप वाहन का ऑनर बुक / पहचान पत्र के साथ वन क्षेत्र पदाधिकारी, बडकागांव प्रक्षेत्र कार्यालय से सर्म्पक कर वाहन प्राप्त कर लें।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

PR 320494 (Forest, Environment and Climate Changes)23-24*D

नैतिन जिम्मेदारियों के प्रति तेजी से बढ़ रही उदासीनता: डॉ सचि कुमारी

बेड़ो (आजाद सिपाही)। छोटानागपुर सांस्कृतिक संघ के तत्वावधान में प्रखंड के पंचायतों में बाल संरक्षण एवं विकास पर विगत 20 फरवरी से चलायी जा रही सात दिवसीय कार्यशाला का मंगलवार को समापन हुआ। जिसमें कुल 240 अभिभावकों ने भाग लिया। साथ ही विभिन्न पंचायतों से आये अभिभावक समूह के सदस्यों को अभिभावकीय कौशल, किशोर न्याय अधिनियम 2015, पोक्सो कानून 2012, श्रम कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम व डिजिटल सुरक्षा के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित सदस्यों को बालकों की देखभाल संबंधी कौशल के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए समुदाय द्वारा अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपायों को ज्यादा कारगर माना गया। उच्च शिक्षा में छीजन की दर बढ़ रही है। वहीं बच्चे स्मार्ट फोन व बाइक के लिए मजदूरी करना पसंद कर रहे हैं। संस्था की सचिव डॉ सचि कुमारी ने पैनल चर्चा के दौरान कहा कि बदलते परिवेश में भौतिक लोलूपता के कारण नैतिक जिम्मेवारियों के प्रति उदासीनता तेजी से बढ़ रही है। इस समय विशेष कौशल एवं जागरूकता बच्चों के परवरिश के लिए आवश्यक है। कानून एवं योजनायें भी इस बात को मजबूत बनाती हैं केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2023 से देश भर में लागु मिशन वात्सल्य योजना शीर्ष से लेकर गांव तक ढांचागत व्यवस्था को मजबूत करेगी। साथ ही सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं को धरातल पर मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाने की बात कही। मौके पर मोनिका गाड़ी, अर्चना आइंद, रामप्रकाश ठाकुर, नैंसी जर्मिना तिर्की, करमी कुमारी व जुली कुमारी मौजूद थीं।

दिव्यांग जन स्नेह के सबसे अधिक हकदार: बीडीओ

बेड़ो (आजाद सिपाही)। प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ संग्राम मुर्मू की ओर से त्वरित कार्यवाही करते दिव्यांग को एक ही दिन में ट्राई साइकिल दिया गया। मुरतो पंचायत के डाड़ कंडरिया गांव के रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति बसंत उरांव ने अपनी समस्या रखते हुए ट्राई साइकिल के लिए आवेदन दिया था। बीडीओ ने दिव्यांग की स्थिति को देखते हुए साइकिल उपलब्ध करा दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति समाज में हमारे स्नेह और प्रेम की सबसे अधिक जरूरतमंद होते हैं। समाज की सहायता प्राप्त करने का सबसे ज्यादा हकदार दिव्यांग व्यक्ति ही होते हैं। जहां तक संभव हो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। वहीं, ट्राई साइकिल मिलने पर बसंत ने खुश जाहिर की। बताया ट्राई साइकिल न होने से कहीं भी आनेजाने में असुविधा होती थी। अब उसे अपने रोजमर्रा के कामकाज करने में सहूलियत होगी।

राज्यसभा सांसद ने अधिकारियों को लिखा पत्र

विनोद बिहारी महतो चौक को विकसित किया जाये : सांसद

आजाद सिपाही संवाददाता

अनगड़ा। विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति के सदस्यों ने विगत दिनों राज्यसभा सांसद से मुलाकात कर विनोद बिहारी महतो चौक चतरा-टाटीसिलवे में प्रस्तावित उनकी आदमकद प्रतिमा निर्माण के मद्देनजर चौक को विकसित करने की मांग की थी। सांसद को अवगत कराया गया था कि वर्तमान समय में रांची-मुरी मार्ग पर फोरलेन को लेकर चौड़ीकरण कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में चौक को इस ढंग से व्यवस्थित व परिवर्तित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को आवगमन में किसी तरह की असुविधा ना हो। यह भी बताया कि यह मोड़ राहे सहित अनगड़ा प्रखण्ड के कई पंचायतों को रांची शहर से सीधे जोड़ता है। जिस कारण यहां हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। चौड़ीकरण कार्य के दौरान इसे चौराहा के रूप में परिवर्तित कर दिए जाने से प्रतिमा निर्माण के लिए पर्याप्त जगह मिलने के साथ जाम की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लेते हुए सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने मंगलवार को पथ निर्माण सचिव, रांची डीसी और बिहार के पटना बीएसआईडीसी प्रबंध निदेशक को पत्र प्रषित कर ग्रामीणों के उचित मांगों पर त्वरित कार्रवाई शुरू कराने का आग्रह किया। कहा कि रांची जिला अंतर्गत प्रखंड के रांची-पुरूलिया पथ पर चतरा पंचायत के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित स्व विनोद बिहारी महतो चौक कई पंचायतों को रांची शहर से जोड़ने का मुख्य रास्ता है। वर्तमान में इस चौक पर भारी संख्या में वाहनों के आवागमन से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। वहीं ग्रामीण यहां झारखंड के पितामह स्व विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय ले चुके हैं। भविष्य में ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए स्व विनोद बिहारी महतो चौक का व्यवस्थित ढंग से पुनः निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है।

सांसद को ज्ञापन सौंपते समिति के सदस्य।

e- Procurement Cell
Office of The Executive Engineer,
Building Construction Department, Building Division, Ramgarh.

अति अल्पकालीन ई–प्रोक्योरमेंट नोटिस

ई–टेन्डर रेफरेन्स नं०– BCD/EE/RAMGARH/ 24 /2023-24 दिनांकः– 27.02.2024

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू०)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	दुलमी प्रखण्ड के पंचायत सिरू में उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिरू में चाहरदिवारी निर्माण।	Rs. 60,78,100.00	6 (Six) Months
2	माण्डू प्रखण्ड के पंचायत हेसागढ़ा के ग्राम केरीबन्दा छापर टोला में छापर टोला मैडाय के पास दिनेष टुडू के घर तक गार्डवाल का निर्माण कार्य	Rs. 71,16,700.00	6 (Six) Months
3	पतरातू प्रखण्ड के पतरातू पंचायत के बाबाबुचा बांध का सुन्दरीकरण एवं सामुदायिक भवन निर्माण।	Rs. 99,82,900.00	6 (Six) Months
i	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	02.03.2024	
ii	वेबसाईट में निविदा डालने की अंतिम तिथि एवं समय	06-03-2024 को अपराह्न 3.00 बजे	
iii	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	07-03-2024 को अपराह्न 3.00 बजे	
iv	निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	e- Procurement Cell Office of The Executive Engineer, Building Construction Department, Building Division, Ramgarh.	
v	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या	9110983022	
vi	ई–प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या	9340378587	

- किसी भी प्रकार का बदलाव http:// Jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।
- अन्य किसी भी प्रकार की सूचना http:// Jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

note: UCAN Registration is mandatory for the bidders.

Nodal Officer
e- Procurement Cell
Office of The Executive Engineer,
Building Construction Department,
Building Division, Ramgarh.

PR 320582 Building(23-24).D

13 सूत्री मांगों को लेकर नामकुम प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव

नामकुम (आजाद सिपाही)। आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को 13 सूत्री मांगों को लेकर नामकुम प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव किया गया। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों महिला एवं पुरुष हरवे-हथियार के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष प्रकाश लकड़ा एवं मंच संचालन 52 पडहा अध्यक्ष प्रदीप तिर्की ने किया। इस दौरान नामकुम बीडीओ और सीओ को मांग पत्र सौपते हुए प्रकाश लकड़ा ने अबुआ आवास योजना में गलत तरीके से आवास आवंटन करने का आरोप लगाया। साथ ही अंचल कार्यालय में जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र बनाने में सुधार करने, पंजी 2 में ऑनलाईन प्लॉट नंबर चढ़ाने, राशन कार्ड में ऑनलाईन नाम जोड़ने आदि की मांग रखी। इस पर बीडीओ ने सभी समस्याओं को 15 दिनों के अंदर सुधार करने की बात कही। मौके पर प्रदीप तिर्की, नन्हे कच्छप, मुन्ना बडाईक, रामअवतार केरकेट्टा, रामाधार सिंह, बिपिन टोप्पो आदि मौजूद थे।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, रामगढ़

अतिअल्पकालीन निविदा आंमत्रण सूचना सं0–23/2023–24

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पदनाम :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल रामगढ़।
2. परिमाण विपत्र निर्गत की तिथि एवं समय :– दिनांक 06/03/2024 को अपराह्न 1:00 बजे तक ।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक 07/03/2024 को अपराह्न 3:00 बजे तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 07/03/2024 को अपराह्न 3:30 बजे।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :– (1) अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल हजारीबाग, (2) कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, रामगढ।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान :– कण्डिका 5, में वर्णित (2)
7. कार्यो का विवरण :–

क्र0 स0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मुल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	प्रखण्ड माण्डू में नव प्राथमिक विद्यालय जमुनिया टोला में जर्जर विद्यालय भवन का मरम्मती कार्ययोजना।	15,50,400/-	31,500/-	5,000/-	3 माह
2	प्रखण्ड गोला के पंचायत उपरबरगा ग्राम अंवराडीह परस बेदिया के घर से बिलेश्वर मांझी के टांड तक गार्डवाल निर्माण। 500फीट	6,15,200/-	13,000/-	1,250/-	2 माह
3	प्रखण्ड गोला के पंचायत बेटुलकलां उप स्वास्थ्य केन्द्र के प्रांगण मे पेवर ब्लॉक निर्माण।	7,28,650/-	15,000/-	1,250/-	2 माह
4	Repairing & Renovation at DTC, Ramgarh	7,83,600/-	16,000/-	1,250/-	2 माह
5	रामगढ़ नगर परिषद् वार्ड संख्या 18 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय चैनगड़ा में चाहरदिवारी का निर्माण।	19,68,200/-	40,000/-	5,000/-	3 माह

* निविदा की शर्तें एवं अन्य सूचनाएँ www.jharkhandtenders.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल ,रामगढ़।

PR.NO.320581 Building(23-24):D

लापुंग साईं मंदिर में पर्यावरण मंच की दो दिवसीय बैठक का शुभारंभ

पर्यावरण व नैसर्गिक संपदा को कायम रखना सभी भारतीयों का परम कर्तव्य : रवींद्र हेमटे

आजाद सिपाही संवाददाता

बेड़ो। पर्यावरण व नैसर्गिक संपदा को कायम रखना हम भारतीय नागरिकों का परम कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण के बगैर पृथ्वी के जीवों के जीवन को अक्षुण्ण बनाए रखना असंभव है। उक्त बातें अखिल भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री रवींद्र हेमटे ने कहीं। वे मंगलवार को लापुंग प्रखंड के सरसा ग्राम स्थित साईं मंदिर के परिसर में पर्यावरण मंच (भारतीय मजदूर संघ) के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। पर्यावरण प्रेमियों ने संयुक्त रूप से भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बैठक में हिमटे ने कहा कि पेड़-पौधे हमें प्राण वायु के साथ ही फूल, फल और ईंधन देते हैं। यह मिट्टी के संरक्षण व प्रदुषण नियंत्रण में अमूल्य भूमिका निभाते हैं। उन्होंने पृथ्वी और पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाने वाली चीजों को छोड़ने की अपील की। साथ ही प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने पर बल दिया। उन्होंने नदियों व जलाशयों के सूखने पर चिंता जाहिर की। और गंभीरता से चिंतन, मनन, अध्ययन और लेखन करने की बात कही। उन्होंने भविष्य में पानी के विषय को लेकर ही विश्व युद्ध होने की चिंता और संभावना जताया। बैठक में अखिल भारतीय संयोजक लक्ष्मण चंद्रा, झारखंड प्रदेश संयोजक प्रशांत बलथरिया, धर्मदास शुक्ला, राजीव रंजन सिंह, ब्रजेश कुमार, एनामूल हक, विश्वजीत गुहा, कुशला राम ढोकिया, लखन लाल चौधरी, सरवन भट्ट, सुरभि श्वाईन व संपत सेट्टी आदि ने भी अपने-अपने विचार रखे। वहीं, सांई मंदिर के व्यवस्थापक मनोज उरांव ने रवींद्र हेमटे को सांई मंदिर का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। बैठक का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन झारखंड के संयोजक प्रशांत बलथरिया ने किया। इस मौके पर राष्ट्रव्यापी पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति तथा जलवायु परिवर्तन पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के प्रतिनिधियों ने योगदान दिया।

पर्यावरण मंच की बैठक में उपस्थित गणमान्य लोग।

अबुआ आवास योजना में अमियमितता को लेकर ज्ञापन सौंपा

पिस्कानगड़ी (आजाद सिपाही)। नगड़ी प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सहाबीर लोहरा के नेतृत्व में मंगलवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने बीडीओ दीपाली भगत को ज्ञापन सौंपा। जिसमें आरोप लगाया गया कि नगड़ी प्रखंड में अबुआ आवास योजना में हो रही अनियमितता एवं गड़बड़ी को सुधार कर गरीब असहाय और मिट्टी का घर वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाए। जिनको पहले आवास का लाभ मिल चुका है और जिनके पक्के मकान हैं वैसे लोगों को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। कोई गरीब अबुवा आवास योजना से वंचित न रहे। मांग पुरी नहीं होने पर नगड़ी प्रखंड कांग्रेस की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सहाबीर लोहरा, मंडल अध्यक्ष अख्तर अंसारी, रोशन कुजूर, धरमु नायक, एनामूल अंसारी, माहिर अंसारी, मंजूर अंसारी, विनीता एक्का, विलियम तिर्की, प्रेमचंद उरांव आदि उपस्थित थे।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, राँची
(पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य शाखा)
Email - dsoranchigov@gmail.com

अतिअल्पकालीन आमंत्रण सूचना "इच्छा की अभिव्यक्ति"

Very Short Term Inviting Notice "Expression of Intrest"

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राँची जिलान्तर्गत संचालित आवासीय बैडमिंटन (बालक) क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इण्डोर स्टेडियम, खेलगाँव, होटवार, राँची में "फिट इण्डिया योजना" के तहत जिम अधिष्ठापन किया जाना है। इस निमित इच्छुक निर्माता/प्राधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्ता से "इच्छा की अभिव्यक्ति" अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/कम्पनी/संस्थान/फर्म/उत्पादक एवं उनके प्रतिनिधि आदि से दिनांक 05/03/2024 के पूर्वा०/अप० 11:30 बजे तक "इच्छा की अभिव्यक्ति" अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

"इच्छा की अभिव्यक्ति" दिनांक– 05/03/2024 को पूर्वाह्नः– 11:30 बजे तक कचहरी रोड स्थित विकास भवन के प्रथम तल में उप विकास आयुक्त, राँची के कार्यालय में (जिला खेल शाखा) में मुहरबन्द "इच्छा की अभिव्यक्ति" स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक, स्वयं प्रस्तावक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर निर्धारित तिथि व समय के अन्दर ऊपर दिये गए पते पर जमा किया जायेगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात किसी भी "इच्छा की अभिव्यक्ति" को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निविदादाता द्वारा तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड की अलग–अलग सीलबन्द लिफाफे को एक बड़े सीलबन्द लिफाफे में तथा अलग से जिम से संबंधित सामग्रियों/उपकरणों के नमूनों (ढोने लायक) का एक सीलबंद पैकेट में समर्पित किया जायेगा तथा ऐसे नमूने जिसे ढोया नहीं जा सकता, वैसे नमूनों का विवरणिका Brochure (रंगीन फोटोग्राफ्स सहित) एवं विडियों हेतु 1 पेन ड्राईव समर्पित किया जायेगा।

सर्वप्रथम निविदा –सह– क्रय समिति द्वारा प्रस्तावकों के नमूनों की गुणवत्ता की जाँच प्रस्तावकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक– 05/03/2024 को अपराह्नः– 04:00 बजे कचहरी रोड स्थित विकास भवन के प्रथम तल में उप विकास आयुक्त, राँची के समक्ष खोला/देखा जाएगा। जिन प्रस्तावकों द्वारा समर्पित जिम सामग्रियों/उपकरणों के नमूने उच्च गुणवत्ता (ब्रांडेड) वाली होगी उनका ही तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव निविदा –सह– क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। (केवल तकनीकी बीड के सफल प्रस्तावकों के वित्तीय बीड खोले जायेंगे)

नोटः– "इच्छा की अभिव्यक्ति" समर्पित करने से संबंधित विस्तृत शर्त्ते एवं दिशा–निर्देश राँची जिला के अधिकारिक बेवसाईट www.ranchi.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला खेल पदाधिकारी, राँची | निदेशक, डी०आर०डी०,राँची | उप विकास आयुक्त, राँची

PR 320562 District(23-24).D

झारखंड के बजट को भाजपा ने बताया जुमला

रूपेश अग्रवाल

लातेहार (आजाद सिपाही)। झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसने युवाओं को निराश किया है सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मेहताब आलम ने कहा कि झामुमो-कांग्रेस-राजद कुशासन के अंतिम बजट में विफल हेमन्त सरकार भाग-2 ने पूरे प्रदेश को निराश किया है। यह बजट कमजोर नेतृत्व, असमर्थ-असक्षम सरकार का आईना है। झारखंड राज्य को बेरोजगार राज्य और बीमारू राज्य की ओर ले जाता हुआ यह बजट युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जेपीएससी नियुक्ति की सीबीआई जांच एवं जे०एस०सी०सी का पेपर लीक मामले में सरकार ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, झारखंड की खनिज संपदाओं को लूटा जा रहा है इसके रोकथाम के लिए बजट में किसी भी प्रकार बजट में घोषणा नहीं की गई है, महिलाओं के लिए इस बजट में किसी प्रकार की विशेष योजना नहीं की गई है जब के अन्य भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के लिए विशेष सुविधा हर बजट में दी जा रही है। अल्पसंख्यक समाज को इस बजट में पूरी तरह से ठगा है, किसी प्रकार की विशेष योजना अल्पसंख्यक समाज के लिए यह बजट में नहीं है, जबकि झोली भर भर के अल्पसंख्यक समाज नें वोट महागठबंधन को दिया है, निश्चित ही आने वाले चुनाव में अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह से भाजपा का साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठायेंगे

बजट को किसी ने सराहा, तो किसी ने चुनावी कहा

आजाद सिपाही संवाददाता

गुमला। राज्य सरकार के बजट प्रस्तुत करने के साथ ही बजट पर राय आने शुरू हो गए। जहां इंडिया गठबंधन से संबंधित पार्टियों के नेताओं ने इसे लाभकारी, किसानों का हितैषी और आमजनों को राहत पहुंचाने वाला बजट बताया वहीं भाजपा के लोगों ने इसे लोक लुभावन, और चुनावी बजट की संज्ञा दी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के जॉइंट स्टेट कोडिनेटर फिरोज आलम ने बजट के बारे में कहा कि वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किया गया राज्य का बजट संतुलित और सराहनीय है। वित्त मंत्री ने राज्य को कई बड़ी सौगातों की घोषणाएं की है जिससे राज्य का सर्वांगीण विकास होना तय है। सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जनकल्याणकारी बजट बनाया है जो आगामी दिनों में झारखंड को विकास की ओर अग्रसर करेगा। वहीं कांग्रेस की अल्पसंख्यक

चैतु उरांव

कुमुदनी प्रभावती

फिरोज आलम

आनंद गुप्ता

कलीम अख्तर कल्लन

शिव प्रसाद साहू

विभाग की महासचिव कुमुदिनी प्रभावती ने कहा कि राज्य के गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों अल्पसंख्यकों, महिला, युवा, बुजुर्ग, मजदूर किसानों की गांव और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला संतुलित बजट है। विशेष कर महिलाओं पर बजट में पूरा ध्यान दिया गया है। सरकार ने गर्भवती महिलाओं को मातृ किट देने की घोषणा कर महिला विकास व उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता साबित किया है। कांग्रेस ज़िला अध्यक्ष चैतू उरांव ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने राज्य के किसानों का भी खास ख्याल रखा है और ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख कर दिया गया है जो किसानों के लिए वरदान साबित होगा। सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली प्रदान करने का ऐलान कर राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत दी है। । इसके अतिरिक्त भी कई सारी योजनाओं की सौगात राज्य सरकार ने दी है जो सराहनीय है। झामुमो के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष कलीम अख़्तर कल्लन ने कहा है कि अत्यंत सुझबुझ के साथ बनाया गया बजट है। इस बजट में गरीबों के साथ-साथ आम लोगों को भी राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मूलतः किसानो को कई प्रकार की राहते दी गई है। साथ ही महिलाओं का ख्याल रखा गया है। इधर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवप्रसाद साहू का कहना है कि इस बजट से झारखंड का कल्याण नहीं होने वाला। इस इंडिया गठबंधन वाली चंपई सरकार महिलाओं को छलने का काम किया है। जहां रघुवर दास सरकार में महिलाओं की रजिस्ट्री 1 रुपए में की जाती थी उसे झामुमो वाली सरकार ने बंद करके महिला विरोधी कार्य किया है। अब बजट में हल्के-फुल्के प्रावधान करके महिलाओं को लुभाना चाहती है। वहीं किसानों को मिलने वाले भत्ते को खत्म करके किसानो की कर्ज माफी का वादा करने वाली सरकार खुद ही साबित कर रही है कि वह किसान विरोधी है। इस बजट से आम आदमी का कोई लेना देना नहीं। यह बजट चुनावी बजट है। वही आजसू जिला उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता कहते हैं कि यह बजट चुनाव के पूर्व किए जाने वाले कोरे वादों के जैसा है। इससे राज्य का उत्थान होने की उम्मीद करना फिजूल है।

आरके मल्लिक मुख्यालय के एडीजीपी बने

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। झारखंड के 23 आइपीएस अधिकारियों का सरकार ने तबादला किया है और एक को अतिरिक्त प्रभार दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को जारी कर दी है।

कौन कहां गये

1) एडीजी वायरलेस के पद पर पदस्थापित आरके मलिक को एडीजी मुख्यालय के पद पर पद पदस्थापित किया गया। आरके मल्लिक एडीजी वायरलेस के अतिरिक्त प्रभार पर भी रहेंगे।

2) आइजी प्रोविजन के पद पर पदस्थापित प्रभात कुमार को आइजी स्पेशल ब्रांच के पद पर पदस्थापित किया गया है।

3) आइजी एसीबी के पद पर पदस्थापित पंकज कंबोज को आइजी प्रोविजन के पद पर पदस्थापित किया गया है।

4) जोनल आइजी पलामू के पद पर पद स्थापित राजकुमार लकड़ा को जैप आइजी के पद पर

पदस्थापित किया गया है।

5) नरेंद्र कुमार सिंह को पलामू जोनल आइजी के पद पर पदस्थापित किया गया। नरेंद्र कुमार सिंह रेल आइजी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

6) कोल्हान डीआइजी के पद पर पदस्थापित अजय लिंडा को डीआइजी होमगार्ड के पद पर पदस्थापित किया गया।

7) डीआइजी स्पेशल ब्रांच के पद पर पदस्थापित मनोज रतन चौथे को डीआइजी कोल्हान के पद पर पदस्थापित किया गया।

8) डीआइजी रेल के पद पर पद पदस्थापित कार्तिक एस को डीआइजी स्पेशल ब्रांच के पद पर पदस्थापित किया गया।

9) डीआइजी एसआइबी के पद पर पदस्थापित शैलेंद्र प्रसाद बरनवाल को डीआइजी एसीबी के पद पर पदस्थापित किया गया।

10) डीआइजी होमगार्ड के पद पर पदस्थापित वाइएस रमेश को डीआइजी बजट के पद पर पदस्थापित किया गया।

11) सुमित कुमार अग्रवाल को रांची ट्रैफिक एसपी के पद पर स्थापित किया गया।

12) प्रवीन पुष्कर को जमशेदपुर रेल एसपी के पद पर पदस्थापित किया गया।

13) शंभू कुमार सिंह को गुमला एसपी के पद पर पदस्थापित किया गया।

14) गुमला एसपी के पद पर पदस्थापित हरविंदर सिंह को एसपी वायरलेस के पद पर पद पदस्थापित किया गया।

15) आनंद प्रकाश को जैप 6 जमशेदपुर का कमांडेंट बनाया गया।

16) मूमल राजपुरोहित को स्पेशल ब्रांच का एसपी बनाया गया।

17) रेल एसपी जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित ऋषभ झा को एटीएस एसपी के पद पर पद स्थापित किया गया।

18) लातेहार एसपी के पद पर पदस्थापित अंजनी अंजन को रांची ग्रामीण एसपी के पद पर पदस्थापित किया गया।

19) सरायकेला एसपी के पद पर पदस्थापित डॉक्टर विमल कुमार को रामगढ़ एसपी के पद पर पद स्थापित किया गया।

20) चतरा एसपी के पद पर पदस्थापित राकेश रंजन को जैप 1का कमांडेंट बनाया गया।

21) रांची ग्रामीण एसपी के पद पर पदस्थापित मनीष टोप्पो को सरायकेला एसपी बनाया गया।

22) रामगढ़ एसपी के पद पर पदस्थापित पीयूष पांडे को लातेहार का एसपी बनाया गया।

23) विकास कुमार पांडे को चतरा का एसपी बनाया गया।

24) जेएपीटी पदमा में पदस्थापित चंदन कुमार झा अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक झारखंड पुलिस अकादमी का प्रभार में रहेंगे।

जेट्रोफा का सूखा बीज खाने से दो छात्र की स्थिति बिगड़ी

गुमला (आजाद सिपाही)। सदर थाना क्षेत्र के टोटो नवा टोली निवासी छात्र 9 वर्षीय विपिन उरांव पिता सुधीर उरांव और 12 वर्षीय मंगल उरांव पिता बिरसा उरांव सोमवार को विद्यालय छुट्टी होने के बाद मवेशी चराने जंगल की ओर गए थे। इसी क्रम में जेट्रोफा का सुखा बीज का चार-पांच दाना खा गए। इसके बाद दोनों को नशा हो गया। वही दोनों उल्टी भी करने लगे। आसपास मवेशी चरा रहे ग्रामीण दोनों को लेकर उनके घर पहुंचाया। इसके बाद दोनों को सोमवार की रात सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां विपिन उरांव की स्थिति खराब होने लगी। जबकि मंगल को इलाज के उपरांत उसे घर भेज दिया गया जबकि विपिन का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

झारखंड सरकार का बजट संतुलित और सराहनीय : विशाल डुंगडुंग

आजाद सिपाही संवाददाता

लोहरदगा। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के द्वारा पांचवीं बार राज्य का बजट पेश किया गया और कई बड़ी जनकल्याणकारी घोषणाएं की गयी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वर्ष 2024 - 25 के लिए एक लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया। इस पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विशाल डुंगडुंग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जनकल्याणकारी बजट बनाया है जो आगामी दिनों में झारखंड को विकास के पद पर अग्रसर करेगा, यह बजट राज्य के गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों अल्पसंख्यकों, महिला ,युवा बुजुर्ग, मजदूर किसानों की गांव और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला संतुलित और बजट है,झारखंड सरकार ने राज?य के

किसानों का भी ख्याल रखा है और ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख करने तथा एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने का एलान किया गया। कृषि एवं पशुपालन के लिए 40606.57 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया, साथी सरकार ने 125 मिनट फ्री बिजली प्रदान करने का ऐलान किया है, गरीबों का दाल चावल के साथ-साथ सोया बड़ी भी उपलब्ध कराया जाएगा, एवं मुखिया का मानदेय 2000 से 2500 वार्ड सदस्य का 200 से 500 प्रमुख का 3000 से 5000 किया गया है जिससे जनप्रतिनिधियों को बल मिलेगा, माता व शिशुओं के साथ बजट में शिक्षा पर जोर। वित्त मंत्री ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को मातृ किट मिलेगा। महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 8021.93 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें जच्चा बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग आदि होंगे। उन्?होंने एलान किया कि अगले वित्तीय वर्ष में 325 प्रखंडों में लीडर स्कूल खुलेंगे। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12 हजार तीन सौ 14 करोड़ 21 लाख रुपये तथा उच्च एवम तकनीकी शिक्षा के लिए 2411.77 करोड़ का बजट रखा गया है। उन्?होंने बताया कि 4036 पंचायत स्तरीय विद्यालय अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित होंगे। 117 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा हेतु लैब की स्थापना होगी।

झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला

संतोष सिन्हा

बालूमाथ (आजाद सिपाही)। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को रांची मे राज्य के मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात कर जहाँ राज्य मे पत्रकार सुरक्षा कानून लागु करने की मांग की। वहीँ राज्य के पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान की दिशा मे समुचित पहल करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमण्डल मे यूनियन के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, महासचिव राजीव नयनम, रांची महानगर अध्यक्ष जावेद, सरायकेला खरसावां के अध्यक्ष सुधाकर झा, पश्चिमी सिंहभूम के

अध्यक्ष गौरीशंकर झा, उदय प्रताप सिंह, जगदीश सिंह, उदय सिंह जोगी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आनंद प्रियदर्शी आदि शामिल थे। वहीं राज्य मे पत्रकार सुरक्षा कानून लागु करने की मांग तथा राज्य के पत्रकारों की समस्याओं से मुख्यमंत्री चमपई सोरेन को अवगत कराये जाने पर बालूमाथ प्रखंड के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिन्हा, जावेद अख्तर, कौशर अल्ली, बारियातू प्रखंड के मो अरसद, मो कुतुबुद्दीन ने झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस के प्रतिनिधिमंडल मे शामिल अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, महासचिव राजीव नयनम, रांची महानगर अध्यक्ष जावेद, सरायकेला खरसावां के अध्यक्ष सुधाकर झा, पश्चिमी सिंहभूम के अध्यक्ष गौरीशंकर झा, उदय प्रताप सिंह, जगदीश सिंह, उदय सिंह जोगी को हार्दिक बधाई दिया है।

शांति नहीं, अब क्रांति से बनेगी बात: राजेंद्र प्रसाद

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आने वाले लोकसभा, विधानसभा चुनाव में हक के लिए आर-पार की लड़ाई के लिए मूलवासी सदान तैयार रहे। मोर्चा का राजभवन मार्च मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से निकला। राजभवन के समीप पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद सभी लोग वहीं जम गये। कहा कि राज्य बने 23 वर्ष हो गये, लेकिन एक स्थानीय नीति सरकार नहीं बना पायी है। सदानों के शहादत से झारखंड राज्य मिला, लेकिन राज्य बनने के पश्चात मूलवासी सदानों के अधिकारों एक-एक कर छीना जा रहा है। इसे अब किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कहा कि नियोजन नीति और स्थानीय

नीति अंतिम सर्वे के आधार पर सरकार बनाये। राज्य में पिछड़ी जाति का आबादी 55 प्रतिशत है, लेकिन सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। सात जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ों को 36 से 50 तक आरक्षण देने की राज्य सरकार से अनुशंसा की है। उन्होंने सदान आयोग बनाने की मांग की। कहा कि सत्ता की चाबी मूलवासी सदानों के पास है। 2024 के विधानसभा चुनाव में मूलवासी सदान सत्ता किसे देंगे, इसका निर्णय अक्टूबर माह में रांची में एक बड़ी रैली कर निर्णय लिया जायेगा। मार्च में शामिल लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। जो मूलवासी सदानों की बात करेगा, वही झारखंड में राज करेगा, स्थानीय नीति-नियोजन नीति अंतिम सर्वे के आधार पर बनाना होगा...के नारे लगा रहे थे। मार्च अधिकार रैली को संबोधित करने वालों में धनंजय राय, विश्वनाथ गोप, आरती देवी, प्रभा देवी, कृष्ण सिंह आदि शामिल थे।

40 महिलाओं के बीच किया गया गैस चूल्हा का वितरण

आजाद सिपाही संवाददाता

गुमला। परमवीर अल्बर्ट एक्का परिसर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा का निशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष अनूप चंद अधिकारी,वर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शकुंतला उरांव, भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री पायल तिवारी, सोशल मीडिया प्रभारी गुड्डी नंदा रोमा, नगर अध्यक्ष बल्केश्वर सिंह, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह,दीप्ति कच्छप के द्वारा संयुक्त रूप से उपस्थित लाभुकों के बीच गैस चूल्हा का वितरण किया गया। मौके पर

उपस्थित अनूप चन्द अधिकारी ने कहा केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण व शहरी महिलाओं को निशुल्क गैस चूल्हा उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं व बहने लकड़ी से चूल्हा फुकते फूकते उनकी आंखें लाल हो जाती है। उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों में बड़ी मुश्किल होती है।

जेसीबी मशीन ऑपरेटर को अपराधियों ने मारी गोली

आजाद सिपाही संवाददाता

कुडू / लोहरदगा । कुडू थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ कुडू से सुंदरू होते हुए बंदुवा मोड़ तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य मे लगी जेसीबी मशीन के ऑपरेटर को आज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना सुंदरू और सरना टोली केधोबकट नदी के समीप सोमवार की शाम करीब 6 बजे के आसपास की है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही सड़क निर्माण का काम करा रही एजेंसी चरण महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्य मे लगी जेसीबी मशीन के ऑपरेटर बिहार औरंगाबाद के नबीनगर निवासी

धीरज कुमार सिंह काम करने के बाद जेसीबी के सहायक ऑपरेटर उत्तर प्रदेश के चंदौली गांव निवासी रविरंजन कुमार के साथ वापस बड़की चांपी कैंप लौट रहा था, तभी तीन की संख्या में पैदल पहुंचे अज्ञात अपराधकर्मियों ने जेसीबी को धोबकट नदी के समीप रुकवाकर कर यह कहते हुए फायरिंग कर दी कि इसको मना करने के बाद भी काम बंद नही किया है। गोली धीरज के दाहिने हाथ मे लगी। घटना को अंजाम देकर तीनो पैदल जंगल की ओर चलते बने। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद, कुडू थाना प्रभारी कुलदीप राज टोप्पो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

गोली लगने के बाद ऑपरेटर जेसीबी लेकर भागने में सफल रहा, भाग रहे ऑपरेटर पर पीछे से भी फायरिंग किये जाने की सूचना है। ऑपरेटर धीरज और सहायक रवि जेसीबी लेकर किसी तरह बढकी चापी पुलिस पिकेट पहुंचे और घटना की जानकारी दी। जिसके बाद घायल को लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया गया है। जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है।

सूत्रों की माने तो मौकाए वारदात से पुलिस ने कोयल शंख जोनल कमिटी पीएलजीए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नाम से छोड़े गए चार - पांच पोस्टर भी बरामद किए हैं। जिसमे बिचौलिए-दलाल होश में आएं, घमंड में चूर पुलिस के साथ मिलकर गलत कार्य करने वांले खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, आदि बातें लिखी गयी हैं। प्रथम दृष्टया घटना रंगदारी वसुसलने का प्रतीत हो रहा है। लेकिन माओवादी के नाम पर पोस्टर किसके द्वारा छोड़ा गया है। फिलहाल पुलिस इसकी गहन जांच में जुटी है।

शराब बिक्री बंद कराने गयी पुलिस टीम पर हमला

सिमडेगा (आजाद सिपाही)। जलड़ेगा प्रखंड के लोम्बोई में लगे साप्ताहिक बाजार में अवैध शराब बिक्री बंद कराने पहुंची जलड़ेगा थाने की पुलिस टीम पर शराब विक्रेताओं सहित कुछ गांव वालों ने हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोम्बोई मे साप्ताहिक बाजार लगा था जिसमें अवैध शराब बिक्री हो रही थी। जलड़ेगा थाने की टीम जब उसे बंद कराने पहुँची तब शराब विक्रेताओं ने पुलिस टीम को घेर कर हमला कर दिया। इस हमले में गांव वाले भी शामिल हो गये।

झारखण्ड सरकार के द्वारा पेश की गयी बजट ऐतिहासिक: समीद अंसारी

आजाद सिपाही संवाददाता

कैरो। कैरो प्रखंड में झारखण्ड सरकार के द्वारा मंगलवार को प्रदेश का बजट पेश किया गया।इस बजट को झारखण्ड का अहम बजट बताते हुए जे एम एम कैरो प्रखण्ड कमिटी द्वारा झारखण्ड सरकार व सरकार के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बधाई दी गई।झारखण्ड सरकार के द्वारा पेश की गई इस बजट को इतिहास बजट बताते हुए केंद्रीय समिति सदस्य समीद अंसारी ने कहा कि झारखण्ड झारखण्ड के विकास के लिए जनकल्याणकारी बजट पेश की है इस बजट में गरीब,किसान,मजदूर के साथ साथ समाज के तमाम तबके के विकास के योजना बनाई है।बजट में किसानों के ऋण माफी का दायरा 50 हजार से बढ़कर 2 लाख कर दी गई है वहीं इस बार एन पी ए खाताधारकों के भी सामील किया गया है,निवार्चीत जनप्रतिनधियो का मानदेय बढ़ाने ,सर्वजन पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा में कटौती करने, ग्रीन कार्ड की संख्या 20 लाख से बढ़कर 25 लाख करने,राशन डीलरों का कमीशन 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढाकर 150 रुपये करने,घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर 125 यूनिट फ्री करने,गरीबो को को दाल चावल के साथ साथ सब्जी भी देने की बात कही गई।इसके साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है।बधाई देने वालो में प्रखण्ड प्रमुख सह जे एम एम नेता श्रीराम उरांव,प्रखण्ड अध्यक्ष मो सजाद,प्रखण्ड सचिव धनपत उरांव, परवीन साहू,अख्तर अंसारी, समीरुदीन अंसारी, लक्ष्मण उरांव ,शिब उरांव,बजरंग उरांव आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री से मिलकर बबलू सिंह ने जनसमस्याओं से अवगत कराया

हुसैनाबाद (आजाद सिपाही)। झामुमो के केंद्रीय सदस्य सह समाजसेवी वशिष्ट कुमार उर्फ बबलू सिंह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को गुलदस्ता देकर अभिवादन किया। इस दौरान हुसैनाबाद क्षेत्र की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व सिचाई समेत विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं और झामुमो की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने की बात कही गई। झामुमो नेता बबलू सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हुसैनाबाद क्षेत्र में विकास योजनाओं को गति देने को लेकर आश्वस्त किया है। झामुमो की सरकार राज्य की समुचित विकास के लिए कृतसंकल्पित है।

मरीज दिखाने के बहाने आये थे अपराधी, जबरन गाड़ी में बैठाकर ले भागे

ग्रामीण चिकित्सक का अपहरण

आजाद सिपाही संवाददाता

हुसैनाबाद। थाना क्षेत्र के ऊपरी कला गांव निवासी एक ग्रामीण चिकित्सक डॉ रहमान का सोमवार की शाम अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण चिकित्सक डॉ रहमान जपला-छतरपुर मुख्य पथ के ऊपरी गांव के समीप अपने निजी क्लीनिक में मरीज की जांच कर रहे थे। तभी शाम करीब सात बजे तीन लोग चारपहिया वाहन से आए और कहा कि गाड़ी में गंभीर स्थिति में एक मरीज है। वे वहीं चलकर उसकी जांच कर लें। जब डॉ रहमान मरीज को देखने गाड़ी के पास आए तभी अपहरणकर्ताओं ने उन्हें जबरन गाड़ी में बिठा लिया और फरार हो गए।

डॉ रहमान की फाइल फोटो।

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

उधर, चिकित्सक के अपहरण की जानकारी मिलते ही आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने मंगलवार को छतरपुर-जपला मुख्य मार्ग को एक घंटे तक जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को भरोसा दिया कि पुलिस डॉ रहमान को सकुशल बरामद कर लेगी। साथ ही अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद आक्रोशित लोग शांत हुए और सड़क अवरोध खत्म किया। हालांकि खबर लिखे जाने तक अपराधियों की ओर से किसी तरह की फिरौती की मांग नहीं की गई है। वहीं, कंपाउंडर द्वारा अपराधियों के बारे में दी गयी जानकारी के आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जबकि पुलिस आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। अपराधियों की तलाश में कई जगहों पर छापामारी की जा रही है। उधर, हुसैनाबाद के एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो घटना के बाद मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। हालांकि अब तक अपहरण के कारणों का पता नहीं चल सका है। थाना प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि डॉ रहमान की पत्नी के आवेदन पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

औद्योगिक विकास का बजट छलावा : आनंद शंकर

मेदिनीनगर (आजाद सिपाही)। पलामू चेंबर अध्यक्ष आनंद शंकर ने कहा कि औद्योगिक विकास की बातें या बजट छलावा है। चार साल की अवधी में सरकार कई जिलों में अब तक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बना पाई है। ना ही झारखंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू कर पाई, जबकि हर वर्ष बजट में रुपय का प्रावधान होता। फिर कैसा औद्योगिक विकास। पलामू जिला जो प्रमंडल का मुख्यालय है कई वर्षों से इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए भूमि की बात कर रही है, जबकि आज तक इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाया। फिर सरकार किस औद्योगिक विकास की बात कर रही है। लातेहार और चतरा सहित कई जिले ऐसे हैं जहां उद्योग के लिए एक इंच भूमि नहीं है। बजट खाने कमाने वाला है।

जिला अभियंता का कार्यालय, जिला परिषद, खूँटी
(अभियंत्रण शाखा)

शुद्धि पत्र

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा ई–निविदा अन्तर्गत अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 33/2023-24 PR No- 320334 (District) 23-24 (D) द्वारा निकाली गई खूँटी जिला अन्तर्गत कर्रा प्रखण्ड में ग्राम गोविन्दपुर में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य क्रम संख्या 01 को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

ह०/–
जिला अभियंता,
जिला परिषद, खूँटी

PR 320530 District(23-24)#D

पत्रकार को पितृ शोक, राजनीतिक दलों और समाजसेवियों ने व्यक्त किया शोक

हरिहरगंज/पलामू (आजाद सिपाही)। हरिहरगंज और पीपरा प्रखंड के एक पत्रकार पिंटू मिश्रा (राजीव रंजन मिश्रा) के पिता सेवानिवृत रेलवे अभियंता विवेकानंद मिश्रा (65) का सोमवार को निधन हो गया। जिससे मृतक की पत्नी प्रभावती देवी सहित पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं पत्रकार के पिता के निधन की सूचना मिलने के बाद विधायक कमलेश कुमार सिंह, पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, राजद के संजय सिंह यादव, कमलेश कुमार यादव, बसपा नेता प्रमोद कुमार रवि, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार सिंह आदि ने पत्रकार को फोन कर शोक व्यक्त किया। जबकि भाजपा नेता विनोद कुमार सिंह घर पहुंच कर ढांढस बंधाया। उनका अंतिम दाह संस्कार मंगलवार को घाघरा बटाने नदी तट हुआ। बड़े पुत्र दयानंद मिश्रा ने मुखाग्नि दी। दाह संस्कार में सांसद प्रतिनिधि अरुण मिश्रा, मुखिया उमेश साव, भीम मिश्रा, विनय जायसवाल, शिक्षक बिगन प्रजापति, विजय मिश्रा, अनुज कुमार मिश्रा, पैक्स अध्यक्ष धनंजय सिंह, मिथिलेश कुमार पांडेय आदि मौजूद थे।

हुसैनाबाद में ही होगी सेमेस्टर दो की परीक्षा : कमलेश सिंह

- विधायक ने कहा- वीसी ने दिया है आश्वासन
- परीक्षा केंद्र जपला में ही रखने की मांग को लेकर वीसी से मिले थे विधायक प्रतिनिधि

आजाद सिपाही संवाददाता

हुसैनाबाद। जपला एके सिंह कालेज में अध्यनरत विभिन्न संकायों में स्नातक के विद्यार्थियों के सेमेस्टर की परीक्षा समय-समय पर ली जाती है। एक मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा का केंद्र इस बार नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय द्वारा छतरपुर गुलाबचंद प्रसाद डिग्री कालेज कर दिया गया है। इस बाबत विधायक कमलेश कुमार सिंह के निर्देश पर विधायक प्रतिनिधि अजीत सिंह व एके सिंह कालेज के दानदाता पूर्व सचिव रौनक सिंह ने वीसी से मिलकर समस्याओं से अवगत कराया। बताया कि जपला के विभिन्न गांव से छतरपुर की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। दूसरी समस्या यह है कि जपला से छतरपुर आने जाने का समुचित साधन नहीं है। जिससे छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अधिकांश गरीब विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। विद्यार्थियों व उनके अभिभावको द्वारा विधायक से छतरपुर की जगह जपला के किसी कालेज या विद्यालय में परीक्षा केंद्र कराने की मांग की जा रही है। विधायक प्रतिनिधि ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर से जपला एके सिंह कालेज के विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए परीक्षा केंद्र जपला के ही इंटर उच्च विद्यालय या बीएड कालेज में करने की मांग की है। विधायक ने भी वीसी व परीक्षा नियंत्रक से फोन पर इस संबंध में बात की। वीसी ने बताया कि विभिन्न परीक्षाओं की वजह से हुसैनाबाद के एक भी शैक्षणिक संस्थान परीक्षा की व्यवस्था कराने की स्थिति में नहीं हैं। मगर सेमेस्टर 2 की परीक्षा हुसैनाबाद में ही कराने की व्यवस्था की जाएगी।

चुनावी शंखनाद: कुम्हार महाकुंभ के लिए हुआ मैराथन मंथन: अविनाश

मेदिनीनगर (आजाद सिपाही)। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसी बीच झारखंड विधानसभा का बिगुल फूंका जायेगा। हम सभी कहीं न कहीं वोट मागेंगें लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद हम कहां खड़े रहेंगे। सरकार हमें किस तरह के लाभ पहुंचाएगी और क्या मिलेगा अहम सवाल है। इसीलिए राज्यभर से समाज के बुद्धिजीवियों की बैठक मेदिनीनगर में हुई। मैराथन मंथन के बाद राज्यभर से आए बुद्धिजीवियों के बीच सरकार व सरकारी लाभ के लिए आपसी समन्वय बनाने पर सहमति बनी। मातृ संगठन के साथ जो जहां है वह वहीं रहे। पर समाजहित में वक्त पर समन्वय समिति के साथ कदम ताल करें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी रांची में चुनावी बसंत के बज्रनाद करने के लिए कुम्हार महाकुंभ लगाने का एजेंडा पास हुआ। झारखंड माटीकला बोर्ड पुनर्गठन के लिए आंदोलन करने, छात्रावास एवं राज्य कार्यालय निर्माण पर सहमति बनी। मैराथन मंथन में धनबाद से प्रकाश, दक्षिणेश्वर, रांची से दिनेश, बोकरो से बैजनाथ, गोमिया से कुलदीप, हजारीबाग से महेंद्र, रामगढ़ से नमिता, लातेहार से आनंद, चंदवा से डब्ल्यू, बालूमाथ से अनिल, गढ़वा से कन्हैया, योगेंद्र, पलामू से प्रदीप नारायण के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारी बुद्धिजीवी साथी मौजूद रहे। सम्मानित साथी संजय, संतोष, शोभा, विनोद, अच्छेलाल, सत्येंद्र, मदन, चंदन, कमलेश गुरुजी, त्रिपुरारी गुरुजी, संतोष गुरुजी, शंकर जी, भीम, परमानंद, परमेंद्र, अरुण, लखु जी, ब्रह्मदेव, बालेश्वर, राजू, भुनेश, अनूप, पीतांबर, शत्रुघ्न, आचार्य रामनरेश आदि उपस्थिति थे।

उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा
(पर्यटन शाखा)

शुद्धि पत्र

कोडरमा जिला अन्तर्गत चन्दवारा प्रखण्ड के तिलैया डैम एवं झील रेस्टुरेन्ट उरवाँ के समीप पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पार्क एवं विभिन्न संरचनाओं का विकास हेतु दिनांक 23/24–02–2024 को अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कि गई थी, जिसका PR सं0 320108 है। उक्त सूचना में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है :–

क्रमांक	निविदा संबंधित विवरण	पूर्व में निर्धारित तिथि	संशोधित निर्धारित तिथि
01	Last date & Time for BID submission	03-03-2024 till 12:00 PM	04-03-2024 till 12:00 PM
02	Date & Time for BID opening	03-03-2024, 03:00 PM	04-03-2024, 03:00 PM
03	Technical Solution Presentation & Evaluation	03-03-2024, 03:00 PM	04-03-2024, 03:00 PM
04	Opening of Financial Bids and finalevaluation	03-03-2024, 03:00 PM	04-03-2024, 03:00 PM

अल्पकालीन निविदा सूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

PR 320467 Tourism, Art Culture Sports And Youth Affairs(23-24)#D

ह0/–
जिला पर्यटन पदाधिकारी, कोडरमा

उंटारी पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान

उंटारी रोड/पलामू। एसपी रिष्मा रमेशन के निर्देश पर पलामू जिले के उंटारी रोड थाना के समीप चेकपोस्ट पर मंगलवार को वाहन जांच और सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसका नेतृत्व मुन्नालाल जमुदा कर रहे थे। उन्होनें बताया कि वाहन के सभी कागजात, हेलमेट सहित सिटबेल्ट की जांच की जा रही है। सभी वाहनों की गहनता से जांच हो रही है। यातायात संबंधित जानकारी भी दी जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक एवं डीजल गाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन

मेदिनीनगर (आजाद सिपाही)। महिंद्रा आनंद मोटर्स सर्विस सेंटर की ओर से गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज रेड़मा में इलेक्ट्रिकल और डीजल इंजन गाड़ियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के सभी शिक्षक और छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस आयोजन में महिंद्रा से आए कस्टमर केयर मैनेजर सीसीएम श्रीराम सिंह और उनके साथ टेक्निकल स्पेशलिस्ट मो मुशर्रफ हुसैन, आनंद मोटर्स के जीएम रविंद्र सिंह, अगस्त तिवारी, टेक्निकल मैनेजर रणविजय सिंह मौजूद थे। इसमें आनंद मोटर सर्विस सेंटर के रविंद्र सिंह द्वारा छात्र-छात्राओं सहित सभी लोगों को देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक कारों की गुणवत्ता के बारे में बताया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदे, ताकि देश में प्रदूषण वृद्धि में कमी लायी जा सके। यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोगों को कम बजट में ही रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। इस प्रशिक्षण समारोह में गवर्नमेंट आईटीआई के प्रिंसिपल चनर्धन बैठा और सारे टीचर मौजूद थे और सारे स्टूडेंट ने इस अवसर का काफी लाभ उठाया।

भवन निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री बसंत सोरेन से मिले पांकी विधायक

आजाद सिपाही संवाददाता

पांकी/पलामू। विधायक डॉ कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सूचना के माध्यम से पलामू जिला के भवन निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। विधायक ने सदन में आवाज उठाया कि किस प्रकार कार्यपालक अभियंता की जानकारी के बिना प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किए पशुपालन विभाग के भवनों और चहारदीवारी निर्माण कराने और जीर्णोद्धार के कार्यों की निविदा निकाल दी गई। चौंकाने वाली बात है कि ना सिर्फ

बिना प्रशासनिक स्वीकृति के निविदा निकाली गई, बल्कि कार्यालय में क्रमशः पिछले बारह एवं पांच वर्षों से जमे कैशियर एजाज एवं लेखापाल नीरज कुमार राय द्वारा चहेते संवेदकों के पक्ष में निविदा मैनेज करने का प्रयास किया गया। उक्त दोनों कर्मचारी टेंडर मैनेज करने एवं कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की मुख्य कड़ी हैं। जब यह मामला सदन के संज्ञान में कल शून्यकाल के माध्यम से सरकार के संज्ञान में आया तब आनन फानन में निविदा को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया। करीब तीन माह पूर्व में भी इन लोगों द्वारा हाल ही में 15वीं वित्त की राशि से जीर्णोद्धार कराए गए पंचायत भवनों का पुनः कार्य कराने की निविदा निकाल दिया गया। जिसे विधायक द्वारा सरकार के संज्ञान में लाए जाने पर आनन फानन में स्थगित कर दिया गया था। विधायक डॉ शशिभूषण मेहता ने राज्य सरकार के भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन को लिखित रूप से अवगत कराया। मंत्री बसंत सोरेन ने अविलंब दोषियों पर विभागीय कार्रवाई करने का अश्वशन दिया।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, हजारीबाग

अतिअल्पकालीन ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना (2nd Call)

ई–निविदा प्रसंग सं० :– **RCD/HAZARIBAG/188/2023-24**
दिनांक : **27.02.2024**

1.	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में पथ प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत **'महतो–अहरा–रामपुर–बसिरया–चौपारण पथ के कि॰मी॰ 0.00 से कि॰मी॰ 32.85 तक (कुल लम्बाई–32.85 कि॰मी॰) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य '**
2.	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	रू॰ 25,63,97,000.00 (पच्चीस करोड़ तिरेसठ लाख संतानबे हजार रूपये) मात्र
3.	कार्य समाप्ति की अवधि	06 (छः) माह
4.	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि एवं समय	29.02.2024 10:30 A.M
5.	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	06.03.2024 12:00 P.M
6.	निविदा खोलने तिथि एवं समय	07.03.2024 12:00 P.M
7.	Pre-Bid बैठक	05.03.2024 12:00 P.M
8.	निविदा आमंत्रित करने वाले का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, हजारीबाग।
9.	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क नं०	8709320541
10.	ई–प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्प लाईन नं०	0651–2446007

अतिरिक्त जानकारी के लिए वेबसाईट पर देखें :–
http://jharkhandtenders.gov.in
E-mail ID : eercdhazari-jhr@nic.in
Tel. No. – 06546-225818

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग
पथ प्रमण्डल, हजारीबाग

PR 320538 Road (23-24)_D

डीसी ने की अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास और भीमराव अंबेडकर आवास योजना की समीक्षा

अबुआ आवास के जिन लाभुकों के सभी कागजातों की जांच हो गयी है, उन सभी को दो दिनों में जारी हो पहली किस्त : डीसी

आजाद सिपाही संवाददाता

मेदिनीनगर। पलामू डीसी शशि रंजन ने मंगलवार को एनआईसी सभागार से वर्चुअल जिले के सभी बीडीओ व आवास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक की। इस दौरान आबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए लंबित आवासों को पूर्ण करने व जिन लाभुकों के सभी दस्तावेजों की जांच हो गयी है उनको त्वरित गति से प्रथम किस्त भुगतान करने का निर्देश दिए। आबुआ आवास योजना

अंतर्गत प्रखंडवार प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन तथा जियोटैगिंग का बिंदुवार समीक्षा की गयी। इस दौरान डीसी ने सभी बीडीओ को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निर्गत करने को शत प्रतिशत लाभुकों का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कहा कि जिसका खाता नंबर, आधार व जॉब कार्ड की जांच हो गयी है उन सभी को दो दिनों के भीतर प्रथम किस्त का भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लंबित आवासों की समीक्षा करते हुए युद्ध स्तर पर सभी आवासों को पूर्ण करने के निर्देश दिया। इसी तरह मनरेगा अंतर्गत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना की समीक्षा की। बताया गया कि जिले में 6,460 लक्ष्य के विरुद्ध 4,604 का काम जारी है, जबकि 1856 लंबित है। इस पर डीसी ने सभी बीडीओ व बीपीओ को लंबित बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना को अगले दो दिनों के भीतर ऑनगोइंग करने का निर्देश दिया। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये बागवानी हेतु 1500 एकड़ का लक्ष्य जिले को प्राप्त है जिसमें अभी तक 355 एकड़ में बागवानी हेतु लाभुकों का चयन किया गया है। इस पर डीसी ने चयन लाभुकों को 24 घंटे के भीतर स्वीकृत करते हुए ओंनगोइंग करने का निर्देश दिया। इसके अलावे प्राप्त लक्ष्य के दोगुना क्षेत्र में बागवानी करने का निर्देश दिया। इस मौक डीडीसी रवि आनंद, मनरेगा के परियोजना पदाधिकारी उपेंद्र पासवान, आवास के परियोजना पदाधिकारी विमलेश विश्वकर्मा, आवास के जिला कोऑर्डिनेटर मुफ्ती अनवर व प्रशिक्षण समन्वयक अभय चौरसिया उपस्थित रहे, जबकि सभी बीडीओ, बीपीओ व आवास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वर्चुअल मोड से जुड़े रहे।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
जल पथ प्रमंडल सं0–2 हजारीबाग।
Email Id- eewwdchak2-cer-jhr@nic.in

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0 – 04/2023–2024

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost (INR)	Earnest Money (INR)	Cost of BOQ (INR)	Completion period of Work
1	प्रखंड बरही अन्तर्गत अग्निषमन वाहनों में पानी भरने के लिए डीप बोरिंग, पम्प, स्टेटिक टैंक एवं विभिन्न निर्माण कार्य।	9,85,359	19,800	1250	1 Months

1. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान तिथि एवं समय : कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, जलपथ प्रमंडल सं0–2, हजारीबाग। दिनांक 05.03.2024 अपराहन 3:00 बजे तक।
2. निविदा प्राप्ति की स्थान तिथि एवं समय : कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, जलपथ प्रमंडल सं0–2, हजारीबाग। दिनांक 06.03.2024 पूर्वाहण 11:00 से अपराहन 3:00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की स्थान तिथि एवं समय : दिनांक 06.03.2024 को अपराहण 3:30 बजे कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, जलपथ प्रमंडल सं0–2, हजारीबाग।
4. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं दूरभाष सं0– 7903709450 : कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल सं0–2, हजारीबाग।
5. परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है।

नोट :– निविदा से संबंधित शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय अवधि में सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
जलपथ प्रमंडल सं0–2,
हजारीबाग।

PR 320395 Water Resource(23-24)D

गिरिडीह नगर भवन में जेएसएलपीएस की ओर से जिलास्तरीय रोजगार मेले का आयोजन

रोजगार मेले में 1229 युवाओं को मिला नियुक्तिपत्र

जिनका चयन नहीं हुआ, वे निराश ना हों, फिर मिलेगा मौका: डीडीसी

आजाद सिपाही संवाददाता

गिरिडीह। नगर भवन में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी (जेएसएलपीएस) की ओर से मंगलवार को जिलास्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। क्जिसका उद्घाटन डीडीसी दीपक कुमार दूबे, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी व जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा किया गया। इस अवसर पर डीडीसी ने कहा कि गिरिडीह जिले के युवाओं को बेहतर रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जिले में बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा युवाओं को चिन्हित कर रोजगार मुहैया कराया जा सके। जेएसएलपीएस का यह प्रयास सराहनीय है। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। रोजगार सृजन मेले से आज सैकड़ों युवक-युवतियां अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर लौटेंगें। लेकिन, वैसे अभ्यर्थी जिनका किसी कारण चयन नहीं हो सका, वह निराश नहीं होंगे। पुनः रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ज्यादा से ज्यादा युवाओं/युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को प्रयासरत है। वहीं, डीपीएम ने कहा कि जिले में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने रोजगार मेले में शामिल सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि निबंधित छात्र-छात्राओं का डाटा संग्रह करते हुए प्रशासन ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मुहैया करायेगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराएं गए रोजगार के अवसर को गंभीरता से लेने को कहा। इस दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा डीडीसी ने नगर भवन में आयोजित रोजगार सृजन मेला में लगाएं गए 20 कंपनियों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टॉल पर उपलब्ध नियोक्ताओं व अभ्यर्थियों से जानकारी ली। सांकेतिक रूप से मौके पर ही दर्जनों चयनित युवक-युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र सौंपा। मेले में गिरिडीह व देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 2417 युवक-युवतियों ने निबंधन कराया, जिसमें विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा 1229 युवक-युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर प्लेसमेंट पदाधिकारी सांई दत्ता, जेएसएलपीएस की कौशल विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

रोजगार मेले में उपस्थित डीडीसी व अन्य गणमान्य लोग।

रोजगार मेले में विभिन्न जगहों से आए अभ्यार्थी

संत रैदास की 647वी जयंती में शामिल हुए पूर्व मंत्री माधवलाल/ बेरमो (आजाद सिपाही)। गुजरकुंडा गांव में आयोजित संत रैदास जी की 647वी जयंती में पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने संत महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, कार्यक्रम के अध्यक्षता विजय सिंह और संचालन सचिव मोहन सिंह ने किया। माधवलाल सिंह ने कहा कि संत रैदास जी का जीवन समाज के उन वर्ग के लोगो के जीवन के उत्थान में लगा रहा जिस दबे, कुचले वर्ग की सदैव उपेक्षा होती थी।

उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा
(जिला विकास शाखा)

2nd Call इच्छा की अभिव्यक्ति
(Expression of Interest)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए **DMFT** मद से **1. HbA1c Machine 2. Hemoglobin Meter 3. CBC Machine (5 Parameter)** क्रय किया जाना है।उक्त कार्य के दर निर्धारण हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/एजेन्सी से इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है। आपूर्तिकर्त्ता/एजेन्सी को सूची बद्ध जिला विकास शाखा, कोडरमा में किया जायेगा। **1. HbA1c Machine 2. Hemoglobin Meter 3. CBC Machine (5 Parameter)** क्रय किये जाने निमित आवयक कार्य/ **Specification**सूची संलग्न।

अतः इच्छूक आपूर्तिकर्त्ता/एजेन्सी अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति **(Expression of Interest)**का आवेदन मुहर बन्द लिफाफा में उपायुक्त, कोडरमा को संबोधित करते हुए स्थान–जिला विकास शाखा,कोडरमा में दिनांक–05/03/2024 को अपराह्न 12:00 बजे तक हाथों–हाथ या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। उक्त इच्छा की अभिव्यक्ति उपायुक्त, कोडरमा के सभा कक्ष में दिनांक–05/03/2024 को 03:00 बजे अपराह्न में खोला जायेगा।

नोटः–उक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी जिले के बेवसाईट www.koderma.nic.in पर देखा जा सकता है।

उपायुक्त,
कोडरमा

PR 320515 (District)23-24*D

हजारीबाग नगर निगम, हजारीबाग

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं 52/2023–24

Group No.	Name of work	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Cost of BOQ (Rs.)	Completion period for construction
1.	Construction of P.C.C Road from H/O Chanrashekhar Kumar to Baleshwar Prasad in New Colony Babugaon in Ward No. 08 Under Municipal Corporation, Hazaribag	9,96,600/-	20,000/-	5,900/-	60 Days
2.	Construction of R.C.C Drain from Jibraltor Chowk Canary Jabra Road to Nala via H/O Murli Singh in Ward No. 08 Under Municipal Corporation, Hazaribag	9,92,939/-	20,000/-	5,900/-	60 Days

1. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान तिथि एवं समय	:	नगर निगम कार्यालय, हजारीबाग दिनांक 05.03.2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक
2. निविदा प्राप्ति का स्थान तिथि एवं समय	:	नगर निगम, हजारीबाग दिनांक 07.03.2024 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक
3. निविदा खोलने का स्थान तिथि एवं समय	:	नगर निगम, हजारीबाग दिनांक 07.03.2024 को 2.00 बजे अपराह्न से अंतिम निविदा खुलने तक
4. विज्ञापनदाता का पदनाम	:	नगर आयुक्त–सह–प्रशासक, नगर निगम, हजारीबाग।

ह०/–
नगर आयुक्त–सह–प्रशासक
नगर निगम, हजारीबाग

PR 320499 Urban Development and Housing(23-24)#D

महत्वपूर्ण न्यूज

प्रधानमंत्री के धनबाद आगमन की तैयारियों को लेकर रागिनी सिंह की अगुवाई में बैठक

झरिया (आजाद सिपाही)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मार्च को धनबाद आगमन पर तैयारियों को लेकर मंगलवार को झरिया-कतरास मोड़ स्थित बिहार बिल्डिंग कार्यालय में बैठक हुई। जिसमें भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह जनता श्रमिक संघ (जश्रसं) की महामंत्री रागिनी सिंह भी शामिल थीं। बैठक में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चर्चा की गई और कार्यक्रम में झरिया विधानसभा में जश्रसं सह भाजपा कार्यकर्ताओं की अधिक से अधिक उपस्तिथि की रूपरेखा तैयार की गई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर प्रदीप सिन्हा, गौरव वक्ष, सतेंद्र कुमार, दिलीप भारती, शिव कुमार यादव आदि मौजूद थे।

गिरिडीह के 17वें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में अंजना भारती ने संभाला पदभार

गिरिडीह (आजाद सिपाही)। जिले के 17वें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के रूप में अंजना भारती ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने उन्हें पदभार सौंपा। इस दौरान अंजना भारती ने कहा कि जनसंपर्कीय कार्यों के लिए सरकार ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, उस पर शतप्रतिशत खरा उतरने का प्रयास करूंगी। साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार के साथ मीडिया से बेहतर समन्वय की दिशा में कार्य करने का प्रयास किया जायेगा। इस मौके पर सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर, साउंड ऑपरेटर आदि मौजूद थे।

दो बाइक की टक्कर में चार लोग घायल

एग्यारकुंड (आजाद सिपाही)। चिरकुंडा थाना अंतर्गत चिरकुंडा-पंचेत रोड में मंगलवार को दो बाइक की टक्कर में एक महिला सहित चार लोग घायल हो गए। इसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीन घायल को इलाज के लिए सरसापहाड़ी स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां नूतनगांव निवासी मिलन झाल, उसकी पत्नी लालमुनि झाल व भाई आकाश झाल का इलाज चल रहा है। आकाश परिवार के साथ डेढ़ माह के बच्चे का इलाज कराने बाइक से नूतनगांव से चिरकुंडा की ओर आ रहे थे। तभी हादसा हुआ।

झारखंड सरकार ने पेश किया चहुमुखी विकास का बजट : ब्रजेंद्र

आजाद सिपाही संवाददाता

धनबाद। राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने मंगलवार को झारखंड सरकार द्वारा पेश बजट की सराहना की। कहा कि झारखंड में जो बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया गया है वह किसानों, मजदूरों और नौजवानों के हितों को ध्यान में रखकर किया है। खासकर किसान वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। बेरोजगारों का ख्याल विशेष रूप से रखा गया है। झारखंड को चौमुखी विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। किसी नए टैक्स का बोझ जनता पर नहीं थोपना सराहनीय कदम है।

आरटीइ एक्ट में धनबाद के डीएसइ का चलता है अपना कानून : अनूप

धनसार (आजाद सिपाही)। बीपीएल नामांकन प्रक्रिया को जटिल करने से अभिभावकों में आक्रोश है। इसके निमित्त मंगलवार को झरिया-बाटा मोड़े पर गणेश चौक के समक्ष अभिभावकों ने धनबाद के जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार का पुतला दहन कर विरोध जताया। साथ ही झरिया सीओ के विरुद्ध भी नाराजगी जाहिर की। कहा कि हम लोगों के पास बीपीएल कार्ड भी है जिसे सरकार न्यूनतम आय के रूप में मानती है। बावजूद इसके जिला शिक्षा अधीक्षक बच्चों के बीपीएल नामांकन में 72000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र मांग रही है, जिसे सीओ निर्गत नहीं कर रही है, जबकि रांची में ऐसा कोई प्रावधान लागू नहीं किया गया है। एक ही राज्य में अलग-अलग नियम यह एक अजीब विडंबना है। वहीं पूर्व पार्षद अनूप साव ने कहा कि आरटीई एक्ट में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले बीपीएल कार्ड धारी को पूर्व से अपने बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन करने का अधिकार था पर इस वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक किन कारणों से गरीब अभिभावकों को परेशान कर रही हैं पता नहीं चल रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी भ्रष्टाचार का खेल होगा। जिसका हम लोग विरोध करते हैं। मांग करते हैं कि दो मार्च का निर्धारण आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए, ताकि हम अभिभावक अपने जनप्रतिनिधि से बीपीएल कार्ड या आय प्रमाण पत्र दोनों में से किसी एक को मान्यता देने अथवा झरिया अंचल अधिकारी को 72000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र निर्गत करने को कह कें। इस मौके पर मिथिलेश यादव, टुनटुन रजक, मिनी साव, टुन्नू गुप्ता, नरेश साव, बबलू वर्मा, सूरज वर्मा, शेखर रजक, बिहार बर्मन आदि उपस्थित थे।

चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर दी गयी श्रद्धांजलि

कतरास (आजाद सिपाही)। रामकनाली स्थित पार्श्वनाथ उद्यान में बीसीकेयू के केंद्रीय सचिव कंचन महतो एवं झामुमो के वरीय नेता राजेंद्र प्रसाद राजा के संयुक्त तत्वावधान में क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर मंगलवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सर्वप्रथम शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दर्जनों लोगों ने नमन किया। वहीं, वक्ताओं ने उनके आंदोलन एवं उद्देश्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए देश की आजादी को क्रांतिकारीयों के बलिदान की देन बताया। मौके पर झामुमो पंचायत अध्यक्ष साजन महतो, संजय महतो, पंचायत सचिव प्रदीप महतो, दिनेश महतो, शक्ति महतो, शंकर महतो, राजू महतो, बिनोद महतो, विवेक महतो, कमल दास, सोमनाथ महतो, अमर बाउरी, सोम बाउरी, अजीत दास, फुलचंद कुम्हार, मिथुन कुम्हार, सुनील दास आदि मौजूद थे।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, राँची

Un-Tied मद अन्तर्गत
अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0 – 44/2023–24

1. विज्ञापनदाता का नाम :– कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम,राँची।
2. परिमाण विपत्र, बिक्री की तिथि/स्थान :– दिनांक **04.03.24 को** 3.00 बजे तक। विकास भवन, राँची।
3. निविदा प्राप्त करने की तिथि/स्थान :– दिनांक **05.03.24 को 3.00** बजे अपराह्न तक जिला नियंत्रण कक्ष, राँची।
4. निविदा खोलने की तिथि :– दिनांक **05.03.24 को 3.00** बजे अपराह्न ।
5. कार्य का विवरण।

क्र0 स0/ ग्रुप स0	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि	यंत्र सयंत्र का स्वामित्व
1	2	2	4	5	6	7	8
1	शहरी क्षेत्र	शहरी क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड सं0 01 न्यू हॉट लिप्स के सामने मुख्य पथ से चर्च गली में पी0सी0सी0 पथ के साथ ढ़क्कन सहित नाली निर्माण।	17,70,000.00	**35,500/-**	**5000/-**	तीन माह	कार्य के अनुरूप

नोट :
1-Tender Fee, अग्रधन की राशि 2 प्रतिशत, पैन, GST Certificate, Up To date GST Return Certificate तथा निबंधन प्रमाण पत्र को स्वअभि प्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से जमा करने के पश्चात ही निविदा पत्र (BOQ) निर्गत किया जायेगा।
2. निविदा डालते समय पथ निर्माण विभाग झारखण्ड राँची के संचिका सं0 प0नि0वि0/विविध 06–33/2007 (अंश – 1) 2146 (5) दिनांक 09.09.2020 के अनुसार Performance Security उपलब्ध करायें।

कार्यपालक अभियंता
एन0आर0ई0पी0 – 1, राँची

PR 320480 (NREP) 23-24 (D)

कार्यालय जिला अभियन्ता, जिला परिषद, गुमला
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 21/2023–24

1. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता :– जिला अभियन्ता जिला परिषद, गुमला
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :– दिनांक 05.03.2024 (अप0 3.00 बजे तक)
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक 06.03.2024 (अप0 3.00 बजे तक)
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 06.03.2024 (अप0 3:30 बजे)
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :– कार्यालय जिला अभियन्ता जिला परिषद, गुमला
6. निविदा प्राप्ति का स्थान :– कार्यालय जिला अभियन्ता जिला परिषद, गुमला
7. कार्य का विवरण मदवार :– विभिन्न भवनों परिसम्पतियों का निर्माण, मरम्मति एवं नवीकरण

क्रम	प्रखण्ड	पंचायत	योजना का नाम	कुल आवंटित राशि	परिमाण विपत्र की राशि	अग्रधन की राशि	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sisai	Bhurso	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2278900	5000	45578	तीन माह
2	Gumla	Kulabira	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2242900	5000	44858	तीन माह
3	Dumri	Nawadih	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2266000	5000	45320	तीन माह
4	Gumla	Karti	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2300500	5000	46010	तीन माह
5	Ghaghra	Dirgaon	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2395200	5000	47904	तीन माह
6	Dumri	Khetli	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2242900	5000	44858	तीन माह
7	Chainpur	Chichhwani	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2274600	5000	45492	तीन माह
8	Chainpur	Buweynagar	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2242900	5000	44858	तीन माह
9	Bishunpur	Nirasi	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2237100	5000	44742	तीन माह
10	Bishunpur	Ghaghra	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2214900	5000	44298	तीन माह
11	Bishunpur	Narma	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2295700	5000	45914	तीन माह
12	Bharno	Duria	Reparing work for Rajeev Gandhi Sewa Kendra (Panchayat Bhawan)	2287200	5000	45744	तीन माह
13	Gumla	Thana road Gumla	Reparing work for Market Complex Building	4969500	5000	99390	पांच माह

NIT के नियम एवं शर्त्ते :–
1.निविदा की विस्तृत शर्त्तों का अवलोकन जिला परिषद, गुमला के सूचना पट्ट एवं **gumla.nic.in** पर किया जा सकता है।

जिला अभियन्ता, जिला परिषद,गुमला

PR 320466 Rural Development(23-24)D

विधायक पर जबरन मंदिर ट्रस्ट को जमीन देने के लिए ग्रामीणों पर दबाव बनाने का आरोप

विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सात परिवार के सदस्य, बिजली-पानी कटवाने का आरोप

आजाद सिपाही संवाददाता

महुदा। बाघमारा प्रखंड के टुंडो पंचायत स्थित चिटाही के ग्रामीणों ने विधायक ढुल्लू महतो पर कथित रूप से शोषण एवं अत्याचार का आरोप लगाते हुए धनबाद स्थित रणधीर वर्मा चौक के समीप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गये। बतातें चलें कि चिटाही धाम के राम राज मंदिर के समीप रहने वाले ग्रामीणों ने विधायक पर रैयती व पुश्तैनी जमीन को जबरन मंदिर ट्रस्ट को दान देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी विधायक के खिलाफ ग्रामीण धरना दें चुके हैं। तब जिला प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक उचित कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण फिर से धरने पर बैठ गये। गौरतलब हो कि चिटाही धाम में वर्तमान में सात परिवारों के घरों की बिजली काट दी गयी है। उन्हें पानी भी नहीं मिल रहा है। आरोप है कि बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा यह सब विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर किया जा रहा है। जबकि प्रावधान के मुताबिक बीसीसीएल क्षेत्र में बसे लोगों को सीएसआर के तहत मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए। उधर, स्थानीय ग्रामीण सुरेश महतो ने बताया कि मंदिर प्रांगण के बाहर उन लोगों की जमीन हैं जिसपर दुकान लगाकर अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। पर उस जमीन को विधायक मंदिर ट्रस्ट को जबरन दान में देने का दबाव बना रहे हैं। उनकी गुंडागर्दी से परेशान होकर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट को जमीन दान देने से मना करने पर विधायक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हैं। 25 जनवरी से अबतक हमारे घरों में बिजली नहीं हैं। जिस रास्ते से वे लोग आते-जाते हैं, उस पर मिट्टी गिरा दिया गया हैं। इसके अलावे दुकानों के आगे बांस व कपड़े से दीवालनुमा घेराव कर दिया गया जिससे श्रद्धालु उनकी दुकान पर नहीं आ सके। विधायक उन्हें 2019 से ही परेशान कर रहे हैं। वहीं सुनीति महतो ने आरोप लगाया कि ढुल्लू महतो अपने विधायक पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं। हम ग्रामीणों की जमीन को जबरन छिनना चाहता हैं। पर अब उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। आरोप लगाया कि प्रशासन भी विधायक के दबाव में काम कर रही है। हमें जमीन नापी का नोटिस जिस दिन दिया गया। उससे दो दिन पहले ही अचानक नापी कर दी गई। इसका प्रथम पक्ष कौन हैं इसका अता-पता ही नहीं हैं। उनकी दबंगई के खिलाफ डीसी और मुख्यमंत्री सहित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी लिखित शिकायत की हैं। जबतक हमें न्याय नहीं मिलता तबतक धरने पर बैठे रहेंगे। इस बार हमें आश्वासन नहीं न्याय चाहिए।

बाघमारा विधायक के खिलाफ रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठे लोग।

न्यूज रील्स

रास चुनाव : कर्नाटक में कांग्रेस को तीन, भाजपा को एक सीट मिली

बंगलुरु। कर्नाटक में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने तीन सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीती। उच्च सदन के लिए निर्वाचित नेताओं में कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन, जीसी चंद्रशेखर और सैयद नसीर हुसैन. जबकि भाजपा के नारायणसा के भांडगे शामिल हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों में अजय माकन 47, डॉ. सैयद नसीर हुसैन 46 और जीसी चंद्रशेखर 46 वोटों से जीते। राज्यसभा चुनाव में चार सीट के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें जनता दल (सेक्युलर) के उम्मीदवार डी कुपेंद्र रेड्डी भी शामिल थे। चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। भाजपा विधायकों में से एक, एसटी सोमशेखर ने कांग्रेस के अजय माकन के लिए मतदान किया, जबकि अन्य विधायक ए शिवराम हेब्बार ने मतदान में भाग नहीं लिया। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कार्यकताओं को धन्यवाद दिया है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 103.58 करोड़ की लागत से बनवाया अस्पताल

सीएम ने झारसुगुड़ा में कार्डिएक केयर अस्पताल का किया उद्घाटन

एमसीएल ने इलाके में हृदय रोग चिकित्सा होगी सुलभ, लोगों को होगी सुविधा

आजाद सिपाही संवाददाता

संबलपुर। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने झारसुगुड़ा में कार्डिएक केयर अस्पताल के माध्यम से सामाजिक कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया। झारसुगुड़ा में आयोजित उद्घाटन समारोह में अक्षय एस बापट, निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना) एमसीएल भी उपस्थित रहे।

ओडिशा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से एमसीएल ने झारसुगुड़ा में निर्मित अत्याधुनिक एक सौ बिस्तरीय कार्डिएक केयर अस्पताल ओडिशा सरकार को प्रदान किया। एमसीएल द्वारा सीएसआर पहल के तहत 103.58 करोड़ रुपये के निवेश से अस्पताल के बुनियादी ढांचे का निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और चिकित्सा कर्मियों के लिए आवासीय परिसर की स्थापना शामिल है। यह कार्डियक केयर अस्पताल पश्चिमी ओडिशा के अपेक्षाकृत कम उन्नत क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सेवा में उन्नति के प्रतीक के रूप में उभरेगा। उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित, इस अस्पताल में पश्चिमी ओडिशा के निवासियों को कम कीमत पर गुणवत्ता हृदयरोग चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होगी।

विपक्षी गठबंधन ने चुनाव से पहले मानी हार: पीएम मोदी

आजाद सिपाही संवाददाता

तिरुपुर (तमिलनाडु)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु में तिरुपुर के पल्लदम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के विकास से लेकर विपक्षी गठबंधन पर बात की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने जो गठजोड़ बनाया है, उसने पहले ही हार मान ली है। पीएम ने कहा कि आज जहां भी मेरी नजर पड़ रही है, वहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा विराट सम्मेलन, आप सब इतनी बड़ी तादाद हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, वो जरा आकर के देख लें कि तमिलनाडु हिंदुस्तान का

भाग्य बनाने वाला ये राज्य आज आपके आंखों के सामने है। जिन्होंने दशकों तक तमिलनाडु को लूटा, वो लोग भाजपा की बढ़ती ताकत से घबराये हुए हैं। वो लोग झूठ बोलकर, जनता को आपस में बांटकर, लोगों को लड़वाकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो राजनीति के समीकरण बनाते हैं, वे लिख लें कि इस बार देश का भाग्य पक्का करने में तमिलनाडु सबसे आगे होगा। 2024 में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का, नयी राजनीति का सबसे नया सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि आप ये भी याद रखिए कि द्रमुक और कांग्रेस लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी हैं। 2004-14 तक द्रमुक के लोग कांग्रेस की यूपीए सरकार के बड़े मंत्रालयों में मंत्री थे, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने कहा कि एमजीआर ने परिवार के आधार पर नहीं, बल्कि प्रतिभा के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य से आज तमिलनाडु में द्रमुक के कारण जो राजनीति हो रही है, वो एमजीआर साहब के लिए अपमान जैसी है। अगर एमजीआर के बाद कोई था, तो वो अम्मा जयललिता जी थीं, जिन्होंने तमिलनाडु के जनहित और जनकल्याण के लिए अपना पूरा जीवन दिया।

चार दिवसीय यात्रा पर आज ओड़िशा आयेंगी राष्ट्रपति, तैयारी पूरी

भुवनेश्वर में किया गया कारकेड रिहर्सल

आजाद सिपाही संवाददाता

भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को ओड़िशा के चार दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। इसके लिए कमिश्नरेट पुलिस की ओर से मंगलवार को कारकेड रिहर्सल किया गया। एयरपोर्ट से राजभवन और वहां से उत्कल यूनिवर्सिटी परिसर तक कारकेड रिहर्सल किया गया। कारकेड रिहर्सल में 28 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति बुधवार को विशेष विमान से बीजू पटनायक हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग उनका स्वागत करेंगे। फिर एयरपोर्ट परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जायेगा। वहां से राष्ट्रपति राजभवन जायेंगी। वह वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से मयूरभंज, क्योंझर, ब्रह्मपुर, कटक और संबलपुर जायेंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा की निगरानी के लिए कमिश्नरेट पुलिस द्वारा 30 प्लाटून बलों के साथ 150 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया है।

क्योंझर में नो-फ्लाइंग जोन की घोषणा

राष्ट्रपति की 29 तारीख को क्योंझर जिले की एक दिवसीय यात्रा की तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन ने राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कार्यक्रम स्थल से 700 मीटर के दायरे में नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया है।

जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति सबसे पहले 11.40 बजे क्योंझर जिले के गोनासिका पहुंचेंगी और जनजातीय लोगों के साथ बातचीत करेंगी। इसके बाद वह दोपहर तीन बजे धरणीधर विश्वविद्यालय उत्तर परिसर में राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेंगी। इस सेमिनार में क्योंझर में रहने वाले आदिवासियों की संस्कृति और विरासत पर चर्चा की जायेगी और वह छात्रों को संबोधित करेंगी। इसमें जिले के लगभग 150 आदिवासी समुदाय के लोग भाग लेंगे और अपनी पारंपरिक कला, कपड़े, आभूषण आदि का प्रदर्शन करेंगे। इस धरणीधर विश्वविद्यालय के कुल छात्रों में से 28 प्रतिशत छात्र आदिवासी समुदाय से हैं। जब राष्ट्रपति आयेंगी, तो उनका स्वागत आदिवासी लोग अपने पारंपरिक संगीत नृत्य से करेंगे। दोपहर 3:00 बजे से 3:45 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति भुवनेश्वर के लिए रवाना हो जायेंगी।

जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन ने धुबेनछापल गांव में खुले में शौच और कचरा मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया

आजाद सिपाही संवाददाता

भुवनेश्वर। जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन द्वारा संबलपुर के ठेलकोलोई ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले धुबेनछापल गांव के गौंतियापड़ा और पाउलेपड़ा ने गांव के कल्याण के लिए खुले में शौच और कचरा मुक्त कार्यक्रम की गौरव यात्रा निकाली । इसका आयोजन ग्राम निग्रानी समिति, ग्राम जल स्वच्छता समितियां और

फीडबैक फाउंडेशन द्वारा किया गया था । समारोह में जेएसडब्ल्यू बीपीएसएल के सीएसआर प्रमुख, रेंगली ब्लॉक बीडीओ, स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक, ब्लॉक जूनियर जंत्री, ठेलकोलोई ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत विस्तार अधिकारी, वार्ड सदस्य, स्थानीय विद्यालय के शिक्षक, एमबीके सीआरपी, ग्राम जल स्वच्छता समिति, स्वयं सहायता समूह और आम जनता ने भाग लिया।

वेदांता एल्युमीनियम एनजीओ भागीदारी के माध्यम से लगभग 5 लाख लाभार्थियों के जीवन को उज्ज्वल करता है

दो लोगों के लाइफ कवर और तीन पीढ़ियों तक मिलने वाली आय को एक ही उत्पाद में पैक किया गया

आजाद सिपाही संवाददाता

भुवनेश्वर। विश्व एनजीओ दिवस पर भारत के सबसे बड़े एल्युमीनियम उत्पादक वेदांता एल्युमीनियम ने घोषणा की कि गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ साझेदारी में उसके प्रभावशाली आउटरीच प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 5 लाख व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। संचयी रूप से, कंपनी के सामाजिक हस्तक्षेपों ने पिछले वित्तीय वर्ष में 6.3 लाख से अधिक व्यक्तियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। कंपनी सामुदायिक आवश्यकताओं, सरकार की विकासात्मक पहलों और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप सामाजिक-आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए 20 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है।

वेदांता एल्युमीनियम के परिचालन में झारसुगुड़ा में दुनिया के सबसे बड़े एल्युमीनियम स्मेल्टरों में से एक, ओडिशा के लांजीगढ़ में एक विश्व स्तरीय

एल्यूमिना रिफाइनरी, छत्तीसगढ़ के कोरबा में भारत का प्रतिष्ठित एल्युमीनियम उत्पादक बाल्को और बढ़ती खदानें शामिल हैं। साथ मिलकर, वे बहुआयामी ग्रामीण गरीबी को कम करके, उद्यम और रोजगार के अवसर पैदा करके ग्रामीण भारत के कई क्षेत्रों को सामाजिक-आर्थिक मुख्यधारा में ला रहे हैं। कंपनी के सामाजिक कल्याण हस्तक्षेप महिला एवं बाल विकास पर ध्यान देने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और जमीनी स्तर के खेल, कला और संस्कृति तक फैले पांच विषयगत क्षेत्रों पर आधारित हैं।

एनजीओ इस पूरे प्रयास में महत्वपूर्ण हैं, जिसमें ग्रामीण समुदायों में गहरी पैठ, कार्यक्रम विकास विशेषज्ञता और सामाजिक संरचनाओं और रीति-रिवाजों पर अंतर्दृष्टि जैसी ताकतें शामिल हैं। वे वैज्ञानिक आधार पर कार्य करते हैं, वेदांत एल्युमीनियम के सामाजिक समर्थन से लाभान्वित होने वाले समुदायों की जरूरतों का पता लगाने के लिए आवश्यकता आकलन करते हैं, कल्याण पहल के लिए एक प्रोग्रामेटिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं, और कल्याण कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए नियमित प्रभाव आकलन करते हैं। एनजीओ बाद में इन निश्चित निष्कर्षों के आधार पर चल रहे कार्यक्रमों को पुनः अंशांकित या बढ़ाते हैं।

वेदांता एल्युमीनियम के सीइओ जॉन स्लेवेन ने कहा, वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 23 के बीच हमारे सामुदायिक निवेश में 45% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो उन समुदायों के समग्र विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दशार्ता है जिनके भीतर हम काम करते हैं। प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित करके , हम अपने समुदाय के सदस्यों के लिए प्रभावशाली सामाजिक कल्याण पहलों को डिजाइन करने और वितरित करने के लिए अपनी साझा शक्तियों का लाभ उठाते हैं। वेदांत एल्युमीनियम में, हम मानते हैं कि समावेशी विकास समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने से होता है। हमारी एनजीओ भागीदारी परिवर्तनकारी, सतत विकास को उत्प्रेरित करके इस मोर्चे पर काम करती है।

इन पहलों के प्रभाव को साझा करते हुए, डॉ. एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन (एएफपीआरओ) के कार्यकारी निदेशक, जैकब जॉन ने कहा, वेदांत एल्युमीनियम के साथ हमारी साझेदारी के माध्यम से, हम हजारों किसानों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव सुनिश्चित कर रहे हैं और युवा पीढ़ियों के लिए एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में खेती को फिर से स्थापित कर रहे हैं।₹ महाशक्ति फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक, श्री जुगल पटनायक ने कहा, हमने उद्यमिता पहल पर वेदांत एल्युमीनियम के साथ साझेदारी की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने परिवार की भलाई के बारे में सूचित विकल्प चुनने में मदद कर रही है और अपने समुदाय के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है।

रवींद्र कुमार बने एनटीपीसी के निदेशक (संचालन)

आजाद सिपाही संवाददाता

भुवनेश्वर। रवींद्र कुमार ने 26 फरवरी को एनटीपीसी के निदेशक (संचालन) के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने बीएससी के बाद (इंजीनियरिंग) 1988 में बीआइटी सिंदरी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा किया। एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक (संचालन) के रूप में शामिल होने से पहले वह एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक (संचालन) के ओएसडी (विशेष कार्य अधिकारी) थे। श्री कुमार 1989 में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी अधिकारी के रूप में एनटीपीसी लिमिटेड में शामिल हुए और उनके पास कमीशनिंग, ओएंडएम, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट प्रबंधन

में 34 वर्षों से अधिक का विविध और बहुमुखी अनुभव है।

श्री कुमार ने एनटीपीसी कहलगांव परियोजना में ओएंडएम कार्य में विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्हें इंजीनियरिंग विभाग में कॉरपोरेट सेंटर में काम करने और निदेशक (तकनीकी) के लिए तकनीकी सहायता के रूप में काम करने का अनुभव है। वह बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड (बीआइएफपीसीएल), बांग्लादेश की पहली मैत्री सुपरक्रिटिकल बिजली परियोजना के विकास में सक्रिय रूप से शामिल थे। मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बीआइएफपीसीएल की 660 मेगावाट की पहली इकाई की सभी इंजीनियरिंग, कमीशनिंग और ओएंडएम गतिविधियों का नेतृत्व किया। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) के रूप में उन्होंने विभिन्न निर्माण और गतिविधियों में तेजी लायी। वह कॉरपोरेट और साइट अनुभव, जन-केंद्रित दृष्टिकोण, ज्ञान और पूरे बिजली क्षेत्र के अनुभव के साथ एक पेशेवर हैं।

खनन उद्योग का देश के विकास में योगदान

गोंदलपुरा खनन परियोजना के शुरू होने से सरकार को मिलेगा 600 करोड़ का राजस्व

बड़कागांव। झारखंड के पास इतना कोयला है कि यह राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ को कमाई में पीछे छोड़ सकता है। लेकिन यह तभी संभव है, जब यहां कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाये और आवंटित कोल ब्लॉकों में जल्द से जल्द खनन शुरू किया जाये। झारखंड में अगर कोयला के उत्पादन की बात करें, तो वर्ष 2022 में यहां 130.104 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था, जबकि वर्ष 2021 में 123.428 मिलियन टन कोयला निकाला गया था। वर्ष 2019 में कोयले का उत्पादन 134.666 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) और उसकी सहायक कंपनियों ने 2020-21 में 596.22 मीट्रिक टन और वर्ष 2021-22 के दौरान 4.4% की वृद्धि करते हुए 622.63 मीट्रिक टन का उत्पादन किया। 2022-23 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड का कोयला उत्पादन 12.94% की वृद्धि के साथ 703.21 मीट्रिक टन रहा।

एक कोयला खान से पांच से 10 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

कोयला बाहुल क्षेत्र हजारीबाग के बड़कागांव में आवंटित कोल ब्लॉकों में जल्द खनन शुरू होने से राज्य सरकार को राजस्व का अतिरिक्त लाभ होगा, जबकि यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एक कोल ब्लॉक से औसतन पांच से दस हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर मिलता है। जिसमें आसपास खुलने वाली दुकानें, डंपर संचालक और अन्य व्यवसाय आदि शामिल हैं। बड़कागांव में एनटीपीसी, एनएमडीसी, अदाणी और जेएसडब्ल्यू समेत अन्य निजी कंपनियों को भारत सरकार की ओर से कोयला मंत्रालय ने कोयला खान आवंटित किया है। यहां खनन शुरू होने से इलाके की तस्वीर बदलेगी और विकास के नये आयाम दिखेंगे। स्थानीय स्तर पर रोजगार के असीम मौके मिलेंगे और राज्य सरकार को भी राजस्व का बड़ा लाभ होगा। सिर्फ अदाणी इंटरप्राइजेज के गोंदलपुरा खनन परियोजना के शुरू होने से राज्य सरकार को करीब 600 करोड़ रुपये का राजस्व हर साल मिलेगा। इतनी बड़ी रकम का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचना को विकसित करने, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा। कोयला खनन शुरू होने से अवैध कोयले की तस्करी पर भी लगाम लगेगी। एक आंकड़े के मुताबिक, झारखंड से हर रोज करीब 530 ट्रक अवैध कोयला निकलता है। यह सारे कोयले की चोरी बंद पड़ी खदानों या उत्खनन की अधिकारिक रूप से बाट जोह रही खदानों से होती है, जिसमें फॉरेस्ट लैंड भी शामिल है। इससे सरकार को राजस्व की भारी होनी होती है।

कोयले की कहानी:-

लगभग तीन सौ मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपिडित हो गये।जैसे-जैसे वे गहरे होते गये उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गये। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि वह वनस्पति के अवशेषों से बना है अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं।

कोयले के स्रोत

खानों से निकाले जाने वाला यह शक्तिप्रदायक खनिज मुख्यतः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में पाया जाता है। भारत में यह मुख्यतः झारखंड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश/तेलंगाना एवं तमिनाडु में पाया जाता है। जनवरी 2000 में किये गये आकलन के अनुसार भारत की खानों में कुल 211.5 अरब टन कोयले का भंडार है।

पर्यावरण सुरक्षा और आधारिक संरचना का विकास

प्रस्तावित सुधारों के तहत राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण/द्रवीकरण (को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 तक 1 बिलियन टन वार्षिक कोयला उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये केंद्र सरकार द्वारा कोयला खनन से जुड़ी आधारभूत संरचना के विकास हेतु 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस पहल के तहत खदानों से रेलवे लाइनों तक कोयले को आसानी से पहुँचाने के लिये 18,000 करोड़ के निवेश से कन्वेयर बेल्ट प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

देश को बिजली उत्पादन के लिए बाहर से मंगवाना पड़ता है कोयला

गर्मी के समय में झारखंड समेत देश भर में बिजली की खपत बढ़ी है। कोयला कंपनियों पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव है। आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 के लिए एक हजार मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य कोल इंडिया समेत अन्य कंपनियों ने रखा है। हालांकि, भारत सरकार को अभी भी सिर्फ बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए 100 मिलियन टन के आसपास कोयला विदेशों से मंगवाना पड़ रहा है। झारखंड की बात करें तो यहां गर्मी आते ही पावर प्लांटों में कोयले की कमी हो जाती है, जिस कारण लोगों को बिजली की समस्या से परेशान होना पड़ता है। हजारीबाग में तो खासकर बिजली की समस्या विकराल रूप ले लेती है। ऐसे में जल्द खनन शुरू होने से बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और आम लोगों को काफी राहत मिल सकेगी।

यातायात के विकास के लिए पत्थर का कोयला परमावश्यक पदार्थ

आधुनिक युग में उद्योगों तथा यातायात के विकास के लिये पत्थर का कोयला परमावश्यक पदार्थ हैं। लोहे तथा इस्पात उद्योग में ऐसे उत्तम कोयले की आवश्यकता होती है जिससे कोक बनाया जा सके। भारत में साधारण कोयले के भंडार तो प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं, किंतु कोक उत्पादन के लिये उत्तम श्रेणी का कोयला अपेक्षाकृत सीमित है। गोंडवाना कोयला उच्च श्रेणी का होता है। इसमें राख की मात्रा अल्प तथा तापोत्पादक शक्ति अधिक होती है। तृतीय कल्प का कोयला घटिया श्रेणी का होता है। इसमें गंधक की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। भारत में गोंडवाना युग के प्रमुख क्षेत्र झरिया (झारखंड) तथा रानीगंज (बंगाल) में स्थित है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, पेंचघाटी, उमरिया, सोहागपुर, सिगरेनी, कोठा गुदेम आदि उल्लेखनीय हैं। भारत में उत्पादित संपूर्ण कोयले का 70 प्रतिशत केवल झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। तृतीय कल्प के कोयले, लिग्नाइट

और बिटूमिनश आदि के निक्षेप असम, कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडू और गुजरात राज्यों में है। मुख्य गोंडवाना विरक्षा तथा अन्य संबंधित कोयला निक्षेप प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी और उनकी सहायक नदियों की घाटियों के अनुप्रस्थ एक रेखाबद्ध क्रम में वितरित हैं।

डीएमएफटी से हुई है झारखंड को अच्छी आमदनी

देश के चार राज्यों में कोयला उत्पादन का आंकड़ा देखें तो 80 फीसदी कुल कोयला उत्पादन में से छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी करीब 22%, उड़ीसा की 21%, मध्य प्रदेश की 18% और झारखंड की लगड्डाग 17% फीसदी है। डीएमएफटी (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट) की बात करें, तो देश में जितने पैसे इस फंड के तहत विभिन्न राज्यों को मिले हैं, उसमें सर्वाधिक आमदनी वाले शीर्ष तीन राज्यों में से झारखंड ड्डी शामिल है। कोकिंग कोल के उत्पादन में झारखंड शीर्ष पर है। हालांकि, ओवरऑल कोयला उत्पादन में झारखंड चौथे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ पहले, दूसरे स्थान पर ओडिशा और तीसरे स्थान पर मध्यप्रदेश है। झारखंड ने पिछले वर्ष 119.226 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन किया है और चौथे नंबर पर है।

निष्कर्ष: हाल के वर्षों में भारत ने अपनी विनिर्माण और निर्यात क्षमता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु स्थानीय स्तर पर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना एवं इसकी लागत में कमी लाना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान में भारत में विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, कोयला क्षेत्र में अन्य उद्योगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन की भी संभावनाएं हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाना बहुत ही आवश्यक है परंतु वर्तमान में परिस्थिति में देश की कुल ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ कोयला खनन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

आजाद सिपाही की ओर से स्वत्वाधिकारी लैंडस्केप मीडिया प्रा. लि., प्रकाशक एवं मुद्रक हरिनारायण सिंह के लिए 176 कोकर चौक, ओल्ड एचबी रोड, रांची 834001 (झारखंड) से प्रकाशित तथा डीबी प्रिंट सोल्यूशंस (ए यूनिट ऑफ डीबी कार्प लिमिटेड), प्लॉट नं. 535 एवं 1272, ललगुटवा, पुलिस स्टेशन, रातू, रांची से मुद्रित।
संपादक : हरिनारायण सिंह, **स्थानीय संपादक*** : विनोद कुमार,***पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के लिए जिम्मेदार, **राज्य समन्वय संपादक :** अजय शर्मा। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवाइयों एवं दंडित परिवादों के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। फोन : 9264434560, **R.N.I. No.-JHAHIN/2015/65109,** Postal Registration No. **RN/249/2019-21**